खण्ड - 24 | अंक - 2 | फरवरी 2023

रेड स्टार

कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का मंच

भाकपा (माले) रेड स्टार का केन्द्रीय मुखपत्र

संपादकीय

बिहार में चल रही जाति जनगणना के राजनीतिक निहितार्थ

मौलाना आजाद फैलोशिप बंद

जोशीमठ बचाओ

हिंडनबर्ग के पहले भी चुप्पी थी, आज भी है

जाति उन्मूलन आंदोलन को आगे बढ़ाएं , मनुवादी हिंदुत्व का प्रतिरोध करें

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार

रोको, टोको और ठोको को उसकी औकात दिखानी है

पार्टी दस्तावेज
भारतीय क्रांति का रास्ता

WWW.REDSTARONLINE.COM

रेड स्टार

कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का मंच

भाकपा (माले) रेड स्टार का केन्द्रीय मुखपत्र | खण्ड - 24 | अंक - 2 | फरवरी 2023

इस अंक में :-

संपादकीय

03 बिहार में चल रही जाति जनगणना के राजनीतिक निहितार्थ

पार्टी दस्तावेज

05 भारतीय क्रांति का रास्ता

आलेख

26 मौलाना आजाद फैलोशिप बंद: शिक्षा में पहले से ही पिछड़े मुसलमानों के लिए नई मुसीबत

28 जाति उन्मूलन आंदोलन को आगे बढ़ाएं, आरएसएस के वैचारिक आधार मनुवादी हिंदुत्व का प्रतिरोध करें

30 हिंडनबर्ग के पहले भी अडानी समूह में घोटालों के संकेत मिले थे, पर तब भी चुप्पी थी, आज भी है

34 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार

35 छत्तीसगढ़ में संघी फासिस्ट गिरोह की रोको, टोको और ठोको को उसकी औकात दिखानी है

37 जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशनार्थ

39 पार्टी के वक्तव्य

43 रिपोर्ट

संपादक मंडल
विजय कुमार, उर्मिला, तेजराम विद्रोही, सौरा, वशिष्ठ, रितांश

संपादक : तुहिन

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी:
पीजे जेम्स

सी - 141
सैनिक नगर, नई दिल्ली - 110059
फ़ोन: 011-41056622 (ऑफिस), 9582950680
ईमेल: redstarhindi@gmail.com, info@cpiml.in
वेबसाइट: www.cpiml.in, redstaronline.in

बिहार में चल रही जाति जनगणना के राजनीतिक निहितार्थ

जाति आधारित जनगणना का पहला चरण जो बिहार में 7 जनवरी, 2023 को शुरू हुआ था, राज्य में परिवारों की कुल संख्या पर डेटा एकत्र करने के बाद 21 जनवरी को संपन्न हुआ, और दूसरा चरण जिसमें जाति से संबंधित डेटा एकत्र किया जाना है अप्रैल में आयोजित किया जाएगा। जहां मुख्य रूप से मंडल युग के बाद की पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले "महागठबंधन" की बिहार सरकार जाति-आधारित जनगणना से राजनीतिक लाभ लेने का बेसब्री से इंतजार कर रही है, वहीं भाजपा इससे होने वाले संभावित नुकसान से बचने की कोशिश कर रही है। उसी के हिस्से के रूप में, हालांकि आरएसएस/बीजेपी ने प्रशासनिक कठिनाइयों का हवाला देते हुए जाति-जनगणना प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन इस मामले में हस्तक्षेप करने की अदालत की अनिच्छा ने भगवा ताकतों की चिंताओं को बढ़ा दिया है।

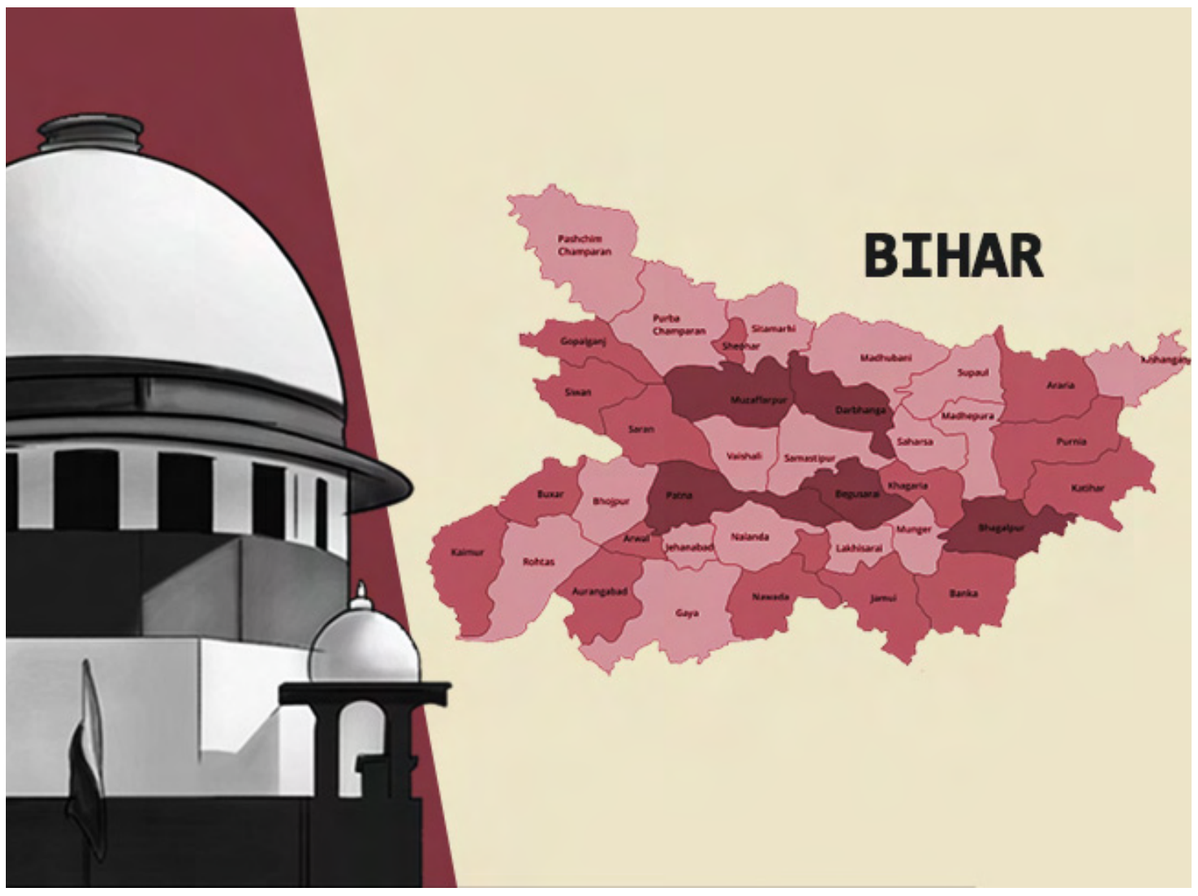

Credits: LiveLaw

भारत में होने वाली एकमात्र जाति आधारित जनगणना 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी जब जाति से संबंधित उपलब्ध जानकारी को आधिकारिक रूप से संहिताबद्ध किया जा सका था। उसके बाद, हालांकि जातिगत जनगणना की मांग विभिन्न हलकों से होती रही है, उच्च जाति के राजनीतिक नेता और नौकरशाही, जिन्होंने देश के धन और सरकारी नौकरियों पर एकाधिकार कर लिया है, वर्षों से इस तरह के कदम को लगातार बाधित कर रहे थे। निचली जाति के नेताओं को खुश करने और उनका समर्थन सुनिश्चित करने के लिए, हालांकि 2018 में भाजपा शासन ने 2021 की जनगणना में जाति को श्रेणी के रूप में शामिल करने की घोषणा की, लेकिन यह बिना कोई स्पष्टीकरण दिए चतुराई से उस स्थिति से पीछे हट गई।

जाहिर है, जिस तात्कालिक संदर्भ ने मंडल समर्थक दलों और ओबीसी नेताओं को बिहार में जातिगत जनगणना के लिए प्रेरित किया, वह मोदी सरकार का पूर्ण रूप से उच्च जाति-उन्मुख 10 प्रतिशत आर्थिक आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बहुमत के फैसले के आधार पर उसी का समर्थन है।1990 के दशक की शुरुआत में, जब मंडल रिपोर्ट का पालन करते हुए पिछड़ी जाति का आरक्षण अस्तित्व में आया, आरएसएस/बीजेपी ने एक शातिर हिंदुत्व ध्रुवीकरण के माध्यम से इसके खिलाफ 'कमंडल' को खड़ा किया, जिसके कारण भगवा गुंडों द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ-साथ राव सरकार के कार्यकारी आदेश की घोषणा कि सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आर्थिक आरक्षण मिलेगा की घोषणा की गई।इस घोषणा का उस समय माकपा ने भी समर्थन किया था। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय की 9-सदस्यीय संविधान पीठ ने इसे असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया।

बहरहाल, मोदी के दूसरे शासनकाल के माध्यम से , RSS/BJP को न्यायपालिका सहित पूरे शासन पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में तथा फिर से

Credits: Express Illustrations

'असंवैधानिक' आर्थिक आरक्षण पर मुहर लगाने में लगभग तीन दशक लग गए। विडम्बना यह है कि जब भाजपा के नेता सरकारी नौकरियों में ओबीसी की आबादी के अनुपात के अनुसार उनकी उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को समाप्त करने की मांग को लेकर बिहार सरकार पर हमला कर रहे हैं, तो वे उस तरीके की अनदेखी कर रहे हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के फैसले के आधार पर पहले ही इस संवैधानिक जनादेश को तोड़ दिया है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अल्पसंख्यक सवर्णों के हितों की रक्षा करने पर तुला हुआ आरएसएस/बीजेपी जातिगत जनगणना से डरता है क्योंकि यह न केवल संभ्रांत जातियों द्वारा आयोजित धन और शीर्ष नौकरशाही पदों पर उनके वर्चस्व को उजागर करेगा, बल्कि उनके द्वारा प्राप्त आर्थिक,सामाजिक,शैक्षिक विशेषाधिकार को भी सवालों के घेरे में लायेगा। निश्चित रूप से, बिहार राज्य में इसके प्रभाव के साथ-साथ जाति की जनगणना के अखिल भारतीय प्रभाव होंगे। यह कई निचली जातियों को हिंदुत्व की छत्रछाया में एकीकृत करने के चल रहे भगवाकरण के हमले में और अधिक बाधाएँ पैदा करेगा, जिसे 'जातियों का विखंडन' कहा जाता है। इसे दूर करने के लिए, अगर आरएसएस/बीजेपी हिंदुत्व के जवाबी हमले का सहारा लेते हैं, जो 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में मंडल-कमंडल संघर्ष की याद दिलाता है, तो आने वाले दिनों में यह एक अशांत राजनीतिक स्थिति पैदा कर सकता है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, भारतीय जाति व्यवस्था के अंतर्निहित अंतर्विरोधों के कारण, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण का समर्थन सुनिश्चित करने में आरएसएस/बीजेपी का अति-उत्साह अल्पकालिक प्रतीत होता है, क्योंकि इसने मंडल दलों को गहनता से राजनीतिक औचित्य प्रदान करने वाला भानुमती का पिटारा खोल दिया है।और वो है उनका समर्थन पाने की कोशिश में जातिगत जनगणना की उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार कर लेना ।

इस संदर्भ में, जाति आधारित भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जातिगत जनगणना के राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, और आज की ठोस हिंदुत्ववादी फासीवादी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भाकपा (माले) रेड स्टार चल रही बिहार जाति जनगणना का समर्थन करती है। हालांकि आज जाति आधारित जनगणना के नतीजे की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन आज के कॉर्पोरेट-भगवा फासीवाद को चुनौती देने के अपने तत्कालिक कार्य को पूरा करने में लोकतांत्रिक ताकतों के लिए एक विश्वसनीय और आधिकारिक जाति डेटा मददगार होगा।

भारतीय क्रांति का रास्ता

(भाकपा (माले) रेड स्टार की 12 वीं कांग्रेस द्वारा अपनाया गया)

1 परिचय
2. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति
3. हमारी क्रांति के कार्य
4. हमारा देश
5. भारतीय समाज का वर्ग विश्लेषण
6. भारतीय सर्वहारा वर्ग के हिरावल के रूप में पार्टी का निर्माण
7. श्रमिक वर्ग को पीडीआर के नेता के रूप में संगठित करना
8. कृषि प्रश्न, कृषि कार्यक्रम और क्रांतिकारी किसान आंदोलन
9. जाति प्रश्न
10. अल्पसंख्यक प्रश्न
11. पारिस्थितिकी और प्रकृति का प्रश्न
12. महिलाओं को मुक्ति के लिए गोलबंद करना
13. सांस्कृतिक मोर्चे में कार्य
14. छात्रों और युवाओं को क्रांति के लिए गोलबंद करना
15. फासीवाद का मुकाबला
16. राष्ट्रीयता प्रश्न
17. संघर्ष के संसदीय रूपों का उपयोग
18. रणनीतिक और रणकौशलीय संयुक्त मोर्चा
19. भारतीय क्रांति का रास्ता
20. निष्कर्ष

1. परिचय

1.1 भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन में जब-जब क्रांति के रास्ते पर चर्चा को उठाया गया, तब शुरुआत से ही उसमें कॉपी-पेस्ट की पद्धति हावी रही। काफी लंबे समय तक तथाकथित रूसी रास्ते और चीनी रास्ते के बीच बहस प्रमुख रही। हालाँकि यह समझ कि, हमारे देश की ठोस वास्तविकता के आधार पर क्रांति के रास्ते को समझा जाना चाहिए, भी साथ-साथ मौजूद थी। हम आज के परिप्रेक्ष्य में इस अवधारणा को ऊंचा उठाते हुये इसे और विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं ।

1.2 दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियों के सामने अब तक के अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय अनुभव का मूल्यांकन करने और वर्तमान की ठोस परिस्थितियों के ठोस विश्लेषण के आधार पर अपनी क्रांति का मार्ग विकसित करने का काम है। उन्हें हठधर्मिता और अवसरवाद कि सभी परतों को उतार फेंकने का साहस करना चाहिए, और ऐतिहासिक और द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हुये, मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्से तुंग विचार और सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयता पर आधारित सैद्धांतिक दिशा और प्रथाओं का विकास करना चाहिए।

2. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति

2.1 वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति दुनिया भर में बढ़ती नव-फासीवादी ताकतों और विकसित होते जन आंदोलनों के बीच बढ़ते अंतर्विरोध से परिलक्षित होती है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रम्प की भारी हार आक्रामक ब्लैक लाइव्स मैटर (बीएलएम) आंदोलन के परिणामस्वरूप दिखाई पड़ी, जो कि कोरोना महामारी के कारण लागू पहले चरण के लॉकडाउन के बीच देश के दो सौ से अधिक शहरों में हुआ था। यूरोप के कई देशों में फासीवादी सत्ताधारी सरकारों द्वारा लगाए गए जनविरोधी प्रतिबंधों के खिलाफ इसी तरह के आन्दोलन देखे जा सकते हैं। लैटिन अमेरिका में, हाल ही में ऐसे देशों का एक समूह उभरा है जहां फासीवाद समर्थक राजनीतिक दलों को हराकर जन-समर्थक ताकतें सत्ता में आई हैं। मुख्य रूप से, यदि फ़ासीवादी ताकतों का संघटन वर्तमान युग की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, तो नए सिरे से जन आंदोलनों का उदय एक और महत्वपूर्ण घटना है।

2.2 वित्तीय पूंजी पोर्टफोलियो के अभूतपूर्व विकास के साथ जुड़ा उत्पादन का अंतर्राष्ट्रीयकरण आज वैश्विक एकाधिकार पूंजी और नवउदारवादी साम्राज्यवाद के शासन में वास्तविक अर्थव्यवस्था से लगभग अलग हो गया है। हालाँकि साम्राज्यवादी ताकतों के बीच द्वंद विकसित हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर साम्राज्यवादियों के बीच श्रम और बढ़ते जन आंदोलनों के खिलाफ सहयोग और मिलीभगत देखी जा रही है। इस लिहाज से कम्युनिस्ट और जनपक्षधर ताकतों के बीच अंतरराष्ट्रीय समन्वय बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

2.3. भारत के नव-फासीवादीकरण की शुरुआत 2014 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की जीत के साथ हुई थी। तब से, किसानों, मजदूर वर्ग, महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों सहित जनता पर हमले कई गुना बढ़ गए हैं। तत्कालीन कल्याणकारी राज्य की सभी विशेषताएं नष्ट होती जा रहीं हैं। बुर्जुआ जनवादी राज्य की सभी संस्थाओं को खत्म करने या उसपर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। भारत को एक "हिंदू राष्ट्र" बनाने का आह्वान न केवल पुनर्जीवित किया गया है बल्कि बड़े उत्साह के साथ लागू किया जा रहा है। भारत के विशेष संदर्भ में, "हिंदू राष्ट्र " का अर्थ फासीवादी भारत है।

2.4. अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के साथ समानता रखते हुए, कई क्षेत्रों में फासीवाद विरोधी जन आंदोलन विकसित हो रहे हैं। दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र और देश के कई अन्य हिस्सों में एक मजबूत एनआरसी विरोधी आंदोलन विकसित हुआ, जिसके बाद भारत में सबसे महत्वपूर्ण और शानदार आंदोलन किसान आंदोलन रहा जिसने नरेंद्र मोदी सरकार को पीछे हटने और तीन बर्बर कृषि क़ानूनों को रद्द करने के लिए मजबूर किया। बहुराष्ट्रीय निगमों और उनके राजनीतिक प्रतिनिधियों के खिलाफ खेतिहर किसानों और कृषकों के बड़े वर्गों के बीच अभूतपूर्व एकता हाल के भारत में एक बड़ी घटना है।

2.5 देश में एकताबद्ध क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के अभाव में वर्ग संघर्ष वांछित दिशा में नहीं पनप सका।

मजदूर वर्ग को एक वर्ग के रूप में विकसित करने के लिए उसका राजनीतिकरण और देश में अन्य महत्वपूर्ण संघर्षों के साथ-साथ क्रांतिकारी किसान आंदोलनों का निर्माण इस बात पर निर्भर करता है कि पार्टी कितनी जल्दी बनाई जा सकती है ।

3. हमारी क्रांति के कार्य

3.1 हमारी क्रांति के चरित्र और मार्ग का वर्णन करते हुए, पार्टी कार्यक्रम कहता है कि, "मुख्य अंतर्विरोध का समाधान अन्य विरोधी अंतर्विरोधों के समाधान के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। नव-फासीवादी संदर्भ में, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में फासीवाद-विरोधी जन मोर्चा, जिसमें मजदूर वर्ग, किसान, और सभी शोषित और उत्पीड़ित शामिल हैं, को राजनीतिक सत्ता हथियाने की दिशा में आगे बढ़ते हुये शासक वर्गों के विभिन्न वर्गों के बीच अंतर्विरोधों का चतुराई से उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। इसका अर्थ है मजदूर वर्ग के देशव्यापी संघर्षों को क्रांतिकारी कृषि संघर्षों के साथ जोड़ना, और संघर्ष के अन्य सभी रूपों को इसके साथ जोड़ना।" (4.13)

3.2. आगे कहा गया है कि हमारी क्रांति विश्व सर्वहारा क्रांति का एक अविभाज्य अंग है। इसलिए, हमारी क्रांति का नेता महान मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्से तुंग विचार द्वारा संगठित और सशक्त श्रमिक वर्ग है। राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने के बाद मजदूर वर्ग और उसकी पार्टी पीडीआर/एनडीआर की सीमा को पार करते हुए समाजवादी क्रांति और समाजवादी निर्माण की दिशा में क्रांति का नेतृत्व करती है। इसलिए, हमारे लिए क्रांति का अर्थ केवल सत्ता पर कब्जा नहीं है, बल्कि सत्ता पर कब्जे की तैयारी से लेकर समाजवादी निर्माण के पूरा होने तक का पूरा रास्ता है। हालाँकि, हमारा वर्तमान क्रांति का रास्ता दस्तावेज़ केवल सत्ता पर काबिज होने तक, क्रांति के मार्ग के बारे में सामान्य रूपरेखा पर चर्चा करने तक ही सीमित है।

3.3 हमारे पार्टी कार्यक्रम ने आगे बताया है कि शुरू से ही जाति संघर्ष और लैंगिक संघर्ष भारतीय वर्ग संघर्ष के दो अभिन्न पहलुओं के रूप में विकसित होते रहे हैं। इसलिए, हमारी क्रांति का कार्य मजदूर वर्ग के नेतृत्व में मजदूर वर्ग, किसानों और अन्य क्रांतिकारी वर्गों की एकता विकसित करना और शासक वर्ग के हाथों से राजनीतिक सत्ता छीनने के लिए वर्ग संघर्षों को जाति संघर्षों और लिंग संघर्षों के साथ जोड़ना है और समाजवादी निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना है। शासक वर्गों से राजनीतिक सत्ता छीनने और मनुवादी , पितृसत्तात्मक राज्य और साम्राज्यवाद और कॉर्पोरेट पूंजी के जूएँ को उखाड़ फेंकने के साथ ही जनवादी क्रांति के कार्यों को पूरा किया जाएगा और क्रांति तत्काल ही समाजवादी चरित्र ग्रहण कर लेगी।

4. हमारा देश

4.1. हमारे देश, जहां हम क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं, का वर्णन करते हुए हमारा पार्टी कार्यक्रम कहता है: "हमारा देश भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है जहां लगभग 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। यह एक बहुराष्ट्रीय, बहु-जातीय, बहुभाषी और बहु-धार्मिक देश है जो विशाल विविधताओं और जटिलताओं के साथ गहराई तक स्थापित पदानुक्रमित जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है।" (3.1)

4.2. दुनिया के कई अन्य देशों के विपरीत, हमारे देश के विशाल क्षेत्र न केवल भौगोलिक रूप से विविध हैं बल्कि लोगों के विभिन्न समूहों के भी इतिहास, संस्कृति और जातीय संरचना के अलग-अलग स्रोत और अलग-अलग निरंतरताएं हैं। जब लगभग पूरे उत्तर भारत में वैदिक संस्कृति का बोलबाला था, तब मुख्य रूप से दक्षिण और पूर्व में अवैदिक संस्कृति का बोलबाला था। जब दक्षिण भारत में द्रविड़ वंश का वर्चस्व होता है, तो वहीं देश के अन्य हिस्सों में तुर्क -ईरानी, इंडो-आर्यन, सिथो-द्रविड़ या मंगोलॉयड वंश का प्रभुत्व होता है। आर्थिक और अन्य सामाजिक प्रक्रियाएं जो वर्गों की उत्पत्ति, वर्ग संघर्षों और उनके प्रक्षेपवक्र के लिए जिम्मेदार थीं, वे भी भिन्न हैं।

4.3. चूंकि मजदूर वर्ग हमारे समाज का सबसे आधुनिक वर्ग है, इसलिए मजदूर वर्ग और उसकी हिरावल पार्टी ही भारतीय जनता के संघर्षों के इतिहास से समानता निकालने और अलग-अलग उत्पीड़ित जनता के बीच एकता बनाने में सक्षम हैं ताकि क्रांति का नेतृत्व करें जो एक राष्ट्रीय चरित्र प्राप्त कर सके। मजदूर वर्ग और केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही अलग-अलग कूटनीतिक तरीकों का प्रयोग करने में सक्षम हैं जो उनके संबंधित राजनीतिक-मनोवैज्ञानिक और भौगोलिक वातावरण में उपयुक्त हैं।

5. भारतीय समाज का वर्ग विश्लेषण

5.1 पीडीआर के वर्ग दृष्टिकोण पर, पार्टी कार्यक्रम कहता है: (4.11). " भारतीय मजदूर वर्ग का राजनीतिकरण और गोलबंद करना और उसे क्रांति के नेता के रूप में बदलना राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने की दिशा में कम्युनिस्ट पार्टी का प्राथमिक कार्य है। यह मध्यम वर्ग और राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग के साथ एकजुट होने वाले मजदूर-किसान गठबंधन के आधार पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के निर्माण के साथ शुरू होता है, जो एक ढुलमुल सहयोगी मात्र है।"

5.2 भारत एक ऐसा देश है जहां वर्ण-जाति विभाजन के साथ वर्ग विभाजन शुरू हुआ और भारतीय मेहनतकश जनता का बड़ा हिस्सा दलितों का है जो तथाकथित पिछड़ी जातियों से संबंधित हैं। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन कभी भी भारतीय वास्तविकता की इस अनूठी विशेषता का मूल्यांकन नहीं कर सका जिसने उन्हें वर्ग संघर्ष और जाति संघर्ष की पारस्परिक प्रकृति को समझने से रोका। इस समझ की कमी ने देश की मेहनतकश जनता को एकजुट करने में बाधा उत्पन्न की, जिसके कारण मजदूर वर्ग का नेतृत्व स्थापित करने में, कृषि क्रांति के माध्यम से किसानों को लामबंद करने में, मजदूर-किसान गठजोड़ बनाने में, और इस तरह वास्तविक दुश्मनों पर हमला करने के लिए असली मित्रों के साथ एकजुटता कायम करने में विफलता हासिल हुई।

5.3 दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग शासक वर्गों में अग्रणी वर्ग है। जबकि बड़े भारतीय पूंजीपतियों और नौकरशाही वर्ग के साम्राज्यवाद के साथ अंतर्विरोध हैं, जो अक्सर उनके लाभ के लिए अंतर-साम्राज्यवादी अंतर्विरोधों का उपयोग करने के उनके पैंतरेबाज़ी में परिलक्षित होता है, साम्राज्यवाद के साथ उनका सहयोग बुनियादी है जैसा कि नवउदारवादी नीतियों के साथ उनके सहयोग से परिलक्षित होता है। उनका दूसरे देशों में भारी निवेश करना, या इन कॉरपोरेट घरानों के कुछ प्रमुखों को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में जगह पाना, इस बुनियादी तथ्य को नहीं बदलता है कि वे साम्राज्यवाद के साथ सहयोग करना जारी रखे हुए हैं और देश में उत्पादक शक्तियों के स्वतंत्र विकास को बाधित कर रहे हैं। तो चाहे उसे साम्राज्यवाद का कनिष्ठ साथी कहें या आश्रित बुर्जुआ वर्ग, उसका मूल चरित्र एक ही रहता है- वह मुख्य रूप से साम्राज्यवादी हितों की सेवा करने वाला दलाल वर्ग है, जो सौदेबाजी में बड़ा लाभ उठाता है।

5.4 इसके विपरीत, उन सभी ताकतों द्वारा लिया गया पक्ष, जो इसे एक स्वतंत्र पूंजीवादी वर्ग मानता है और भारत को एक स्वतंत्र पूंजीवादी देश के रूप में परिभाषित करता है (जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ साम्राज्यवाद के इस युग में एक और साम्राज्यवादी देश है) और क्रांति के चरण को समाजवादी के रूप में परिभाषित करता है, विशेष रूप से वैश्वीकरण और 'नव-उदारवादी' नीतियों के लागू होने के बाद, वर्तमान वास्तविकता के साथ असंगत साबित हुआ है। जबकि कृषि और अन्य सभी क्षेत्रों में उत्पादन के संबंधों के बढ़ते पूंजीवादी बदलाव के लिए तीव्र होता नव-उपनिवेशीकरण एक तथ्य है जिसे जानना चाहिए, यह साम्राज्यवादी एजेंसियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वर्चस्व के तहत हो रहा है, यहां तक कि मोनसेंटो जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बीज उत्पादन को भी नियंत्रित किया जाता है। जनवादी क्रांति के दो कार्य पूर्व-पूंजीवादी संबंधों को समाप्त करना और साम्राज्यवादी प्रभुत्व को

उखाड़ फेंकना है। नव-औपनिवेशिक वर्चस्व के तहत, अखिल भारतीय स्तर पर कृषि में पूंजीवादी संबंधों के विकास की प्रवृत्ति बढ़ रही है, हालांकि काफी हद तक विविधताएं और असमानताएं हैं। भारतीय क्रांति का काम साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाही पूंजीवाद और जमींदारी प्रथा को उखाड़ फेंकना है। ये कार्य परस्पर संबंधित हैं। इसीलिए, कृषि में तीव्र और गहरी पूँजीवादी पैठ के बावजूद, क्रांति का चरण अभी भी जनवादी है, समाजवादी नहीं।

5.5 बड़े नौकरशाही-बुर्जुआ जमींदार वर्ग, कृषि कॉर्पोरेट, कृषि पूंजीपति वर्ग और भू-माफियाओं के विभिन्न वर्ग ग्रामीण इलाकों में एक घातक ताकत हैं। यह साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था के साथ कृषि क्षेत्र को एकीकृत कर रहा है, बीज के उत्पादन से लेकर उपज की खरीद और उनके विपणन तक कृषि के हर क्षेत्र में साम्राज्यवादी पूंजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश को सुगम बना रहा है, और नव-औपनिवेशिक लूट को कायम रखने के लिए दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग के साथ गठबंधन कर रहा है।

5.6 राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग भारतीय क्रांति का एक डगमगाने वाला सहयोगी है। अपने वजूद को बनाए रखने के लिए वे दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग के साथ अधिक से अधिक जुड़े रहना चाहते हैं, और खासकर नव-उदारवादी नीतियों को लागू करने के बाद पहले से कहीं अधिक साम्राज्यवाद के साथ सहयोग करना चाहते हैं। इन सबके बावजूद साम्राज्यवाद के साथ उनके अंतर्विरोध हर क्षेत्र में एकाधिकार की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ बढ़ते जा रहे हैं। मजदूर वर्ग और किसान वर्ग के संघर्षों के विकास के साथ, राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होने की संभावना बढ़ जाएगी।

5.7 अपने आकार और वर्गीय चरित्र के कारण निम्न बुर्जुआ वर्ग, जिसमें मध्यम किसान भी शामिल हैं, एक महत्वपूर्ण वर्ग है, जिसमें क्रांति का भरोसेमंद सहयोगी होने की संभावना है। निम्न मध्यम वर्ग जो इसका आधे से अधिक हिस्सा है, जिसे इसका वामपंथी कहा जा सकता है, वैश्वीकरण-उदारीकरण-निजीकरण शासन के तहत लगातार तीव्र दुख का सामना कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप इसका बड़ा हिस्सा श्रमिकों के स्तर तक गिर गया है, जो अपनी पूरी संपत्ति खो चुके हैं।

5.8 भूमिहीन, गरीब और मध्यम किसान और खेतिहर मजदूर, जमीन को वास्तव में जोतने वाले, आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। इनमें आदिवासी, दलित और समाज के सबसे पिछड़े और उत्पीड़ित वर्ग शामिल हैं। नवउदारवादी नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र के वर्गीय ढांचे में भारी परिवर्तन आया है। वर्ग विभेदीकरण के ये नए रूप हमें अधिक गहन अध्ययन करने के लिए बाध्य करते हैं और इससे निकाले गए निष्कर्षों का उपयोग क्रांतिकारी आक्रमण के लिए अधिक ठोस/यथार्थवादी नारों के साथ किया जा सकता है।

5.9 भारत एक विशाल श्रमिक वर्ग वाला देश है, जिसके क्रांति के नेता के रूप में लामबंदी और राजनीतिकरण के बिना, पीडीआर को पूरा करना और समाजवादी क्रांति की ओर बढ़ना असंभव है। पूर्व-क्रांतिकारी चीन को छोड़ दें, तो भारत में मजदूर वर्ग पूर्व-क्रांतिकारी रूस या किसी भी अन्य देश में जहां क्रांति हुई है, की तुलना में कई गुना अधिक है। इसलिए यहाँ मजदूर वर्ग का आन्दोलन कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उदारीकरण-निजीकरण राज के तहत असंगठित क्षेत्र में कामगार वर्ग की आबादी ठेका मजदूरी, काम कराओ बाहर निकालो प्रणाली के चलते बहुत बढ़ गई है। यहाँ तक कि आधुनिक औद्योगिक सर्वहारा वर्ग भी उत्तरोत्तर इस श्रेणी में आता जा रहा है। तालाबंदी, आधुनिकीकरण, आउटसोर्सिंग, वीआरएस आदि के माध्यम से संगठित क्षेत्र में कामगारों और कर्मचारियों की संख्या तेजी से कम हुई है। काम के नियमित घंटों में वृद्धि, वेतन में कटौती, सेवा की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि से संगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। यद्यपि संगठित क्षेत्र के तुलनात्मक रूप से बेहतर वेतन पाने वाले श्रमिक आज

अधिकांश ट्रेड यूनियन केंद्रों की मुख्य शक्ति हैं, असंगठित श्रमिकों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जो श्रमिकों का 98% हिस्सा हैं। हमारा कार्य स्थानीय, राज्यव्यापी और देशव्यापी संघर्षों के लिए उन्हें जुटाना और नेतृत्व करना है, और मजदूर वर्ग के संघर्षों और विद्रोहों के लिए अनुकूल माहौल बनाना है।

6. भारतीय सर्वहारा वर्ग के हिरावल के रूप में पार्टी का निर्माण

6.1 क्रान्तिकारी पार्टी के बिना कोई भी क्रान्तिकारी आन्दोलन सम्भव नहीं है। हालाँकि, हमारे देश में अभी भी कोई भी एकजुट क्रांतिकारी पार्टी मौजूद नहीं है, क्योंकि 1970 के दशक की शुरुआत में कम्युनिस्ट आंदोलन कई समूहों और पार्टियों में बिखर गया था। रूस, चीन और अन्य देशों में हुई क्रांतियों की स्थिति की तुलना में भारत में ठोस स्थितियाँ बहुत भिन्न हैं। आज पार्टी का निर्माण तब हो रहा है जब कॉमिन्टर्न के मार्गदर्शन में निर्मित लगभग सभी पार्टियां नौकरशाही संगठनात्मक संरचनाओं के साथ पूंजीवादी रास्ते पर चली गई हैं। लगभग सभी तत्कालीन समाजवादी देश नौकरशाही राज्य पूंजीवाद या पूंजीवादी/साम्राज्यवादी देशों को खोलने के लिए पतित हो गए हैं। पीडीआर अब हो रहा है जब पूरी दुनिया में और हमारे देश में भी फासीवादी प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं।

6.2 हालांकि सीपीआई (एम), सीपीआई जैसी पार्टियां पूरी तरह से दक्षिणपंथी अवसरवादी पदों पर आसीन हो गई हैं और उस प्रक्रिया में काफी कमजोर हो गई हैं, फिर भी वे कम्युनिस्ट बैनर का इस्तेमाल करना जारी रखे हुए हैं और वामपंथी जनता को भ्रमित कर रही हैं। भाकपा (माओवादी) की गतिविधियां भी कम्युनिस्ट आंदोलन की छवि को नष्ट कर रही हैं। सामाजिक जनवादी प्रभाव के तहत, मार्क्सवादी-लेनिनवादी ताकतों का एक वर्ग पहले ही संसदीय अवसरवाद में पतित हो चुका है। दक्षिणपंथी अवसरवादी और अराजकतावादी, हर तरह की प्रवृत्तियों के खिलाफ वैचारिक संघर्ष तेज करना होगा।

6.3 आवश्यकता इस बात की है कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार वर्ग और जनसंगठनों और विभिन्न जन आंदोलनों से घिरी बोल्शेविक-मॉडल पार्टी का निर्माण किया जाए। लाखों श्रमिकों, भूमिहीन-गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों और अन्य क्रांतिकारी वर्गों सहित लगभग 140 करोड़ लोगों के देश में, उन्हें देशव्यापी अभियानों और संघर्षों के लिए सफलतापूर्वक लामबंद किया जा सकता है, यदि बोल्शेविक पार्टी निर्माण के प्रति लेनिनवादी दृष्टिकोण के साथ वर्ग/जनसंगठनों को वर्तमान जरूरतों के अनुसार विकसित कर उनका शब्दशःपालन किया जाता है। बिना जनवादी कार्यक्रम के मोर्चा संगठनों जैसी अवधारणाएँ और जनता की गोलबंदी केवल संकीर्णतावाद की अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं हैं।

6.4 यह देशव्यापी संगठन और राजनीतिक प्रभाव वाली पार्टी होनी चाहिए। 'दीर्घ जनयुद्ध' की लाइन के अंतर्गत 'क्षेत्रवार राजनीतिक ताकत पर कब्जा' और 'आधार क्षेत्र', स्थानीयता का प्रभाव आदि की अवधारणा वर्तमान में 'आत्मसंतुष्ट' अवसरवाद के आवरण के रूप में जनता से अलग रहने के लिए उपयोग की जाती है और गतिविधियों को जारी रखने के लिए प्रभाव के कुछ क्षेत्रों तक सीमित होती है। हाल के दशकों में विशेष रूप से साम्राज्यवाद और देशी शासक वर्गों द्वारा नव-उदारवादी आक्रमण शुरू करने के बाद ठोस स्थिति में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, उसे देखते हुये यह मांग है कि करोड़ों की संख्या में क्रांतिकारी ताकतों द्वारा देशव्यापी आक्रामक तैयार किया जाये। अतः अखिल भारतीय स्तर पर पार्टी निर्माण के लिए राजनीतिक और सांगठनिक पहल की जानी चाहिए ताकि सभी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी ताकतों को एकजुट किया जा सके।

6.5 जोरदार वैचारिक और राजनीतिक अभियान शुरू करने के लिए, राजनीतिक रूप से प्रगतिशील वर्गों को जीतने और पार्टी निर्माण के लिए आज उपलब्ध संभावनाओं का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। नवउदारवादी नीतियों के दुष्परिणामों, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर बढ़ते हमलों, प्रस्तावित परमाणु संयंत्रों,

विकास' परियोजनाओं के लिए विस्थापन आदि के खिलाफ विभिन्न क्षेत्रों में स्वतःस्फूर्त संघर्षों के खड़े होने के पहले से ही कई उदाहरण मौजूद हैं। सीएए विरोधी आंदोलन, और एक साल के लिए दिल्ली की सीमाओं को लाचार बनाने वाले ऐतिहासिक किसान आंदोलन के बाद देशव्यापी जनउभार के उठ खड़े होने कि संभावनाओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। पार्टी को आने वाली उथल-पुथल का नेतृत्व करने में सक्षम होना चाहिए और इसी परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक और सांगठनिक कार्य किए जाने चाहिए। साथ ही, मजदूर वर्ग के बीच पार्टी फ्रैक्शनों के निर्माण, राज्य तंत्र सहित संवेदनशील क्षेत्रों में और पुलिस, अर्धसैनिक और सेना के भीतर फ्रैक्शनों को संगठित करने को महत्व दिया जाना चाहिए।

6.6 पार्टी को राजनीतिक रूप से सशक्त और संगठनात्मक रूप से सक्रिय रखने वाली वैचारिक-राजनीतिक शिक्षा और प्रशिक्षण को प्रमुखता दी जानी चाहिए। मार्क्सवाद कोई हठधर्मिता नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक है, जिसे अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ठोस परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों से निपटने के लिए निरंतर विकसित किया जाना चाहिए। पार्टी को इस चुनौती को लेने में सक्षम होना चाहिए और पूरे संगठन को सचेत और लगातार सैद्धांतिक हमले के लिए तैयार करना चाहिए।

6.7 जनवादी केंद्रीयवाद को व्यवस्थित रूप से अमल में लाना चाहिए ताकि पार्टी के भीतर संघर्ष के लिए जनवादी माहौल हमेशा मौजूद रहे। व्यक्तिगत सत्ता और नौकरशाही प्रथाओं की अवांछनीयता के बारे में बात करना आसान है। लेकिन आईसीएम द्वारा झेले गए गंभीर झटकों के बाद भी, उनसे कोई उचित सबक नहीं लिया गया जिससे उपरोक्त नकारात्मक कारकों का मुकाबला किया जा सके और पार्टी और वर्ग/जन संगठनों के भीतर एक जीवंत जनवादी माहौल बना रहे। कमेटी सिस्टम और सामूहिक कामकाज को व्यक्तिगत सत्ता से बदलना, और नौकरशाही तरीकों के साथ जनवादी कामकाज पार्टी में पेटी-बुर्जुआ प्रभाव हैं। इसी तरह, मार्क्सवादी-लेनिनवादी लाइन को कायम रखने का दावा करने वाले न जाने कितने समूहों का वजूद बना हुआ है, जबकि कई मामलों में उनकी लाइनों में कोई बुनियादी अंतर नहीं है और 'कई केंद्रों का सिद्धांत' आदि विजातीय, पेटी-बुर्जुआ प्रवृत्तियाँ हैं, जिनका डटकर मुकाबला किया जाना चाहिए।

7. श्रमिक वर्ग को पीडीआर के नेता के रूप में संगठित करना

7.1 मार्क्सवाद सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी विचारधारा है, जो उत्पादन के सबसे विकसित, उन्नत और संगठित क्षेत्रों में लगा हुआ सबसे उन्नत वर्ग है। सर्वहारा वर्ग के हिरावल के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी का काम है कि उसे एक "स्वयं के वर्ग" से "स्वयं के लिए एक वर्ग" में बदला जाये, जो समाज के क्रांतिकारी परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम हो और जो जनता कि जनवादी क्रान्ति को नेतृत्व प्रदान कर सके।

7.2 1991 में साम्राज्यवादी वैश्वीकरण लागू होने के बाद, नव-उदारवादी शासन के तहत मजदूर वर्ग लगातार तीव्र चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक सदी के कटु संघर्षों से प्राप्त लगभग सभी लोकतांत्रिक, वेतन और ट्रेड यूनियन अधिकारों को छीना जा रहा है। ठेका मजदूरी प्रणाली और 'हायर एंड फायर'/काम कराओ बेदखल करो, आज नियम बन गए हैं। जो दृष्टिगोचर है, वह मजदूरी की दासता का चरम रूप है। संगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या तेजी से घट रही है, उनके नेतृत्व में ' श्रम अभिजात्य वर्ग' का प्रभुत्व है। असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मज़दूर, जिनकी संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, सभी लोकतांत्रिक और ट्रेड यूनियन अधिकारों से वंचित हैं। इसके लिए कई बर्बर कानून थोपे गए हैं। यहाँ तक कि आर्थिक माँगों, यूनियन बनाने के अधिकार आदि के लिए संघर्षों को भी अत्यंत कठिन बना दिया गया है। गैर यूनियनिकरण के साथ-साथ अराजनीतिकरण और जाति आधारित, साम्प्रदायिक, पारलौकिक भावनाओं का वर्चस्व कार्यकर्ताओं में बढ़ रहा है। वर्तमान स्थिति को उलटने के लिए पार्टी कमेटियों को तैयार रहना होगा।

7.3 जब बी.एम.एस. और इंटक जैसे प्रमुख ट्रेड यूनियन केंद्रों के नेतृत्व विदेशी निवेश का विरोध नहीं कर रहे हैं और साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के तहत 'विकास' को बढ़ावा देने के नाम पर मजदूर वर्ग और देश के हितों को साम्राज्यवादी हितों के लिए गिरवी रखने में सक्रिय रूप से शामिल हैं, तब एटक और सीटू जैसे टीयू के नेतृत्व के केंद्र साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के खिलाफ पारंपरिक विरोध प्रदर्शन करके संतुष्ट हैं। एनजीओ के नेतृत्व वाली ट्रेड यूनियनें और उनके केंद्र भी हैं। कुछ कम्युनिस्ट क्रांतिकारी केडरों ने श्रम अदालतों में व्यक्तिगत श्रमिकों के मामलों को लड़ने के लिए ट्रेड यूनियन के काम को कम कर दिया है। उनके नेतृत्व में टीयू केंद्र एकता बनाने और मजदूर वर्ग पर बढ़ते हमलों के खिलाफ सक्रिय प्रतिरोध शुरू करने के साथ-साथ राजनीतिक कार्य करने के लिए उनका राजनीतिकरण करने में भी विफल हो रहे हैं। यह ऐसा कार्य नहीं है जिसे टीयू केंद्रों और उनकी समितियों पर छोड़ा जा सकता है। पार्टी को कार्यकर्ताओं के राजनीतिकरण के लिए एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और न केवल पार्टी कैडरों के नेतृत्व वाली यूनियनों के बीच, बल्कि समग्र रूप से ट्रेड यूनियनों में व्यापक फ्रेक्शन कार्य के माध्यम से इसका प्रचार करना चाहिए।

7.4 मजदूर वर्ग का राजनीतिकरण करने का एक महत्वपूर्ण कार्य उसे किसानों के संघर्षों, सभी लोकतांत्रिक आंदोलनों और समाज के उत्पीड़ित वर्गों के संघर्षों के समर्थन में खड़े होने और कार्य करने के लिए संगठित करना है। मजदूर वर्ग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजदूर वर्ग और उत्पीड़ित लोगों के समर्थन में एकजुटता आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

7.5 वर्तमान संदर्भ में जब सीमा पार श्रमिकों का आवागमन आधुनिक पूंजीवाद के महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक है, विदेशी श्रम शक्ति में भारत का भी एक बड़ा वर्ग है। यह बल हमारे मजदूर वर्ग का अभिन्न अंग है। इसलिए उन्हें संगठित करना भी पार्टी के सामने एक महत्वपूर्ण काम है।

8. कृषि प्रश्न, कृषि कार्यक्रम और क्रांतिकारी किसान आंदोलन

8.1 जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, भारत कृषि पर निर्भर 80% लोगों के साथ एक विशाल कृषि प्रधान देश था। ऐतिहासिक तेलंगाना संघर्ष, तेभागा आंदोलन और प्रभुत्वशाली सामंती, अर्ध-सामंती संबंधों के खिलाफ अन्य क्रांतिकारी कृषि आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल रहे थे। कांग्रेस सरकार इन संघर्षों को कुचलने के लिए दोतरफा अभियान चला रही थी: एक ओर उन्होने विनोबा भावे के सुधारवादी भूदान आंदोलन को बढ़ावा दिया, और दूसरी तरफ इन आंदोलनों को कुचलने के लिए क्रूर हमले करना शुरू कर दिया। नीचे से आते दबाव का सामना करते हुये जल्द ही नव-औपनिवेशिक वर्चस्व के तहत, और अमेरिकी साम्राज्यवादी विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर, भूमि सुधार शुरू किया गया, जिसमें सामंती जमींदारों की नई पीढ़ी के जमींदारों के साथ प्रतिस्थापन की शुरुआत हुई, जो साम्राज्यवादी नेतृत्व में हरित क्रांति को गले लगाने के लिए तैयार थे। कृषि क्षेत्र में उर्वरकों, रसायनों, नए बीजों और अन्य निवेशों के साथ-साथ पूँजी के प्रवेश के लिए परिस्थितियाँ निर्मित की गईं। उपनिवेशवाद के तहत साम्राज्यवाद ने सामंतवाद को अपने सामाजिक आधार के रूप में इस्तेमाल किया था। लेकिन नव-औपनिवेशिक वर्चस्व के तहत कृषि क्षेत्र में पूंजीवादी संबंधों को बढ़ावा दिया गया जिससे पूंजीवादी जमींदारों का एक नया वर्ग पैदा हुआ। इस तरह साम्राज्यवाद ने पूरे कृषि क्षेत्र पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया।

8.2 शुरू किए गए भूमि सुधार नीचे से आए हुये "जमीन जोतने वालों के लिए" के आधार पर क्रांतिकारी भूमि सुधार नहीं थे, बल्कि ऊपर से लागू किए गए थे जिससे बुर्जुआ जमींदारों का एक नया वर्ग तैयार हुआ, जबकि आदिवासियों , दलितों और अन्य उत्पीड़ित वर्गों सहित वास्तविक किसान भूमिहीन बने रहे या केवल छोटे आवासीय भूखंडों के स्वामी बने रह गए। अधिकांश मामलों में महिलाओं को भूमि के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, हालांकि भूमि का अधिकार भी सभी संबंधित वर्गों के लिए एक लोकतांत्रिक मुद्दा है।

इसका समग्र प्रभाव यह हुआ कि साम्राज्यवादी पूंजी-बाजार प्रणाली में कृषि क्षेत्र का और अधिक एकीकरण हो गया। नव-उदारवादी नीतियों की शुरुआत के साथ, बड़ी परियोजनाओं के लिए गरीब, सीमांत और मध्यम किसानों की बड़ी संख्या को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया, खेतों खलिहानों की संख्या में वृद्धि हुई है, जमींदारों और कॉर्पोरेट ताकतों के पास भूमि संचय में वृद्धि हुई है, बढ़ते कार्पोरेटिकरण के तहत कृषि क्षेत्र को लाया गया है और पूंजीवादी संबंध बहुत तेजी से बढ़े हैं।

8.3 नक्सलबाड़ी संघर्ष का महत्व यह था कि इसने 1950 के दशक की शुरुआत में भाकपा नेतृत्व द्वारा परित्यक्त कृषि-क्रांतिकारी संघर्ष को कम्युनिस्ट एजेंडे में वापस ला दिया। वामपंथी दुस्साहसवादी लाइन के तहत आंदोलन के विघटन के बाद, हालांकि सीपीआई (एमएल) के सेक्शनों द्वारा एक सुधार की पहल कि गयी थी, और भूमि संघर्षों में बिहार और आंध्र प्रदेश में गरीब और भूमिहीन किसानों और कृषि श्रमिकों की महत्वपूर्ण लामबन्दी हुई थी, लेकिन नवउपनिवेशीकरण के तहत कृषि क्षेत्र में हो रहे व्यापक परिवर्तनों का अध्ययन करने या ठोस परिस्थितियों के अनुसार किसानों के नए वर्ग की मांगों को संबोधित करने वाले कृषि संघर्षों को विकसित करने के कोई प्रयास नहीं किए गए।

8.4 कृषि क्रान्ति का अर्थ है जमींदारवाद का सफाया, जिसमें सामंती और पूर्व-पूँजीवादी भूमि संबंधों के अभी भी बचे हुए अवशेष शामिल हैं, और जोतने वाले को जमीन के नारे के आधार पर भूमि संबंधों में क्रांतिकारी परिवर्तन करना, और बागानों और खेतों पर श्रमिकों का सामूहिक स्वामित्व स्थापित करना, और कृषि के सहकारिता और सामाजिक नियंत्रण का विकास करना। पीडीआर/एनडीआर के दौर में समाज की ठोस स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिक्रियावादी वर्गों के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कृषि क्रांति एक बुनियादी कार्य है। जबकि कृषि क्रांति के कार्य अभी भी प्रासंगिक हैं क्योंकि करोड़ों भूमिहीन, गरीब किसान और खेतिहर मजदूर जमीन चाहते हैं, और कुछ क्षेत्रों में सामंती अवशेष अभी भी मौजूद हैं, हरित क्रांति के तहत हुए व्यापक बदलावों से आई नीतियों ने कृषि के निगमीकरण के लिए जारी नव-उदारवादी हमले के संदर्भ में किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए नए अध्ययन की मांग की।

8.5 नक्सलबाड़ी विद्रोह भाकपा और माकपा द्वारा अपनाए गए सुधारवादी रास्ते को चुनौती देते हुये एक बार फिर कृषि क्रांति को एजेंडे में वापस लाने के लिए हुआ। हालांकि 2020-21 के किसान आंदोलन से पता चलता है कि हरित क्रांति के प्रारंभिक वर्षों से ही जैसे-जैसे कृषि क्षेत्र में पूंजीवादी संबंध हावी होते गए हैं, बहुराष्ट्रीय और बड़ी कृषि कंपनियों और उन्हें बढ़ावा देने वाली राज्य की नीतियों के खिलाफ क्रांतिकारी किसान आंदोलन को विकसित करना का मुख्य कार्य बन गया है। लेकिन लंबे समय तक संकीर्णतावादी लाइन के पदचिन्हों के पालन ने इन आंदोलनों के सैद्धांतिक योग की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर दिया, जिसने बदले में इन संघर्षों को उच्च स्तर पर विकसित करने की संभावना को कम कर दिया। वामपंथी आन्दोलन की कमज़ोरी के बावजूद, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे ऐतिहासिक किसान आन्दोलन को जन्म देने वाले क्षेत्रों में नए प्रकार के किसान आन्दोलन को बल मिला। इस प्रकार किसानों का सवाल एक बार फिर नए रूपों में राजनीतिक परिदृश्य में सबसे आगे आ गया है।

8.6 पार्टी के समक्ष कार्य हैं: सबसे पहले, नव-उपनिवेशीकरण के छह दशकों से अधिक के दौरान कृषि क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तनों का अध्ययन करना, जिसे नव-उदारवादी नीतियों ने गति प्रदान की है, और इन पर आधारित एक कृषि कार्यक्रम तैयार करना। दूसरा, किसानों को संगठित करना, खासकर खेतिहर मजदूरों, भूमिहीन और गरीब किसानों को – जो सबसे अधिक उत्पीड़ित तबके हैं। किसान आन्दोलन को राज्य स्तर पर खड़ा करें और अखिल भारतीय स्तर पर उनका समन्वय करें। कृषि क्रान्तिकारी कार्यक्रम के अनुरूप भूमि संघर्ष समितियों का गठन ग्रामीण स्तर से कृषि श्रमिकों और मध्यम, गरीब और भूमिहीन किसानों के संगठन की

पहल से जोतने वाले को जमीन के नारे के साथ संघर्ष की शुरुआत कर बागानों और खेतों पर अधिकार स्थापित करने के लिए आंदोलनों को संगठित किया जाये. ये दोनों कार्य आपस में संबंधित हैं, और इसके लिए उपयुक्त संगठनात्मक व्यवस्था करते हैं। भूमि सुधार अधिनियमों का गहन अध्ययन भी पार्टी के सामने एक महत्वपूर्ण कार्य है।

8.7 कृषि के इनपुट और आउटपुट पर बहुराष्ट्रीय और बड़ी कृषि कंपनियों के बढ़ते नियंत्रण के खिलाफ, एमएसपी कानूनों के लिए, एपीएमसी कानूनों के लिए और इन कानूनों के सख्त कार्यान्वयन के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे जबरन श्रम , सूदखोरी, सांप्रदायिक और जाति और लिंग आधारित उत्पीड़न, अधिक मजदूरी के लिए, बंजार भूमि के वितरण के लिए, वन ठेकेदारों आदि के खिलाफ तत्काल नारों के साथ आवाज उठानी चाहिए और संघर्षों को संगठित करना चाहिए। तत्काल मांगों के लिए अभियान और संघर्ष करते हुए तत्काल और बुनियादी मांगों के बीच समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। इन वर्गों को अपनी तात्कालिक मांगों के साथ-साथ बुनियादी नारों के लिए लड़ने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर संगठित किया जाना चाहिए। इसी तरह, विस्थापन के खिलाफ हो रहे अनेक किसान आंदोलनों के साथ भी उनके संघर्षों में भाग लेकर संबंध विकसित किए जाने चाहिए। पार्टी को साथ-साथ बागान उद्योग से जुड़े बहुआयामी कार्यों को उठाना चाहिए।

9. **जाति प्रश्न**

9.1 इस सामाजिक महामारी के उन्मूलन के लिए सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलनों की अवधि के प्रयासों के बावजूद, नित नवीन रूपों में भारतीय समाज की वर्ण -जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना अभी भी बनी हुई है, जो उत्पीड़ित जातियों के जीवन को दयनीय बना रही है. यह यांत्रिक समझ कि एक बार क्रांति हो जाने के बाद जाति का सवाल कमजोर हो जाएगा और गायब हो जाएगा, तथाकथित वामपंथी ताकतों में अभी भी हावी है। यह कमजोर हो सकता है, लेकिन नए रूपों में और अधिक उग्र रूप में वापस आएगा क्योंकि जाति विभाजन न केवल अधिरचना का मामला है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। जाति आधारित उत्पीड़न से लड़ाई और जाति उन्मूलन के अभियान को एजेंडे का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। जाति उन्मूलन को वर्ग संघर्ष के अभिन्न अंग के रूप में उठाया जाना चाहिए।

9.2 पिछले छह दशकों के दौरान जाति व्यवस्था नए रूपों में मजबूत हुई है। यह शासक वर्ग के हितों की सेवा करने वाली जाति आधारित पार्टियों के माध्यम से और जाति आधारित वोट बैंकों के निर्माण के माध्यम से शासन व्यवस्था में शामिल है। इनके साथ-साथ प्रतिक्रियावादी विचारधाराओं जैसे पहचान की राजनीति और जनजातीयता को साम्राज्यवादी केंद्रों द्वारा जाति, नस्ल, आदिवासी व्यवस्था आदि के आधार पर उत्पीड़न के खिलाफ संघर्षों को अहानिकर रास्तों पर ले जाने के लिए बढ़ावा दिया जाता है, ताकि इन दलित वर्गों को क्रांतिकारी रास्ते से दूर रखा जा सके। जाति व्यवस्था के खिलाफ समझौतावादी संघर्ष विकसित करने में कम्युनिस्ट आंदोलन की अब तक की कमजोरी ने भी साम्राज्यवादियों और शासक वर्गों द्वारा विभिन्न तरीकों से जाति व्यवस्था और आदिवासी उत्पीड़न को संस्थागत बनाने के इन प्रयासों में मदद की। भारत में दलितों को भूमि के स्वामित्व से दूर रखकर, उन्हें जोतने वाले भूमीहीन बनाकर और उच्च जाति के वर्गों के लिए सभी छोटे-मोटे काम करने तक सीमित करके जातिवादी उत्पीड़न को तेज किया गया । इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में वर्तमान ठोस परिस्थितियों के अनुसार, कृषि क्रांति के माध्यम से जाति व्यवस्था की रीढ़ को तोड़ा जा सकता है, जो एक ओर जोतने वालों को जमीन सुनिश्चित करता है, और दूसरी ओर उत्पादन संबंध को बदलने के लिए एक अलग जाति उन्मूलन आंदोलन खडा करता है। दलितों और आदिवासियों तथा अस्पृश्यता, जो अभी भी विभिन्न रूपों में प्रचलित है, सहित अन्य पिछड़े वर्गों पर जाति आधारित उत्पीड़न के विभिन्न रूपों के खिलाफ अभियान चलाया जाना चाहिए। दलितों के खिलाफ सभी जाति आधारित भेदभाव से लड़ते हुए अंतरजातीय विवाह को

बढ़ावा देना चाहिए। सामाजिक रूप से पिछड़े और उत्पीड़ित वर्गों के लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में जाति के आधार पर प्राप्त आरक्षण का बचाव किया जाना चाहिए और इसे कमजोर किए जाने के खिलाफ संघर्ष किया जाना चाहिए।

9.3 इसी परिप्रेक्ष्य में पार्टी ने अन्य प्रगतिशील ताकतों के साथ एक कार्यक्रम के साथ जाति उन्मूलन आंदोलन शुरू करने की पहल की है। पिछले कई वर्षों के दौरान इसे जो उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, वह इसे मजबूती से आगे ले जाने की आवश्यकता को दर्शाता है।

9.4 लेकिन जाति उन्मूलन आंदोलन की समझ और गतिविधियों को संकल्पनात्मक रूप से और व्यावहारिक कार्रवाई के क्षेत्र में मजबूत करने की आवश्यकता है। उसके लिए, भारत में जाति व्यवस्था को अंतर्निहित सामाजिक संरचना की एक अनूठी समझ और विश्लेषण की आवश्यकता है। दलितों के मानवाधिकारों के लिए जाति व्यवस्था को तोडना और सत्ता/संसाधनों के बंटवारे के मुद्दे से गैर प्रजातांत्रिक जाति व्यवस्था के खिलाफ एक व्यापक जन मोर्चा के निर्माण को सीमित करने की संभावना है। यह एक तथ्य है कि जाति व्यवस्था के सबसे बड़े शिकार समाज के सबसे निचले तबके हैं और उनके मुक्ति संघर्षों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालाँकि, यदि जाति व्यवस्था का समग्र रूप से मूल्यांकन नहीं किया जाता है और इसे केवल दलितों की समस्या माना जाता है, तो जाति उन्मूलन आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। पदानुक्रमित असमानता के आधार पर संचालित होने वाली जाति व्यवस्था को उससे ठीक नीचे की जातियों पर विशेषाधिकार की भावना से बनाए रखा जाता है, जबकि सभी जातियाँ भेदभाव की शिकार होती रहती हैं। ब्राह्मण जातियों में भी इस सामाजिक संरचना को निचली और ऊंची जातियों के क्रम में एक दूसरे के साथ भेदभाव करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जाति व्यवस्था के खिलाफ एक जन एकता तभी संभव होगी जब वे सभी लोग जो स्वयं पर थोपे अपमान के साथ जीते हैं और सोचते हैं कि इस तरह उनके पास भी उनसे नीचे आने वालों का तिरस्कार करने का मौका है, एक जाति-विरोधी लोकतांत्रिक एकजुटता के निर्माण में स्वयं शामिल हों।

9.5 जाति व्यवस्था के विशेषाधिकार प्राप्त समुदायों को जाति-विरोधी संघर्ष में न केवल दलितों की मुक्ति की माँग के रूप में बल्कि इस चेतना में भी एकजुट होना चाहिए कि जाति व्यवस्था एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें समान मनुष्य नहीं मानती। दूसरी ओर जाति की आलोचना, जो केवल दलितों के जातिगत उत्पीड़न के ऐतिहासिक अनुभव पर केंद्रित है, में अन्य पिछड़े/सीमांत समूहों के जातीय ऐतिहासिक अनुभव को अदृश्य रखा गया।

9.6 हालांकि दलित एक राजनीतिक शब्द है, लेकिन ऐसी राजनीतिक चेतना सभी निचली जातियों के समुदायों में मौजूद नहीं है। दलित समुदाय भी कई जातियों में बंटा हुआ है। इसीलिए संघ परिवार दलितों के बीच हो रहे जाति-विरोधी सामूहिक कार्य को ध्वस्त करने के लिए सामाजिक संगठनों को इस तरह संचालित करने में सफल हो रहा है। तथ्य यह है कि संघ परिवार दलितों के बीच जातियों को अपने पक्ष में रखने में सक्षम है, यह दर्शाता है कि निचली जातियों के भीतर जाति-विरोधी विचारधारा की और अधिक प्रभावी निरंतरता की आवश्यकता है।

10. मुसलमानों का प्रश्न - अल्पसंख्यक वर्ग

10.1 वर्तमान भारतीय राजनीति के संदर्भ में, यह निर्विवाद तथ्य है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है और हिंदुत्व का प्रमुख दुश्मन घोषित किया जाता है, जो सत्तारूढ़ राज्य के सांस्कृतिक वैचारिक हथियार के रूप में काम करता है, और इसके बाद ईसाई और कम्युनिस्ट आते हैं। भारतीय मुसलमान राज्य द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के निरंतर उत्पीड़न के दौर से गुजर रहे हैं, राज्य उनपर सभी प्रकार की सत्ता के हथियारों का उपयोग कर रहा है और विशेष रूप से हिंदुत्व विचारधारा के बहुमत द्वारा इस उत्पीड़न को वैध बनाकर उन्हें व्यवस्थित रूप से अलग-थलग किया जा रहा है। गाय पर राजनीति, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, सीएए-एनआरसी से लेकर बुलडोजर की राजनीति आदि कुछ उदाहरण हैं। शारीरिक उत्पीडन के अलावा, मुसलमानों को उनके भोजन, पोशाक और विश्वास संबंधी गालियां देकर, पहले से कहीं अधिक गंभीर तरीके

से सांस्कृतिक रूप से भी परेशान किया जाता है, जिससे देश में मुस्लिम आबादी के बीच गहरी असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। देश में मुसलमानों के इस अलगाव के लिए बहुसंख्यक समुदाय के साथ-साथ तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक वर्गों की भी समान रूप से जिम्मेदार है। हमें इस ठोस स्थिति में बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक साम्प्रदायिक ताकतों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

10.2 भारत में साम्प्रदायिकता का इतिहास स्वतंत्रता-पूर्व काल से ही है। नए उभरे हुये बड़े जमींदार वर्ग और विशेष रूप से 1947 के बाद की कांग्रेस सरकारें नरम हिंदुत्व की पैरोकार थीं। बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसे भीषण आक्रमण की जिम्मेदारी से वे मुंह नहीं मोड़ सकते। हालाँकि, आरएसएस के राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की सत्ता के उदय के बाद, इस प्रवृत्ति ने कई गुना अधिक बल प्राप्त किया। मौजूदा मोदी शासन के तहत, हिंदुत्व विचारधारा मुख्यधारा के सभी वर्गों के बीच एक स्वाभाविक सामान्य विवेक के रूप में शासन कर रही है। एक तरफ संविधान और लोकतंत्र को चुनौती देकर और दूसरी तरफ उसे वैध बनाकर शारीरिक उत्पीड़न के साथ मुस्लिम/अल्पसंख्यक विरोधी हमले जारी हैं। यहां हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सांप्रदायिक ताकतों को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में मापने की पारंपरिक स्थिति का फिर से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यहां तक कि जब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों सांप्रदायिक ताकतें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तब भी उनके शक्ति संबंध और सांस्कृतिक आधिपत्य उनके कार्यों के स्तर और गंभीरता को निर्धारित कर रहे हैं। इसका मतलब मजबूत मुस्लिम/अल्पसंख्यक सांप्रदायिक ताकतों को सरल मान लेना नहीं है जो हिंदुत्व सांप्रदायिक ताकतों के लिए विरोधी ताकत के रूप में काम करती हैं, हालांकि, हिंदुत्व ताकतों और मुस्लिम/अल्पसंख्यक सांप्रदायिक ताकतों को समान रूप से वर्गीकृत कर समान मान लेना राजनीतिक राजनीतिक रूप से गलत है। वास्तव में, ऐसा करके, यह अंततः हिंदुत्व ताकतों को खुद ही मदद करता है। हमारी पार्टी को अन्य सभी प्रकार के इस्लामोफोबिक दृष्टिकोणों के साथ-साथ इस तरह के दृष्टिकोण का भी विरोध करने की आवश्यकता है ।

10.2 भारत में साम्प्रदायिकता का इतिहास स्वतंत्रता-पूर्व काल से ही है। नए उभरे हुये बड़े जमींदार वर्ग और विशेष रूप से 1947 के बाद की कांग्रेस सरकारें नरम हिंदुत्व की पैरोकार थीं। बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसे भीषण आक्रमण की जिम्मेदारी से वे मुंह नहीं मोड़ सकते। हालाँकि, आरएसएस के राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की सत्ता के उदय के बाद, इस प्रवृत्ति ने कई गुना अधिक बल प्राप्त किया। मौजूदा मोदी शासन के तहत, हिंदुत्व विचारधारा मुख्यधारा के सभी वर्गों के बीच एक स्वाभाविक सामान्य विवेक के रूप में शासन कर रही है। एक तरफ संविधान और लोकतंत्र को चुनौती देकर और दूसरी तरफ उसे वैध बनाकर शारीरिक उत्पीड़न के साथ मुस्लिम/अल्पसंख्यक विरोधी हमले जारी हैं। यहां हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सांप्रदायिक ताकतों को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में मापने की पारंपरिक स्थिति का फिर से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यहां तक कि जब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों सांप्रदायिक ताकतें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तब भी उनके शक्ति संबंध और सांस्कृतिक आधिपत्य उनके कार्यों के स्तर और गंभीरता को निर्धारित कर रहे हैं। इसका मतलब मजबूत मुस्लिम/अल्पसंख्यक सांप्रदायिक ताकतों को सरल मान लेना नहीं है जो हिंदुत्व सांप्रदायिक ताकतों के लिए विरोधी ताकत के रूप में काम करती हैं, हालांकि, हिंदुत्व ताकतों और मुस्लिम/अल्पसंख्यक सांप्रदायिक ताकतों को समान रूप से वर्गीकृत कर समान मान लेना राजनीतिक राजनीतिक रूप से गलत है। वास्तव में, ऐसा करके, यह अंततः हिंदुत्व ताकतों को खुद ही मदद करता है। हमारी पार्टी को अन्य सभी प्रकार के इस्लामोफोबिक दृष्टिकोणों के साथ-साथ इस तरह के दृष्टिकोण का भी विरोध करने की आवश्यकता है ।

11.2 पारिस्थितिक विनाश और परिणामस्वरूप बढ़ रहे 'ग्लोबल वार्मिंग' कई आपदाओं का कारण बन रहा है जैसे कि 2013 में उत्तराखंड में परिलक्षित हुआ था और इसी तरह की आपदाएं कई अन्य क्षेत्रों में भी देखी गई थीं। विनाशकारी नव-उदारवादी विकास योजनाओं के लिए पारिस्थितिक रूप से नाजुक हिमालयी श्रृंखलाओं

को लगातार खोदने का चलन भारत, नेपाल और भूटान के विशाल हिमालयी और तराई क्षेत्रों और बांग्लादेश के लिए पानी की उपलब्धता को खतरे में डाल रहा है।

इसी तरह दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्षेत्र भी कॉर्पोरेट, खनन माफियाओं, रियल एस्टेट धन्ना सेठों आदि द्वारा पारिस्थितिकी विनाश का सामना कर रहे हैं। पार्टी ने हिमालयी, तराई क्षेत्रों के अध्ययन के साथ-साथ पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन में सक्रिय रूप से काम करने की पहल की है। . इसी प्रकार राज्य स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण के संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए अध्ययन किया जाता है। हाल के दिनों में हमारी पार्टी कई ने कई संघर्षों किए हैं, जिसमें भांगर आंदोलन भी शामिल है, जहां प्रकृति और पारिस्थितिकी को बचाना मुख्य मुद्दों में से एक था।

11.3 परमाणु हथियारों के खिलाफ और मौजूदा और प्रस्तावित परमाणु संयंत्रों के खिलाफ आंदोलन भी वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों के साथ मिलकर छेड़ा गया है। देश के कई हिस्सों में ओपन कास्ट कोयला खनन के खिलाफ संघर्ष भी विकसित हो रहे हैं। इन सभी गतिविधियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वयित करने के लिए, पारिस्थितिकी संरक्षण और वैकल्पिक विकास के लिए फोरम (एफईपीएडी) भी लॉन्च किया गया है।

12. मुक्ति के लिए महिलाओं और एलजीबीटीक्यूआईए+ को गोलबंद करना

12.1 मार्क्सवाद हमें सिखाता है कि "इतिहास में दिखाई देने वाला पहला वर्ग विरोध एकल विवाह में पुरुष और महिला के बीच विरोध के विकास और पुरुष द्वारा महिला के साथ पहले वर्ग उत्पीड़न के साथ मेल खाता है। मोनोगैमी एक महान ऐतिहासिक प्रगति थी, लेकिन उस समय उसी समय इसने गुलामी और निजी संपत्ति के साथ आज तक कायम उस काल का उद्घाटन किया, जिसमें एक समूह का कल्याण और विकास दूसरे की पीड़ा और दमन से प्राप्त होता है"। जैसा कि माओ त्से तुंग ने चीन में सांस्कृतिक क्रांति की पहली लहर के बाद बताया, पूर्व-क्रांतिकारी देशों में राजनीतिक सत्ता पर कब्जा और क्रांति के बाद के समाजों में समाजवादी परिवर्तन को लगातार बढ़ती समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जब तक पूर्व के गुलामों की मुक्ति के प्रभावी तरीके गायब रहेंगे।

12.2 इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी को महिला मुक्ति आंदोलन के पक्ष में मजबूती से खड़ा होना चाहिए। इसे पितृसत्तात्मक पूंजीवादी-साम्राज्यवादी व्यवस्था के जुए से महिलाओं की मुक्ति और मजदूरों की मुक्ति के बीच कड़ी स्थापित करनी चाहिए। एक कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रह जाएगी और कम्युनिस्ट आंदोलन कम्युनिस्ट आंदोलन नहीं रहेगा अगर वह ऐसा करने में विफल रहता है। बहुत उन्नति के बावजूद तत्कालीन समाजवादी देशों ने इस क्षेत्र में कई रुकावटें दर्शाई हैं। हमें उन अनुभवों से भी सबक लेना चाहिए।

12.3 साम्राज्यवादी देशों की तुलना में भारत जैसे देशों में महिलाओं की स्थिति कहीं अधिक पिछड़ी हुई है। चुने जाने वाले निकायों में 33% आरक्षण प्रदान करने जैसे सतही परिवर्तनों का प्रतिरोध यह सुनिश्चित करता है कि यह लागू न हो पाये। मनुस्मृति की घोषणा कि 'स्त्रियाँ स्वतंत्रता की पात्र नहीं हैं' का प्रभाव अब भी हावी है। जाति व्यवस्था और धर्म महिलाओं के पिछड़ेपन को कायम रखते हैं। नवउदारवाद के तहत पूंजी और बाजार व्यवस्था के शासन ने महिलाओं की दुर्दशा को और तीव्र कर दिया है। महिलाओं और उनके शरीर को तेजी से उपभोग की वस्तु बनाया जा रहा है। वर्तमान पारिवारिक व्यवस्था एकल परिवारों में परिवर्तित होने के बावजूद, अब भी मूल रूप से पुरुष प्रधान और रूढ़िवादी बनी हुई है। दहेज प्रथा और पारिवारिक संपत्ति पर समान अधिकार से वंचित कर दिये जाने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में बाल विवाह, देवदासी प्रथा आदि जैसी पतित प्रथाएं अब भी जारी हैं। नव-फासीवादी शासन व्यवस्था द्वारा प्रायोजित सांप्रदायिक ताकतों और धार्मिक कट्टरतावाद के विकास ने महिलाओं की स्थिति को और बदतर कर

दिया है। नव-औपनिवेशिक संस्कृति के प्रभाव के चलते जैसे-जैसे हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में अधिकाधिक कन्या भ्रूणों को जन्म से पहले नष्ट किया जा रहा है, वैसे ही इन क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या भी कम हो रही है। नतीजतन, इन क्षेत्रों में एक नए प्रकार की महिलाओं की तस्करी हो रही है, जो घरेलू काम करने और बच्चे पैदा करने के लिए दूसरे राज्यों से 'ब्याह' कर लायी जाती हैं। महिलाएं न केवल दमनकारी पितृसत्तात्मक संस्थाओं का दंश झेलती हैं, बल्कि उन्हें वस्तु के रूप मे बेशर्म प्रस्तुतिकरण का भी शिकार होना पड़ता है। हालांकि नवउदारवादी नारीवादी आंदोलनों का शहरी क्षेत्रों में प्रभाव है, लेकिन वे सभी क्षेत्रों में निजी संपत्ति के बढ़ते प्रभुत्व और महिला दासता जैसे महिलाओं की जनता के वास्तविक मुद्दों को संबोधित नहीं करते हैं।

12.4 विशेष रूप से कम्युनिस्ट पार्टी और सामान्य रूप से कम्युनिस्ट आंदोलन द्वारा निभाई गई शानदार भूमिका के बावजूद उसकी कम्युनिस्ट आंदोलन में महिलाओं की भूमिका के बारे में अभी भी बहुत पिछड़ी समझ है। परिणामस्वरूप उन्हें आंदोलन और पार्टी में लाने की सच्ची इच्छा के बावजूद, प्रयास काफी हद तक विफल रहे हैं। बदले में इस असफलता ने कम्युनिस्ट पार्टी को न केवल संरचनात्मक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी विकसित करने के प्रयासों को प्रभावित किया है।

12.5 यह स्थिति महिलाओं के आंदोलन और कम्युनिस्ट आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर व्यापक और सही समझ विकसित करते हुये उनकी मुक्ति का कार्य करने के लिए विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को संगठित करने के सचेत प्रयासों की मांग करती है। पार्टी को एक शक्तिशाली महिला जन आंदोलन के विकास में सहायता के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए।

12.6 पार्टी के अंदर और बाहर पितृसत्तात्मक मानसिकता के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई के बिना महिला मुक्ति हासिल नहीं की जा सकती है। पितृसत्ता को खत्म करने के लिए महिलाओं को संगठित करना ही काफी नहीं है । हमें पार्टी के भीतर और बाहर व्याप्त पुरुषवादी मानसिकता के खिलाफ भी लड़ना है। पुरुषवादी सोच के खिलाफ लड़ाई को सड़कों से लेकर खेतों तक, घरों से दफ्तरों तक, रसोई से लेकर शयनकक्षों तक फैलाना है। पार्टी सामुदायिक रसोई के विकास सहित महिला- केंद्रित घरेलू कार्य को समुदाय-केंद्रित कार्य में बदलने का प्रयास करेगी ।

13. सांस्कृतिक मोर्चे में कार्य

13.1 काफी लंबे समय से सांस्कृतिक मोर्चे के कार्यों को क्रांतिकारी गीत गाने या क्रांतिकारी नाटक करने आदि के लिए टोलियों के निर्माण के रूप में समझा गया है। इप्टा जैसे संगठनों के गौरवशाली अतीत को संजोया गया है जबकि यह भुला दिया गया था कि इस क्षेत्र के वास्तविक कार्य बहुत बड़े हैं। इतिहास में कोई भी वर्ग केवल ताकत के बल पर लोगों पर शासन नहीं कर सका है, यदि वह जनता पर अपनी संस्कृति के प्रभुत्व और आधिपत्य को स्थापित करने में विफल रहा है। इसलिए, एक सफल सामाजिक परिवर्तन करने के लिए क्रांतिकारी ताकतों को अपने सांस्कृतिक प्रभाव को सांस्कृतिक आधिपत्य के स्तर पर स्थापित कर उसका उत्थान करना चाहिए। वर्ना क्रान्ति की जीत नहीं हो सकती, और यदि हो भी जाती है तो कायम नहीं रह सकती। प्रदर्शन कला ऐसा करने के साधनों में से एक है। निजी संपत्ति और साम्राज्यवादी संस्कृति की विचारधारा के आधिपत्य के साथ-साथ सामंती संस्कृति, धर्म और जाति व्यवस्था के निरंतर प्रभाव का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी प्रगति को विफल करने और साम्राज्यवादी व्यवस्था की सेवा करने के लिए किया जाता है। हमें साम्राज्यवादी संस्कृति को थोपने का विरोध करना चाहिए, साथ ही पुराने रूढ़िवादी विचारों और अंधविश्वास को खारिज करते हुये पूरे देश में समाजवादी संस्कृति को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। क्रांतिकारियों के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम वैकल्पिक प्रगतिशील और क्रांतिकारी संस्कृति की स्थापना करें।

13.2 हम पीडीआर के कार्यों को पूरा करने, जनता के जनवाद को साकार करने और अपने देश में समाजवादी क्रांति की ओर बढ़ने के लिए ऐसे समय में क्रांति का रास्ता सामने रख रहे हैं, जब रूस के अक्टूबर क्रांति के दौरान की स्थिति, या चीन और अन्य देशों में हुई क्रांतियों के विपरीत सामाजिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारी परिवर्तन हो चुके हैं । नव-उदारवाद के आगमन के साथ साम्राज्यवादी शक्तियों ने संस्कृति के क्षेत्र में मानव-विरोधी, असामाजिक, पितृसत्तात्मक, धार्मिक, प्रतिक्रियावादी सोच, आदतों और जीने के तरीकों के साथ तकनीकी क्षेत्रों में आधुनिक नवाचारों का उपयोग करके मानव मन पर कब्जा करने के लिए विशेष जोर दिया। निस्संदेह यह सच है कि कम्युनिस्ट आंदोलन अब तक सांस्कृतिक क्षेत्र में एक सफल प्रति-आक्रमण शुरू करने में विफल रहा है। सांस्कृतिक क्रांति के प्रश्न को या तो उपेक्षित कर दिया गया है या केवल औपचारिक मुहावरेबाजी तक सीमित कर दिया गया है।

13.3 यद्यपि नक्सलबाड़ी विद्रोह ने सांस्कृतिक क्षेत्र में भी एक नया भूकम्प पैदा कर दिया था लेकिन यह अल्पकालिक था। जल्द ही, जैसा कि आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में हुआ, कला, साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी नव-औपनिवेशिक, साम्राज्यवादी हमले नए रूपों में तेज हो गए। इन प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों की तालिका बहुत लंबी है जिसमें कला, साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्रों में नए आयात जैसे, शिक्षा और सभी कल्याणकारी क्षेत्रों का व्यावसायीकरण, अनुसंधान के क्षेत्र में नव-औपनिवेशिक परियोजनाएँ, विश्व बैंक की सांस्कृतिक परियोजनाएँ और धार्मिक रूढ़िवादिता के कई अन्य नए अवतार, नए रूपों में जाति व्यवस्था और नस्लवाद की वकालत, नारी मुक्ति पर हमले, कला और साहित्य पर अंकुश लगाने के काले कृत्य आदि शामिल हैं। ये सभी क्षेत्रों में लोगों के जनउभार में बाधा बन रहे हैं। इस स्थिति को उलटने के लिए चौतरफा आक्रामण छेड़ने की जरूरत है।

13.4 यद्यपि प्रति-क्रांतिकारी प्रवृत्तियों का विरोध करने वाली क्रांतिकारी सांस्कृतिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वे स्थानीय हैं, व्यापक या दीर्घ नहीं हैं। वे सतही बने रहते हैं या तात्कालिक नारों तक ही सीमित रहते हैं, वे इसमें शामिल बुनियादी वैचारिक मुद्दों पर नहीं जाते हैं। क्रांतिकारी कतारों में ऐसे कई लोग हैं जो क्रांतिकारी सांस्कृतिक हमले के महत्व को नहीं पहचानते जिसमे मानव विचारों और संस्कृति को एक सतत प्रक्रिया के रूप में बदलने के लिए एक बुनियादी कार्य के रूप में शुरू से ही लिया जाना है। अतः क्रान्तिकारी गतिविधियों को विकसित करते समय सांस्कृतिक क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए। सांस्कृतिक आंदोलन की सामग्री पर गंभीरता से बहस और उसका विकास किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों को भी विकसित किया जाना चाहिए। इस कार्य को राज्य स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर आवश्यक बल प्रदान करते हुए लिया जाना चाहिए, और इसके सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं को गंभीरता से लेते हुए एक अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन बनाने के लिए जोरदार प्रयासों की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य के साथ अखिल भारतीय स्तर पर सांस्कृतिक आक्रमण शुरू करने के लिए उठाए गए कदमों ने सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के अखिल भारतीय समन्वय का गठन किया है। समाज के क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर आक्रमण को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

14. छात्रों और युवाओं को क्रांति के लिए गोलबंद करना

14.1 युवाओं और छात्रों की सक्रिय भागीदारी के बिना कोई भी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन सफल नहीं हो सकता। इतिहास हमें सिखाता है कि अगर वे क्रांतिकारी राजनीति में लामबंद नहीं होते हैं तो फासीवादी ताकतें प्रतिक्रियावादी जन आंदोलनों को विकसित करने के लिए उन्हें, विशेषकर युवाओं के सबसे उत्पीड़ित वर्ग को हमेशा अपनी ओर खींचती हैं। हमारे देश के युवाओं का सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम में और बाद में कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य प्रगतिशील आंदोलनों के नेतृत्व में साम्राज्यवाद-विरोधी, सामंतवाद-विरोधी संघर्षों में सक्रिय रूप से भाग लेने का गौरवशाली इतिहास रहा है।

औपनिवेशिक ताकतों को चुनौती देने वाले अशफाकउल्ला खान और भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी युवाओं की भूमिका आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। लेकिन 1947 में सत्ता हस्तांतरण और कम्युनिस्ट पार्टी में संशोधनवादी प्रवृत्तियों के उभरने के साथ, युवा निराश होने लगे और प्रतिगामी विचारधाराओं से प्रभावित होने लगे और संशोधनवादियों ने युवाओं को गुमराह किया, जिससे वे विरक्ति और मोहभंग की ओर बढ़े, इसने उन्हें प्रतिक्रिया की ओर मोड़ दिया। कई सुधारवादी और यहां तक कि प्रतिक्रियावादी ताकतों में शामिल हो गए। जब नक्सलबाड़ी विद्रोह ने एक क्रांतिकारी उथल-पुथल पैदा की, तो एक बार फिर हजारों युवा क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। लेकिन संकीर्णतावादी प्रवृत्तियों के प्रभाव ने एक बार फिर इस उभार को झटका दिया। कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन एक क्रांतिकारी कार्यक्रम के साथ युवाओं को एक देशव्यापी संगठन में लामबंद करने में विफल रहा। हालांकि आंतरिक आपात काल के दौरान और बाद में प्रगतिशील सक्रियता की फुहारें उठीं, लेकिन ये अल्पकालिक थीं। अखिल भारतीय स्तर पर वामपंथी आंदोलन में युवाओं की भागीदारी घटती चली गई।

14.2 इस बीच बढ़ते हुए नवउपनिवेशीकरण के तहत, विशेषकर नवउदारवादी नीतियों के लागू होने के बाद, युवाओं और छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियाँ तेज हो गई हैं। शिक्षा प्रणाली का व्यावसायीकरण और नव-उदारवादी पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के एक बड़े वर्ग को सामाजिक वास्तविकताओं से दूर ले जा रहे हैं। व्यावसायीकरण ने उच्च शिक्षा को एक आभिजात्य क्षेत्र के रूप में बदल दिया है जो ज्यादातर उच्च जाति, उच्च वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित है। बेरोजगारी और अल्प रोजगार का बोलबाला हो गया है। यहां तक कि पहले से कार्यरत लोगों का भी रोजगार छिनने लगा है। साथ ही निहित स्वार्थ वाले लोग उनमें साम्राज्यवादी संस्कृति, नशाखोरी और अपराधीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि कुंठित युवाओं को प्रगतिशील आंदोलनों में शामिल होने से रोका जा सके। नतीजतन, युवाओं का एक बड़ा वर्ग प्रतिगामी सोच से प्रभावित होकर एक ओर सांप्रदायिक, जातिवादी और उग्रवादी ताकतों द्वारा बड़ी संख्या में भर्ती कर लिया जाता है, और दूसरी ओर शासक वर्गों द्वारा उनके प्रचारक दल और माफिया गिरोहों के रूप में भर्ती किया जाता है।

14.3 हालांकि, नई सहस्राब्दी में देश भर में जन आंदोलनों के उदय के साथ एक बार फिर छात्रों और युवाओं की संख्या बढ़ रही है जो क्रांतिकारी आंदोलनों में आ रहे हैं। विस्थापन के खिलाफ कई संघर्षों से शुरू होकर हाल के किसान आंदोलनों में भगवा नव-फासीवादी ताकतों के खिलाफ आंदोलनों जैसे एनआरसी विरोधी आंदोलनों और अन्य में अच्छी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। कई चुनावी संघर्षों में भी छात्र-युवाओं की भागीदारी साफ दिखाई दे रही है। पार्टी का काम क्रांति और सामूहिक संघर्ष की दिशा में लड़ने वाले युवाओं के इस पूरे समूह का राजनीतिकरण करना है।

15. फासीवाद का मुकाबला

15.1. आज भाजपा सरकार का सत्ता में उत्थान 1998 में एनडीए के सत्ता में आने से स्पष्ट रूप से भिन्न है। पूँजीवाद के तीव्र सामान्य संकट की पृष्ठभूमि में इस बार यह कॉर्पोरेट-भगवा फासीवादी शासन का उदय है, जो वैश्विक नव—फासीवाद के उभार के हिस्से के रूप में है सामने आया है। हिंदुराष्ट्र की स्थापना के नारे का वास्तव में अर्थ फासीवादी भारत की स्थापना करना है। भारतीय राजनीति के इस अति दक्षिणपंथी मोड़ में शामिल खतरों को वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में देखा जाना चाहिए जब अमेरिका के नेतृत्व वाले साम्राज्यवादियों ने साम्राज्यवादी प्रभुत्व के खिलाफ वर्ग संघर्ष और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों को विशाल क्षेत्रों में 'सभ्यताओं के टकराव' से बदलने में सफलता प्राप्त की है, जो सभी तरह के धार्मिक कट्टरतावाद का प्रचार और यहां तक कि पश्चिम एशिया में सुन्नी-शिया संघर्ष को भी बढ़ावा देता है।

15.2 नई स्थिति के अनुसार सही रणकौशल और रणनीतिक कदमों का विकास करना कम्युनिस्ट आंदोलन के सामने एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि यह गुणात्मक रूप से नई स्थिति है जो जारी वर्ग संघर्ष पर नई और उच्च समझ की मांग करती है।

चूंकि कम्युनिस्ट आंदोलन हमारे देश में नव-फासीवादी शासन और नव-फासीवादी विकास का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी को शासक वर्ग के फासीवादी वर्ग और गैर-फासीवादी वर्ग के बीच के अंतरविरोध का बुद्धिमानी से उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही लोगों के सामने क्रांतिकारी वाम विकल्प विकसित करने की काफी समय से लंबित जिम्मेदारी बिना समय गंवाए हाथ में लेनी चाहिए। वर्तमान स्थिति में भारत में कम्युनिस्ट आन्दोलन के लिए एक ओर व्यापक संभव फासीवाद-विरोधी एकता विकसित करना और दूसरी ओर क्रांतिकारी विकल्प विकसित करने के दो कार्य हैं।

16. राष्ट्रीयता का प्रश्न

16.1 राष्ट्रीयता के प्रश्न के समाधान पर, पार्टी कार्यक्रम कहता है: "अलग होने तक सभी राष्ट्रीयताओं के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार सुनिश्चित करें। प्रजातंत्र विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोगों को बल से नहीं, बल्कि उनकी स्वैच्छिक सहमति से एकजुट करने का प्रयास करेगा। जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के मसलों का समाधान सेना को तत्काल वहां से हटाकर और राजनीतिक माध्यमों से आत्मनिर्णय के अधिकार को सुनिश्चित करके किया जाये।" भारत एक बहुराष्ट्रीय देश है जहाँ प्रान्तों, जिन्हें भाषाई आधार पर रियासतों और अंग्रेजी हुकूमत के तहत गठित किया गया था, के पुनर्गठन के लिये भी 1950 के दशक में जनता को खूनी संघर्ष करना पड़ा था। पिछले पांच दशकों के दौरान केंद्र सरकारों ने लगातार 'राष्ट्रीय एकता' या अखंडवाद जैसे उग्रवादी नारों का प्रचार करते हुए राज्यों के कई संवैधानिक अधिकारों को छीन लिया है।

16.2 ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने अपनी लूट को सुविधाजनक बनाने के लिए रियासतों को एक उपनिवेश में बलपूर्वक 'संगठित' किया था, और धार्मिक, जातिवादी, नस्लवादी विचारधाराओं और सामंती ताकतों का उपयोग करते हुए उन्होंने 'फूट डालो और राज करो' की नीति अपनाई थी। उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्षों के दौरान हासिल की गई एकता को अब सत्ता हस्तांतरण के बाद शासक वर्गों ने तोड़ दिया है। इसके खिलाफ लड़ते हुए, कम्युनिस्ट पार्टी को सभी राष्ट्रीयताओं के आत्मनिर्णय के अधिकार के आधार पर अलगाव तक की एकता के लिए संघर्ष करना चाहिए।

16.3 विशेष रूप से साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के लागू होने के बाद, जिससे एफडीआई, एफआईआई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों आदि के प्रवेश को गति मिली और जिसने पूंजी-बाजार राज को मजबूत किया, उत्पादन के पूंजीवादी तरीके के विकास के साथ असमान विकास, विभिन्न क्षेत्रों को 'विकास' सीढ़ी में ऊपर या नीचे धकेल दिया जाना एक कड़वी हकीकत बनती जा रही है। इसके लिए जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही साम्राज्यवादी तानाशाही 'विकास' नीतियों का विरोध करने के बजाय अलग-अलग शासक वर्ग की पार्टियां और साथ ही दलाल और निम्न-बुर्जुआ वर्ग इन पिछड़े क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने की मांग उठा रहे हैं। इन पहले से बने छोटे राज्यों जहां विशाल जनता के रहने की स्थिति में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आया है, के नकारात्मक अनुभव के बावजूद नए राज्यों की मांग लगातार उठाई जा रही है।

16.4 जैसा कि मार्क्सवाद सिखाता है, राष्ट्रीयता का प्रश्न और उससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े विभिन्न आंदोलन बुर्जुआ प्रश्न हैं। चूंकि नए राज्यों की कई मांगें लोगों को उनके सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों से हटाने के लिए उठाई जाती हैं, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी को इन आंदोलनों की पूंछ बनने से गंभीरतापूर्वक बचना चाहिए। साथ ही, इन संघर्षों से प्रभावित जनसमुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए एकता और संघर्ष का दृष्टिकोण इस सोच के साथ अपनाना चाहिए कि नए राज्यों की मांग के साथ-साथ जनता के बुनियादी मुद्दों को भी उठाया जाए।

17. संघर्ष के संसदीय रूपों का उपयोग

17.1 प्रांतीय और केंद्रीय विधान सभाओं के चुनाव भारत में औपनिवेशिक दिनों से शुरू किए गए थे। सत्ता हस्तांतरण के बाद 1950 में अपनाए गए संविधान के तहत सभी स्तरों पर संसदीय प्रणाली को अपनाया गया।

आज, लोक सभा के लिए पंचायत स्तर और यहां तक कि सहकारी समितियों और विभिन्न अन्य संस्थानों के चुनाव नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, जो बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। पूर्व-क्रांतिकारी रूस में भी, चुनावों में भागीदारी का अनुभव आंशिक और सीमित था। चीन और अन्य देशों में जहां क्रांति हुई, वर्ग संघर्ष को विकसित करने के लिए संघर्ष के रूप में संसदीय प्रणाली का उपयोग करने का कोई अनुभव नहीं था। फिर भी द्वितीय इंटरनेशनल और पश्चिम यूरोपीय देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों के अनुभव से सीखकर, लेनिन ने एक ओर संसदीय उन्मादवाद के खिलाफ संघर्ष करने की आवश्यकता, और दूसरी ओर एक रणनीतिक दिशा के रूप में चुनावों का बहिष्कार करने की राजनीति की ओर इशारा किया था।

17.2 चुनावों में भाग लेने का एक क्रांतिकारी तरीका और एक सुधारवादी तरीका होता है। सीपीआई और सीपीआईएम ने लंबे दशकों में इस पिछले तरीके का प्रदर्शन किया है। उन्होंने वर्ग संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सरकारों का उपयोग नहीं किया, बल्कि प्रतिक्रियावादी शासक वर्ग की नीतियों को जनता पर थोपने के लिए किया है। समाज का क्रांतिकारी परिवर्तन लंबे समय से उनके चुनावी एजेंडे का हिस्सा नहीं रहा है। इससे गलत सीख लेते हुए भाकपा(माले) ने अपने गठन के बाद रणनीतिक लाइन के रूप में 'चुनाव का बहिष्कार' अपनाया और बाद में, हालांकि कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के कई वर्गों ने इस लाइन को छोड़ दिया, लेकिन माओवादी रूझान अब भी इस पर अमल कर रही है. चुनाव में भाग लेने के सीपीआई-सीपीआईएम के सुधारवादी तरीके ने अगर उसके वैचारिक दिवालियापन को उजागर किया है और उसे सही अवसरवादी स्थिति में डाल दिया है, तो दूसरे छोर पर बहिष्कार का अनुभव पूरी तरह से नकारात्मक साबित हुआ है। बहिष्कार का आह्वान करने के बाद भी भाकपा (माओवादी) ने अवसरवादी हथकंडे अपनाए हैं जैसे हाल के दिनों में सत्ताधारी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों को गुप्त रूप से या खुले तौर पर समर्थन देना। बहुत कम जगहों पर वे बहिष्कार के अपने आह्वान को 'लागू' करने में सफल हुए हैं। बहिष्कार को लागू करने के लिए जिन तरीकों का सहारा लिया जाता है, वे उसे जनता से और अलग कर देते हैं। हाल के वर्षों में देश के लगभग सभी भागों में मतदान प्रतिशत काफी अधिक रहा है। हमारे देश की ठोस स्थिति में संसदीय संघर्ष, संघर्ष के महत्वपूर्ण रूपों में से एक है। हमें संसदीय संघर्षों से अधिक को प्राथमिक मानते हुए संसदीय संघर्ष को उचित महत्व देना चाहिए। गैर-संसदीय संघर्षों के विकास के लिए संसद और विधानसभाओं के मंचों का ठीक से उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है।

17.3 भारत 130 करोड़ से अधिक लोगों का देश है जहाँ बुर्जुआ संसदीय व्यवस्था कई दशकों से सभी स्तरों पर हर गली कूचे में अच्छी तरह से स्थापित है। कम्युनिस्ट पार्टी को सभी क्षेत्रों में वर्ग संघर्ष को विकसित करने के लिए संघर्ष के अन्य सभी रूपों के साथ बुर्जुआ संसदीय प्रणाली का उपयोग करना चाहिए, शक्तिशाली जन-उभार छेड़ना चाहिए ताकि वह राजनीतिक सत्ता के क्रांतिकारी कब्जे की ओर बढ़ सके और जनता के जनवाद को व्यवहार में ला सके।

18. रणनीतिक और सामरिक संयुक्त मोर्चा

18.1 पार्टी ने हमेशा ही विभिन्न स्तरों पर संयुक्त मोर्चे को विकसित करने का प्रयास किया है, हमारे देश में वर्तमान नव-फासीवादी संदर्भ इस रणनीति को नए जोश के साथ विकसित करने का आह्वान करता है। लोगों के सामने आने वाले कई मुद्दों को उठाने के लिए, समान विचारधारा वाली ताकतों को एकजुट करने के लिए मुद्दा आधारित संयुक्त गतिविधियों को शुरू करना होगा। ये संयुक्त गतिविधियाँ मजदूर वर्ग के क्षेत्र में, कृषि मोर्चे पर और सभी जन आंदोलनों में अन्य ट्रेड यूनियनों या टीयू केंद्रों के साथ एकजुट होकर श्रमिकों की समस्याओं के लिए संघर्ष करने, कृषि मोर्चे में अन्य समान विचारधारा वाली ताकतों के साथ एकजुट होने से संभव हो पाएगा। इन संयुक्त मोर्चों या मंचों के माध्यम से मुद्दों को उठाने के लिए एक व्यापक, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए। हालांकि ये मुद्दों पर आधारित हैं और थोड़े समय के लिए ही जारी रह सकते हैं, लेकिन ये लोगों के विभिन्न मुद्दों को उठाने में मदद करते हैं। इस तरह की संयुक्त गतिविधियों से पार्टी और वर्ग/जनसंगठनों को अपनी गतिविधियों को और अधिक क्षेत्रों में फैलाने में मदद मिलेगी।

18.2 अनुभव बताता है कि थोड़े से उकसावे पर राज्य तंत्र काले कानून लागू करता है और लोगों के खिलाफ आतंकी रणनीति का इस्तेमाल करता है। लोकतांत्रिक अधिकार छीने जाते हैं। यहां तक कि शांतिपूर्ण जन आंदोलनों को भी क्रूरता से दबा दिया जाता है। इससे पार्टी और वर्ग व जनसंगठनों का कामकाज बाधित होता है। इस तरह के दिन-प्रतिदिन के घटनाक्रमों के खिलाफ एकजुट लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकार आंदोलनों को ठोस परिस्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए।

18.3 इन मुद्दों पर आधारित संयुक्त गतिविधियों से एक कदम आगे बढ़ते हुए, जैसे-जैसे इन संघर्षों और वर्ग/जनसंगठनों की ताकत बढ़ती है, लंबे समय तक चलने वाले राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर अधिक बुनियादी मुद्दों को उठाने और संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए राजनीतिक मंचों के गठन की संभावनाओं को विकसित किया जा सकता है। मध्यवर्ती स्तर के मोर्चों के निर्माण की संभावनाएँ उभरेंगी, जो वर्ग संघर्ष के विकास में सहायक होंगी। ऐसी हर संभावना का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।

18.4 मौजूदा स्थिति में जब मोदी सरकार मनुवादी विचारधाराओं के साथ मिलकर नव-फासीवादी नव-उदारवादी नीतियों को लागू करना तेज कर रही है , तब डेमोक्रेटिक पीपुल्स फोरम को विकसित करना या इसे वामपंथी संघर्ष और जनवादी ताकतों के एक व्यापक मंच के रूप में पुनर्गठित करना एक अत्यावश्यक कार्य है ताकि जनता को गोलबंद करके राज्य स्तर और अखिल भारतीय स्तर के आंदोलनों को शुरू किया जा सके। पार्टी को राज्य और अखिल भारतीय स्तर पर इसके लिए तत्काल पहल करनी होगी।

18.5 साम्राज्यवाद की सेवा करने वाले दलाल नौकरशाह बुर्जुआ-जमींदार वर्गों के भारतीय राज को उखाड़ फेंकने और जनता की जनवादी सत्ता स्थापित करने के लिए परिस्थितियाँ बनाने हेतु पार्टी द्वारा जनता के संघर्षों के विकास के स्तर और ठोस स्थिति के अनुसार रणनीतिक निर्माण के लिए दीर्घ प्रयास किए जाने चाहिए ताकि मजदूर-किसान गठजोड़ पर आधारित संयुक्त मोर्चा का निर्माण किया जा सके और सभी वास्तविक साम्राज्यवाद-विरोधी, देशभक्त, जनवादी वर्गों और तबकों के साथ एकता कायम की जा सके।

19. भारतीय क्रांति का रास्ता

19.1 भारत 1.3 अरब लोगों का एक बहुत विशाल देश है। इसमें अत्यधिक विविधता और असमानता है। इसलिए संघर्ष के सभी साधनों और तरीकों का संयोजन अत्यंत आवश्यक है। हमारी पार्टी का कार्यक्रम कहता है: "क्रांतिकारी जनदिशा के मार्ग को कायम रखते हुए, और सभी प्रकार के संघर्षों और संगठनों का उपयोग करते हुए, पार्टी को मजदूर वर्ग और सभी क्रांतिकारी वर्गों और तबकों को भारतीय राजसत्ता को उखाड़ फेंकने और राजनीतिक सत्ता को जब्त करने के लिए बड़े पैमाने पर देशव्यापी जन-उभार लाने के लिए पहल करनी चाहिए।

19.2 जहां सीपीआई, सीपीआईएम जैसे सामाजिक-जनवादी दलों ने क्रांति के विचार को समग्र रूप से त्याग दिया है और एक तरफ संसदीय उन्मादवाद में पूरी तरह से डूब गए हैं, वहीं सीपीआई (माओवादी) जैसे संगठन "क्षेत्रवार सत्ता हथियाने" के रास्ते की वकालत कर रहे हैं। जहां तक मार्ग का संबंध है, हम इन दोनों समझ को अस्वीकार करते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उपयुक्त समय पर स्थानीय सत्ता पर कब्जा करने की संभावना को खारिज करते हैं। हम दृढ़ता से महसूस करते हैं कि भारत जैसे विशाल और विविध देश में कई अलग-अलग रणनीतियों का संयोजन आवश्यक और काफी स्वाभाविक है। "सत्ता की क्षेत्रवार जब्ती" को एक दिशा के रूप में स्थापित करने की समझ झूठी और गलत अवधारणा से आई है कि भारत जैसे देश में एक अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष स्वाभाविक नहीं है। हालाँकि, वर्तमान किसान आंदोलन सहित कई अखिल भारतीय संघर्ष बताते हैं कि अखिल भारतीय क्रांतिकारी आंदोलनों को विकसित किया जा सकता है और भारतीय राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए इसे विकसित

किया जाना चाहिए। हालाँकि, देशव्यापी विद्रोह की स्थिति में विद्रोह हो सकता है या इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि राजनीतिक सत्ता की जब्ती पहले एक क्षेत्र में सीमित होती है और उसके बाद पूरा देश मुक्त करा लिया जाता है।

19.3 पिछले कुछ दशकों में कम्युनिस्ट आन्दोलन इतना कमजोर हो गया है कि जनदिशा की हिमायत करने वाली और कई मुद्दों पर स्पष्ट एकरूपता रखने वाली सभी मार्क्सवादी-लेनिनवादी ताकतों को एकजुट करने का कठिन लेकिन अनिवार्य कार्य भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में पीडीआर को पूरा करने का विशाल कार्य करने के लिए मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी इतनी मजबूत नहीं है। पूरी दुनिया में लगभग यही हाल है। इन चुनौतियों का निर्भीकता से सामना करना होगा और क्रांति की व्यक्तिपरक शक्तियों को मजबूत करना होगा, जिसमें अखिल भारतीय प्रभाव वाली एक शक्तिशाली बोल्शेविक मॉडल पार्टी का निर्माण करना सबसे प्रमुख कार्य है। पार्टी को शासक वर्ग के विकल्पों, जो मूल रूप से मौजूदा शासन व्यवस्था की सेवा में एकजुट हैं, को चुनौती देने वाला एक क्रांतिकारी जनता का विकल्प तैयार करना होगा। जनता की जनवादी क्रांति के कार्यों को पूरा करने के लिए पार्टी को राजनीतिक सत्ता हथियाने की दृष्टि से सभी प्रकार के संघर्षों का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करना होगा।

19.4 देश के विभिन्न हिस्सों में अन्य सामंतवाद-विरोधी संघर्षों की निरंतरता में, 1946-51 का महान तेलंगाना संघर्ष, नौसैनिक विद्रोह और पुनाप्रा-वायलर विद्रोह और इन वर्षों के कई मजदूर वर्ग संघर्ष देश के सबसे बड़े और सबसे उन्नत क्रांतिकारी उभार थे। तेलंगाना संघर्ष ने सिखाया कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में कैसे जोतने वाले को जमीन के नारे पर ध्यान केन्द्रित करते हुये क्रांतिकारी कृषि संघर्ष छेड़े जा सकते हैं और कैसे भूमिहीन, गरीब किसानों और कृषि मजदूरों और माध्यम किसानों और कृषि से जुड़े अन्य कृषक वर्गों के नेतृत्व में ग्राम समितियों, स्वयंसेवी दस्तों का गठन, जमींदारों-पुलिस-गुंडा हिंसा के प्रतिरोध का विकास, और प्रतिक्रियावादी राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत की जा सकती है। महान नक्सलबाड़ी विद्रोह ने मिदनापुर, मुशहरी, लखीमपुर-खीरी और श्रीकाकुलम में आदिवासियों, दलितों और अन्य उत्पीड़ित वर्गों सहित भूमिहीन, गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के क्रांतिकारी विद्रोह को जन्म दिया। हालांकि ये संघर्ष बाद में आंध्रप्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों तक फैल गए, लेकिन संकीर्णतावादी लाइन के प्रभुत्व के कारण आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। क्रान्तिकारी आन्दोलन के सामने मुख्य समस्या यह थी, और अब भी है कि इन तमाम संघर्षों के क्रान्तिकारी अनुभव को आत्मसात करते हुए नवउपनिवेशवादी प्रभुत्व के अधीन वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप क्रान्ति का मार्ग कैसे विकसित किया जाए।

19.5 अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के रूस में अक्टूबर क्रांति की जीत, 1944-45 के दौरान पूर्वी यूरोपीय देशों में क्रांतियों की जीत और फासीवादी ताकतों की हार, 1949 में महान चीनी क्रांति की जीत का गौरवशाली इतिहास है। मार्क्सवादी-लेनिनवादी ताकतों को इन क्रांतियों से और उनकी असफलताओं से उचित सबक लेना चाहिए। लेकिन उनके अनुभवों को लेने का मतलब यांत्रिक रूप से उनमें से किसी के अनुभव की नकल करना या उनके अनुभवों के उदार मिश्रण का पीछा करना नहीं है। उनसे अनुभव लेने का अर्थ है उनके अनुभव का अध्ययन करना, उनसे सबक लेना और उन्हें अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार लागू करना। आईसीएम का इतिहास बताता है कि इन सभी देशों में जहां क्रांति हुई, अन्य क्रांतियों के रास्ते का कोई यांत्रिक अनुप्रयोग नहीं था, और प्रत्येक क्रांति ने प्रत्येक देश की परिस्थितियों के अनुसार अपना रास्ता तय किया। भारतीय क्रांति के सिद्धांत और व्यवहार को पूरी तरह से भारत की वर्तमान स्थितियों के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए, जिसमें अब तक की सभी क्रांतियों से जो भी अनुभव लिया जा सकता है उसे आत्मसात किया जाना चाहिए।

19.6 हालांकि भारतीय क्रांति वर्तमान में जनवादी चरण में है, किन्तु तत्कालीन समाजवादी देशों में, विशेष रूप से सोवियत संघ और चीन में, क्रांति के बाद की स्थिति में क्या हुआ, इसका मूल्यांकन किया जाना है और इससे सबक लिया जाना बाकी है। उदाहरण के लिए, पार्टी निर्माण जैसे क्षेत्रों में अनुभव, जनवादी केंद्रीयवाद की अवधारणा को विकसित करने में, आंतरिक-पार्टी संघर्ष के लिए उपयुक्त तरीके विकसित करने में, नौकरशाही प्रवृत्तियों के उद्भव से बचाव में, जनदिशा और वर्ग/जन संगठनों के निर्माण की अवधारणाओं को विकसित करने में, वर्ग संघर्ष के आर्थिक आधार को अधिरचना से यांत्रिक रूप से अलग करने की गलतियों से बचने में, उदाहरण के लिए, भारत के संदर्भ में, वर्ग संघर्ष से जाति-विरोधी आंदोलनों को अलग करने से बचने में, लोगों के बीच अंतर्विरोधों से सही ढंग से निपटने में, और सांस्कृतिक क्रांति से उचित सबक लेने आदि को संज्ञान देना होगा।

20. निष्कर्ष

20.1 भारतीय क्रांति का रास्ता हमारी पार्टी ने तब आगे बढ़ाया है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुगत स्थिति एक बार फिर क्रांतिकारी ताकतों के आगे बढ़ने के अनुकूल हो रही है, और दुनिया भर में साम्राज्यवाद विरोधी प्रतिरोध संघर्ष हो रहे हैं। भारत में, जो अत्यधिक विविधताओं और असमानताओं वाला एक बहुत बड़ा देश है, लाखों लोगों को शामिल करने वाले कई ऐतिहासिक संघर्षों के इतिहास के साथ दस दशकों की कम्युनिस्ट गतिविधियों के बावजूद, वर्तमान में हमारी पार्टी की ताकत अभी भी उल्लेखनीय नहीं है। दक्षिणपंथी अवसरवादी और अराजकतावादी प्रवृत्तियों से उत्पन्न चुनौती अभी भी बहुत गंभीर है। हालांकि नक्सलबाड़ी विद्रोह ने एक बार फिर पीडीआर को लोगों के एजेंडे में सबसे आगे ला दिया, लेकिन पिछले चार दशकों के दौरान मार्क्सवादी-लेनिनवादी आंदोलन ने इस दिशा में अभी तक कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की है।

20.2 सभी विजातीय प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्षरत भाकपा (माले) रेड स्टार वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय क्रान्ति का मार्ग आगे बढ़ा रही है। यह अखिल भारतीय स्तर पर वर्ग/जन संगठनों से घिरे बोल्शेविक मॉडल पर आधारित एक कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण, वर्ग संघर्ष को विकसित करने के लिए सभी प्रकार के संघर्षों का उपयोग, और जनउभार से जनविद्रोह और देशव्यापी विद्रोह से राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने की दिशा में आगे बढ़ने के महान महत्व पर बल देता है। साम्राज्यवादी हमले के नव-औपनिवेशिक चरण की विभिन्न स्थितियों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और हमारे देश में अब तक के सभी क्रांतिकारी संघर्षों के अनुभव को आत्मसात करते हुए, भारतीय क्रांति का रास्ता तैयार कर पीडीआर की जीत संभव है।

मौलाना आजाद फैलोशिप बंदः शिक्षा में पहले से ही पिछड़े मुसलमानों के लिए नई मुसीबत

राम पुनियानी

यूपीए-1 सरकार द्वारा 2005 में नियुक्त सच्चर समिति की रपट सन् 2006 में जारी हुई थी. इस रपट के अनुसार देश में मुसलमान, सामाजिक और राजनैतिक जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं. उनके खिलाफ अनवरत हिंसा ने उनके मन में असुरक्षा का भाव जागृत कर दिया है जिसके कारण सामाजिक-राजनैतिक जीवन में उनका प्रतिनिधित्व कम होता जा रहा है. यूपीए सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए. इनमें से एक कदम था मौलाना आजाद फैलोशिप की स्थापना. यह फैलोशिप अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा व शोध हेतु दी जाती थी. इसके लिए सभी अल्पसंख्यक वर्गों यथा मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध एवं जैन के विद्यार्थी पात्र थे. परंतु इससे लाभान्वित होने वालों में मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा थी. पिछली बार 1000 फैलोशिप में से 733 मुस्लिम विद्यार्थियों को दी गईं थीं।

स्वतंत्रता के बाद से शैक्षणिक दृष्टि से मुसलमानों की स्थिति में तेजी से गिरावट आई. इसका कारण था डर का वातावरण, गरीबी और सकारात्मक कदमों का अभाव. जैसे-जैसे मुसलमानों में शिक्षा के प्रति अभिरूचि घटती गई वैसे-वैसे स्कूलों में दाखिला लेने वालों में मुस्लिम विद्यार्थियों का अनुपात कम होता गया. केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मुसलमानों की साक्षरता दर 57.3 प्रतिशत है जबकि कुल आबादी में 73.4 प्रतिशत लोग साक्षर हैं. इसी तरह जहां देश में औसतन 22 प्रतिशत लोग मैट्रिक या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त हैं वहीं मुसलमानों में यह प्रतिशत 17 है. मुसलमानों में साक्षरता की दर अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से भी काफी कम है. उच्च शिक्षा व शोध संस्थानों में मुस्लिम विद्यार्थियों की मौजूदगी न के बराबअर है. सन् 2011 की जनगणना के अनुसार जहां 5.98 प्रतिशत हिन्दू स्नातक थे वहीं मुसलमानों के मामले में यह प्रतिशत 2.76 था. मुसलमानों की देश की कुल आबादी में हिस्सेदारी 14.2 प्रतिशत है परंतु केवल 5.5 प्रतिशत मुसलमान उच्च शैक्षणिक संस्थाओं तक पहुंच पाते हैं. इस पृष्ठभूमि में जाहिर है कि मौलाना आजाद फैलोशिप सही दिशा में एक छोटा सा कदम था. इस योजना को बंद कर दिया गया है।

इसी तरह मुसलमानों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को केवल कक्षा 9वीं और 10वीं तक सीमित कर दिया गया है. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की शुरूआत सन् 2008 में की गई थी. वह मैट्रिक में पढ़ रहे मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से बहुत उपयोगी थी. उस समय नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया था कि केन्द्र इस योजना को लागू करने के लिए गुजरात को मजबूर नहीं कर सकता क्योंकि यह योजना धर्म पर आधारित है. गुजरात सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र द्वारा भेजी गई धनराशि वापस कर दी थी।

गत 8 दिसंबर 2022 को अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने घोषणा की कि दिसंबर से मौलाना आजाद फैलोशिप योजना बंद कर दी जाएगी. सरकार की इस मनमानी कार्यवाही की कई लोगों ने खिलाफत की है और कांग्रेस व अन्य पार्टियों के सांसदों ने इस मसले को संसद में भी उठाया है. ईरानी का कहना है कि यह योजना इसलिए बंद की जा रही है क्योंकि इसी तरह की कई अन्य योजनाएं उपलब्ध हैं जिनके लिए मुस्लिम विद्यार्थी पात्र हैं जैसे कि ओबीसी के लिए छात्रवृत्तियां. शायद सुश्री ईरानी यह भूल रही हैं कि कोई भी विद्यार्थी एक से अधिक छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर सकता।

शोधार्थी अब्दुल्ला खान ने 'मुस्लिम मिरर' से बात करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट (एआईएसएचई) जिसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने तैयार किया है, के अनुसार उच्च शिक्षा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व एससी, एसटी व ओबीसी से भी कम है.

यह स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार सभी नागरिकों को एक बराबर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए जो भी थोड़े-बहुत प्रयास किए गए हैं उन्हें मटियामेट कर देना चाहती है. राजनैतिक स्तर पर साम्प्रदायिक तत्व अनेक तरीकों से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं. हाल में हमने देखा कि श्रद्धा-आफताब जैसे अपराधों को 'लव जिहाद' बताया जा रहा है. यह घटना हमारे पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक उदाहरण भर है परंतु इसे साम्प्रदायिक रंग दिया जा रहा है. हिन्दू पुरूषों द्वारा महिलाओं के साथ वीभत्स हिंसा की घटनाएं भी होती हैं परंतु इन पर साम्प्रदायिक तत्व चुप्पी साध लेते हैं.

इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा ही किसी समुदाय की उन्नति की कुंजी है. सईद मिर्जा की क्लासिक फिल्म 'सलीम लंगड़े पर मत रो' इस सच को बहुत शानदार तरीके से सामने लाती है. मुंबई के एक मानवाधिकार संगठन बेबाक कलेक्टिव द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह सामने आया है कि वर्तमान में जो सामाजिक स्थितियां व्याप्त हैं उनके कारण मुस्लिम युवक बहुत कुछ भोग रहे हैं.

भारत में विघटनकारी राजनीति के बढ़ते बोलबाले ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के जीवन को कई तरह से प्रभावित किया है. सत्ता में न रहने पर भी ये ताकतें अर्ध-धर्मनिरपेक्ष दलों की सरकारों पर दबाव बनाती हैं कि वे मुसलमानों और ईसाईयों की बेहतरी और भलाई के लिए कुछ न करें. नई शिक्षा नीति और शिक्षा के अंधे निजीकरण से गरीब और हाशियाकृत समुदायों की समस्याएं बढ़ेंगी ही. सत्ताधारी दल को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त है और इस तरह के निर्णयों पर विरोध दर्ज करवाने मात्र से सरकार अल्पसंख्यकों की मदद नहीं करने लगेगी और ना ही वह श्रेष्ठि वर्ग की बेहतरी के लिए काम करना बंद कर देगी.

सत्ताधारी दल की चुनाव मशीनरी इतनी बड़ी और इतनी शक्तिशाली है कि कम से कम निकट भविष्य में तो वह ऐसे किसी गठबंधन को सत्ता में नहीं आने देगी जो हाशियाकृत समूहों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो. परंतु इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हमें कोई न कोई राह निकालनी होगी ताकि यह डरा हुआ समुदाय खुलकर सांस ले सके और हम एक ऐसा समाज बना सकें जिसमें हरेक को आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त हों फिर चाहे उसका धर्म, जाति, भाषा और लिंग कुछ भी हो.

वर्तमान सरकार का एजेंडा अलग है. जो लोग 'यूथ फॉर इक्वालिटी' जैसे आंदोलनों के पीछे रहे हैं वे यह नहीं समझ सकते कि एक असमान समाज में सकारात्मक भेदभाव कितना महत्वपूर्ण है. अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी अब भी जामिया व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयों में उनके साथियों पर हुए हमलों को भूले नहीं हैं. जिस समय ईरानी केन्द्रीय शिक्षा मंत्री थीं उसी समय रोहित वेम्यूला ने आत्महत्या की थी. इससे शिक्षा जगत में दलितों की स्थिति रेखांकित होती है.

आगे का रास्ता क्या है? क्या मुस्लिम समुदाय के परोपकारी धनिक व वक्फ व अन्य सामुदायिक संपत्ति के नियंत्रणकर्ता आगे आकर उस अंतर को पाटेंगे जो मौलाना आजाद नेशनल फैलोशिप को बंद करने और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति को केवल कक्षा 9 और 10 तक सीमित कर देने से बना है. यह बहुत मुश्किल है परंतु अगर सरकार अपने इन दोनों निर्णयों को पलटती नहीं है तो इस तरह के कदम उठाना जरूरी हो जाएगा. सरकार अपने अल्पसंख्यक विरोधी एजेंडे को पूरे जोरशोर से लागू कर रही है. जो विद्यार्थी अपनी उच्च शिक्षा के अधबीच में हैं और जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं उनकी हर संभव मदद की जानी चाहिए.

जाति उन्मूलन आंदोलन को आगे बढ़ाएं, आरएसएस के वैचारिक आधार मनुवादी हिंदुत्व का प्रतिरोध करें

तुहिन

1936 में जब लाहौर के जात पात तोडक मंडल ने बाबा साहेब डॉ आंबेडकर को पहले ,सभापति के रूप में आमंत्रित किया और फिर भारत की निर्मम जाति व्यवस्था और हिंदुत्व के बारे में उनके क्रांतिकारी विचारों को जानकर उन्हें लाहौर के सम्मेलन में आमंत्रित नहीं करने का निर्णय लिया तब बाबासाहेब ने "जाति उन्मूलन" (Caste Annihilation) के नाम से अपनी पुस्तिका को छपवाया और वितरित किया।

उस समय उन्होंने एक युगांतरकारी बात कही थी कि भारत में अमानवीय जाति व्यवस्थां को उखाड़ फेंके बिना कोई लोकतांत्रिक समाज नहीं बन सकता।इसके लिए उन्होंने भारतीय जनता को दो दुश्मनों से लड़ने को कहा था-एक ब्राम्हणवाद तो दूसरा पूंजीवाद।शहीद भगत सिंह ने भी ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के साथ साथ उसकी दलाल भारतीय पूंजीवाद से भी हमें लड़ने को कहा था।आज की तारीख में हम देखते हैं कि ब्राम्हणवाद, फासिस्ट आरएसएस के वैचारिक आधार मनुवादी हिंदुत्व का रूप धारण कर आज के पूंजीवाद ,जिसे कॉरपोरेट राज कह सकते हैं का लठैत बना हुआ है।बाबा साहेब आंबेडकर की एक बात और हमें नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुराष्ट्र की स्थापना भारत के अंधकारमय युग की शुरुआत है।

2014 के मध्य में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से,दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फासीवादी संगठन आरएसएस,भारत को एक हिंदूराष्ट्र के रूप में बदलने की दिशा में सुनियोजित ताबड़तोड़ आक्रमण में लगा हुआहै। आरएसएस का वैचारिक आधार मनुस्मृति है, जिसके अनुसार दलितों/उत्पीड़ितों ,महिलाओं और गरीब मेहनतकशों को इंसान नहीं समझा जाता।इसके अलावा इनके तथाकथित हिंदुराष्ट्र(जो कि आम हिंदुओं के लिए नहीं है बल्कि अंबानी, अदानी जैसे धन कुबेरों के लिए है)में आरएसएस,मुसलमानों को नागरिकता और मानवाधिकारों से वंचित करती है। विशेष रूप से,मोदी के

दूसरे कार्यकाल के तहत 2019 के बाद से,भारत "मोदीनॉमिक्स" का एक क्रूर स्वरूप भी देख रहा है, जो आज क्रोनी कैपिटलिज्म(जुआड़ी/ दरबारी पूंजीवाद)का भारतीय संस्करण है और अखिल भारतीय स्तर पर पूर्ण रूप से कॉर्पोरेट-भगवा फासीवाद का बहु-आयामी संस्करण है।आज भगवा नव-फासीवाद के तहत देश का समूचा सामाजिक ताना-बाना,अत्यधिक विभाजनकारी नीतियों और साम्प्रदायिक उकसावे के जरिए भयावह विघटन का सामना कर रहा है।

आज इस तथाकथित हिंदुराष्ट्र में लोगों के बीच आपसी द्वेष,नफरत और विभाजन पैदा किया जा है, जिससे दलितों और अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही हैं। राज्य सत्ता के समर्थन से, आरएसएस ने भारत में सभी संवैधानिक और प्रशासनिक संस्थानों के भगवाकरण के अलावा सामाजिक जीवन के हर पहलू को अपने जाल में फंसाने में सफलता हासिल की है। 2019 के मध्य से, यानी मोदी के नेतृत्व में, हिंदुत्व आक्रमण को एक अतिरिक्त गति मिली। दूसरी बार सत्ता में आने के तीन महीने के भीतर, मोदी ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ शुरू होने वाली फासीवादी चालों की एक श्रृंखला शुरू की, जिससे एक ओर कश्मीर के टुकड़े हो गए और

दूसरी ओर इसे जबरन भारतीय संघ में एकीकृत कर दिया गया। संविधान को मानने की शपथ लेने के बावजूद धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करते हुए, मोदी ने स्वयं बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर निर्माण की नींव रखी, जिसके बाद सीएए/एनआरसी के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नागरिकता के अधिकार के मुद्दे पर भेदभाव करना और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की ओर अग्रसर है। अगला कदम नई शिक्षा नीति(NEP 2020) के माध्यम से शिक्षा का भगवाकरण और कॉरपोरेटीकरण,राज्यों पर हिंदी और संस्कृत को थोपना और भारत के इतिहास व संस्कृति को साम्प्रदायिक तथा विकृत बनाना है। बेशक, उनका एजेंडा बहुराष्ट्रीय, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहु-धार्मिक भारत को कॉरपोरेट के प्रभुत्व वाले एक बहुसंख्यक हिंदुराष्ट्र में बदलना है।

मौजूदा स्थिति में,विधानसभा चुनावों में हिंदू वोट-बैंक को मजबूत करने और 2024 के आम चुनाव में भगवा स्वीप के लिए जमीन तैयार करने और " हिंदुराष्ट्र" की घोषणा के लिए, आरएसएस और बीजेपी शासन द्वारा हिंदुत्व पर कोई रोक नहीं लगाकर उसे बेलगाम किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, हाल ही में दिल्ली की आप सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम की अध्यक्षता में धम्म चक्र परिवर्तन के दिन बड़े पैमाने पर दलितों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इस घटना की प्रतिक्रिया में संघी मनुवादी फासिस्ट भाजपा के नेताओं की मांग पर अपने सॉफ्ट हिंदुत्व की नीतियों पर अडिग रहकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनपर दबाव डलवाकर उनसे मंत्री पद वापस ले लिया। उसी प्रकार कुछ दिनों पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरित मानस,मनुस्मृति और संघ परिवार के सबसे सम्मानित गुरु गोलवलकर के Bunch of Thoughts(विचार पुंज) की "समाज में घृणा भड़कानेवाला" कहकर आलोचना की तो उनके खिलाफ जनता दल(यूनाइटेड) और संघ परिवार दोनों मिलकर अभियान चला रहे हैं। नर्म हिंदुत्व की नीति पर चलने का एक और उदाहरण हमारे छत्तीसगढ़ का है जहां पिछले दो माह से फासिस्ट संघी गुंडे,नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर जिले में धर्मांतरित ईसाई अल्पसंख्यकों पर हिसक आक्रमण,धर्म स्थल पर तोड़ फोड़ और आर्थिक सामाजिक बहिष्कार का कार्यक्रम नौकरशाही की मदद से चला रहे हैं।संघ परिवार के मार्गदर्शन में भाजपा के बड़े नेता बकायदा पिछले वर्ष अप्रैल से " रोको, टोको और ठोको" अभियान के माध्यम से नफरत और विभाजन की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे जिसे अब बिना प्रशासन के रोक टोक के अंजाम दिया गया और छत्तीसगढ़ एक नया" कंधमाल" बनने की ओर अग्रसर है।

अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के दौरान आयोजित राज्य के गृह मंत्रियों के तथाकथित चिंतन शिविर में, शाह और मोदी दोनों ने संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक अखिल भारतीय पुलिसिंग को जबरदस्ती थोपने के लिए अपनी बयानबाजी के साथ बहुसंख्यकवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची और 2024 तक प्रत्येक राज्य में एनआईए कार्यालय खोलने की योजना सहित कठोर एनआईए और यूएपीए को और मजबूत करने का कार्यक्रम बनाया है। आतंक से लड़ने के नाम पर, "एक डेटा, एक प्रविष्टि" जैसे कई विचार ", "इस्लामोफोबिया को व्यवस्थित रूप से फैलाने और मुसलमानों को दुश्मन के रूप में चित्रित करने के साथ-साथ एक राष्ट्र, एक पुलिस की वर्दी का एजेंडा भी आगे रखा गया है।

अब इस भगवा आक्रमण की श्रृंखला में नवीनतम चोट, समान नागरिक संहिता और आर्थिक आधार पर आरक्षण हैं। जाहिर है, डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किए गए संवैधानिक रूप से अनिवार्य जाति-आधारित आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक जीवन के सार्वजनिक क्षेत्रों में उच्च जातियों के हमले से उत्पीड़ित जातियों की रक्षा करना था।दलितों,आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का अधिकार,सामाजिक न्याय की दिशा में एक जनवादी अधिकार है।लेकिन,आर्थिक आरक्षण को शामिल करके103वां संवैधानिक संशोधन, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में समर्थन दिया है, मोदी शासन ने जाति-आधारित आरक्षण को कमजोर कर दिया है, जिसका उद्देश्य ब्राह्मणवादी ऊंची जातियों द्वारा अछूत और उत्पीड़ित जातियों के खिलाफ किए गए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना था।अब मध्य प्रदेश में राजपूतों का एक बड़ा संगठन "करणी सेना" ने भोपाल में बड़ी रैली ,आमसभा कर राज्य सरकार के सामने अपने २२ मांगों

(बाकी पेज 32 में)

हिंडनबर्ग के पहले भी अडानी समूह में घोटालों के संकेत मिले थे, पर तब भी चुप्पी थी, आज भी है

विजय शंकर सिंह

हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में, जो अडानी समूह पर, शेल कंपनियों द्वारा समूह में निवेश, मनी लांड्रिंग और स्टॉक मार्केट में ओवरप्राइसिंग सहित कुछ अन्य आरोप लगाए गए हैं, उनकी ओर भारत के भी कुछ पत्रकारों ने, जो आर्थिक मामलों में अध्ययन और रिपोर्टिंग करते रहते हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के पहले भी लिखा है। इनमे, प्रमुख पत्रकार हैं, परंजय गुहा ठाकुरता, रवि नायर और सुचेता दलाल। परंजय गुहा ठाकुरता और रवि नायर ने, राफेल घोटाले पर भी एक बेहद शोधपूर्ण किताब लिखी है, जो उस सौदे की परत दर परत खोल कर रख देती है। परंजय गुहा ठाकुरता को तो, अडानी समूह के बारे में अपनी धोधपूर्ण रिपोर्ट के लिए, अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी और उनका एक लेख, जो अडानी के घपलों और उस समूह द्वारा किए गए वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करता है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली वीकली जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका से हटवा भी दिया गया। अब लेख हटवाने में कौन शामिल था, इस पर सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है और अनुमान लगाना मुश्किल भी नहीं है।

वही पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता, ने ढाई साल बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और कलकत्ता के अंग्रेजी दैनिक अखबार द टेलीग्राफ को अपना एक इंटरव्यू दिया है। उनके खिलाफ मानहानि के एक मामले में, अहमदाबाद की एक अदालत ने एक जुबाबंदी आदेश जारी कर, उनसे कहा था कि, वे ऐसा कुछ भी न बोलें या न लिखें जो अडानी समूह के हितों के विरुद्ध हो। जुबानबंदी का यह आदेश अपने आप में ही, अडानी की सत्ता पर मजबूत पकड़ का संकेत दे देता है। अडानी के बारे में, न कुछ बोलें, न कुछ लिखें, और न कुछ पढ़ें, यह मंशा अदालत की थी या नहीं, यह तो नहीं बता पाऊंगा, पर यह मंशा सरकार की तो है ही, जो अब वह देश की सर्वोच्च पंचायत की हो गई। लोकसभा के स्पीकर ने, जो मुस्कुराते हुए, राहुल गांधी को सदन में, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, बोलने दे रहे थे, ने राहुल के उन प्रश्नों और अंशो को सदन की कार्यवाही से उड़ा दिया, जो प्रधानमंत्री और अडानी के बीच के संबंधों पर थे। बिल्कुल एक आपराधिक गिरोह की मानसिकता से, जो अपराध का कोई सुबूत छोड़ना नहीं चाहता है। पर राहुल ने जो कहा है वह अब अधिकांश के स्मार्टफोन में पड़ा हुआ है।

अंग्रेजी अखबार दे टेलीग्राफ से बात करते हुए, परंजय गुहा ठाकुरता ने कहा, "वे अदालत की अवमानना नहीं करना चाहते हैं, पर वे कुछ तथ्य रखेंगे।" परंजय गुहा ठाकुरता का अध्ययन अर्थशास्त्र में रहा है और वे आर्थिकी और कॉरपोरेट बैंकिंग आदि पर अध्ययन करते रहते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने अडानी के तेजी से बढ़ते आर्थिक साम्राज्य और कारोबार का भी अध्ययन करना शुरू किया। गुहा ठाकुरता ने कहा कि "वह अडानी समूह के भविष्य के बारे में अनुमान लगाने के लिए तैयार नहीं हैं।" और टेलीग्राफ द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने केवल तथ्य बताए हैं। वे आगे कहते हैं, "एक पत्रकार के रूप में मेरी रुचि का क्षेत्र राजनीतिक अर्थव्यवस्था है...। मैं 45 साल से पत्रकार हूं और अब मैं 67 साल का हूं।"

जाहिर है, किसी भी क्षेत्र में जब कोई असामान्य हलचल होती है तो, सजग और सतर्क पत्रकारों की निगाह उसकी ओर स्वाभाविक रूप से पड़ती है। अडानी का भी उदय और विस्तार 2014 के बाद बहुत तेजी से हुआ और इस असामान्य तरक्की ने, एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था का पत्रकार होने के नाते, परंजय का भी ध्यान उधर गया।

अगर देश के कॉर्पोरेट के इतिहास पर कभी कुछ लिखा जाता है तो, अडानी समूह के हैरतअंगेज विकास पर जरूर लिखा जायेगा। आर्थिक इतिहासकार, उन कारणों और उन बाहरी प्रभावों के बारे में भी जरूर लिखेंगे, जिन्होंने इस समूह के अप्रत्याशित विस्तार में उत्प्रेरक और सहायक की भूमिका निभाई है, और उनमें भी, विशेषकर कॉर्पोरेट और सत्ता के गठजोड़ के बारे में। अडानी समूह का उदय, निःसंदेह शानदार रहा है। अडानी ग्रुप के बारे में 20 साल पहले बहुत कम ही लोगों ने सुना था। लेकिन, हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आने तक, वे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी और एशिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। अब, अपनी सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर

गिरने के बाद वह उस स्थिति से नीचे गिर कर, बाइसवे स्थान तक खिसक गए पर, अब फिर थोड़ा ऊपर उठे है। इस प्रकार यदि उन्होंने, शानदार तरीके से विकास किया तो, उनकी गिरावट भी उतनी ही हैरान करने वाली रही है। परंजय अपने इंटरव्यू में बताते हैं, "24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने से पहले, हममें से बहुत कम लोगों ने, जिनमें मैं भी शामिल हूं, का सोचना था कि, अडानी समूह अब आगे नहीं बढ़ेगा।"

इस सवाल पर कि, "अडानी समूह, कई अन्य भारतीय कॉरपोरेट्स से अलग क्या करता है?"

परंजय कहते हैं, "भारतीय अर्थव्यवस्था के इतने सारे क्षेत्रों और खंडों पर अडानी समूह के प्रभुत्व का तरीका और होना, वास्तव में असामान्य है। यह भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह ऑपरेटर है। यह भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट, दोनों ही तरफ, एक दर्जन बंदरगाहों का संचालन करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इसके पास इज़राइल में हाइफ़ा पोर्ट और ऑस्ट्रेलिया में एबॉट पॉइंट है। अडानी निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटरों में से एक है, CIL (कोल इंडिया लिमिटेड) के बाद कोयला खदानों के दूसरे सबसे बड़े ऑपरेटर है; इसकी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में खानें हैं। यह भारत में कोयले के सबसे बड़े आयातक है, एनटीपीसी के बाद, कोयले से बिजली उत्पादन में, दूसरे, सबसे बड़े उत्पादक है.... अदानी समूह 15 साल पहले तराशे और पॉलिश किए गए हीरों का सबसे बड़ा एग्रीगेटर हुआ करता था - लेकिन बाद में यह समूह, इससे अलग हो गया, जतिन मेहता के विनसम डायमंड्स सहित अन्य, जो विनोद अदानी की बेटी (विनोद, गौतम अदानी के भाई हैं) के ससुर हैं, द्वारा घोटाले में लिप्त होने के बाद। जतिन मेहता इस समय देश से बाहर है। विनसम डायमंड्स कभी इनकी सबसे बड़ी गैर-निष्पादित संपत्तियों में से एक है।"

और यह सारी तरक्की और व्यापारिक साम्राज्य विस्तार, 2014 से अब तक के काल खंड का है, यानी वही काल खंड है जिसमे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं।

अडानी समूह के बारे में, परंजय गुहा ठाकुरता ने सबसे पहले कब लिखा था, के सवाल पर, परंजय ने जो कहा, उसे पढ़िए,

"2015 में मेरा लेख कुल मिलाकर उन सामग्रियों का संकलन था जो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में थे।

पहला लेख जिसे कोई एक्सक्लूसिव कह सकता है, अप्रैल 2016 में प्रकाशित हुआ था, जब मैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (EPW) का संपादक था।

मैंने ईपीडब्ल्यू में कई लेख लिखे, जिसमें बिजली के मूल्य निर्धारण के बारे में चर्चा और, अडानी समूह द्वारा तराशे और पॉलिश किए गए हीरा व्यवसाय द्वारा लाभ के दुरुपयोग के आरोप भी शामिल हैं।

जून 2017 में ईपीडब्ल्यू के लिए मैंने जो आखिरी लेख लिखा था, वह एसईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) में बिजली परियोजनाओं से संबंधित नियमों में बदलाव से संबंधित था।"

आगे वह कहते हैं, "इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे सरकार - वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय - 500 करोड़ रुपये से अधिक के सीमा शुल्क की वापसी के लिए एक शिकायत पर कार्रवाई कर रहे थे, कि, बिना पड़ताल के, शुल्क का भुगतान किया गया था या नहीं। यह मामला संसद तक भी पहुंच गया था।"

ईपीडब्ल्यू, एक प्रतिष्ठित मैगजीन है और जब उसमे परंजय गुहा ठाकुरता का लेख छपा तो अडानी समूह असहज हुआ और परंजय को, ईपीडब्ल्यू से इस्तीफा देना पड़ा। इस मामले में परंजय कहते हैं,

"जैसा कि आप जानते हैं, मैंने जुलाई 2017 में इस्तीफा दे दिया था, जब ईपीडब्ल्यू के न्यासी बोर्ड ने कहा कि मुझे अपने नाम से लेख नहीं लिखना चाहिए, हालांकि, मेरे पूर्ववर्तियों ने यह कार्य किया था। मुझे बताया गया कि, वे एक सह-संपादक नियुक्त करने के बारे में सोच रहे थे; कि मैंने एक संस्था की तरह प्रतिष्ठित प्रकाशन की परंपरा को नष्ट कर दिया है। मुझ से कहा गया कि, मैंने प्रकाशक, मुद्रक, लेखक और लेख के संपादक को कानूनी नोटिस का जवाब देने के लिए, एक वकील की निःशुल्क सेवा स्वीकार कर गंभीर अनुचित कार्य किया है और, अंत में, मुझे उस लेख को हटाने के लिए कहा गया और कहा गया कि, जब तक वह लेख, हटा नहीं लिया जाता, तब तक कमरे से बाहर न जाने के लिए भी कहा गया। मैंने अपने एक सहयोगी को बुलाया, लेख को हटा दिया। फिर, कागज का एक टुकड़ा लिया और अपना इस्तीफा लिख दिया।"

आखिर क्या था उस लेख में कि ईपीडब्ल्यू जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका, जो खुद को एक संस्था के रूप में मानती है, एक कॉर्पोरेट पर लिखे गए एक शोधपूर्ण आलोचनात्मक लेख को छापने से डर गई थी। कॉर्पोरेट की जड़ें किस मजबूत सत्ता तक पहुंच रही थी, यह तब भी, किसी से नहीं छुपा था, और अब भी नहीं छुपा है। रस्सी खूंटे के बल पर तनती है!

सवाल पूछा गया, "क्या आपने अडानी समूह पर लिखना जारी रखा ?"

इस पर परंजय गुहा ठाकुरता ने कहा, "ईपीडब्ल्यू द्वारा हटाया गया लेख द वायर (समाचार पोर्टल) द्वारा प्रकाशित किया गया था। मेरे समर्थन में कई लोग सामने आए, जिनमें प्रोफेसर अमर्त्य सेन और प्रसिद्ध विद्वान नोम चॉम्स्की शामिल हैं। बाद में, अडानी समूह पर मेरे लेख, कुल मिलाकर अन्य प्रकाशनों, विशेष रूप से न्यूज़क्लिक में छपे। मैं मई 2018 में न्यूज़क्लिक का सलाहकार बना।"

ईपीडब्ल्यू ने तो फिर उनका लेख नहीं छापा पर अन्य समाचार पोर्टल पर परंजय का लेख छपता रहा।

इन लेखों के कारण, इन पर, अदालतों में मानहानि के मुकदमे दर्ज हुए। इन मुकदमों के बारे में, वे कहते हैं,

"मैं भारत का एकमात्र नागरिक हूं, जिसके खिलाफ गौतम अडानी के नेतृत्व वाली कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने मानहानि के छह मामले दायर किए हैं, जो वर्तमान में कानून की अदालतों में लंबित हैं। इनमें से दो मामले गुजरात के मुंद्रा में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हैं, दो अहमदाबाद, गुजरात की अदालतों में, एक राजस्थान के बारां जिले में और एक दिल्ली में है। सितंबर 2020 में, अहमदाबाद की अदालत ने मुझ पर, मेरे सह-लेखक अबीर दासगुप्ता और प्रबीर पुरकायस्थ के नेतृत्व वाले न्यूज़क्लिक पर एक जुबानबंदी आदेश जारी किया कि हम गौतम अडानी और उनके समूह के हितों के खिलाफ कुछ भी बोल, कह या लिख नहीं सकते।"

वे आगे कहते हैं, "एक लेख था, जिसे मानहानिकारक माना गया था - लेख की सामग्री को चुनौती नहीं दी गई थी। शीर्षक मानहानिकारक माना गया... यह तीन लेखों की श्रृंखला का अंतिम भाग था।"

मुझ पर, मेरे सहयोगियों और न्यूज़क्लिक पर यह आरोप था कि, हमने जनता की नज़र में न्यायपालिका के सम्मान को कम किया है। मामला फिलहाल लंबित है और मैं इस पर और कुछ नहीं कह सकता।

हाल ही में राजस्थान के मामले में, हम में से कई बारां जिले के ग्रामीण न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने जमानत बांड और जमानत बांड के लिए जमानत देने के लिए उपस्थित हुए।

ईपीडब्ल्यू द्वारा हटाए गए लेख को अडानी समूह द्वारा यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि यह मानहानिकारक है। द वायर को चलाने वाली संस्थाओं, मेरे सह-लेखकों और मेरे खिलाफ मामले दायर किए गए थे। यह भुज में एक सिविल कोर्ट और मुंद्रा में एक आपराधिक अदालत में गया। लेकिन अब दोनों मुंद्रा में हैं।"

जब उनसे पूछा गया कि, "जैसा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, क्या आपको गिरफ्तार करने का कोई प्रयास किया गया था? क्या आप जेल गए थे ?"

इस पर परंजय गुहा ठाकुरता ने कहा,

"जनवरी 2021 में, जब महामारी चल रही थी, मुंद्रा में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मेरे खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। मेरे वकील ने तर्क दिया कि यह गैर-जमानती वारंट कानून की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का जिक्र किया जिनमें कहा गया है कि, अगर कोई शख्स कोर्ट में पेश नहीं होता है तो, आप जमानती वारंट जारी कर सकते हैं। अगर वह व्यक्ति फिर भी हाजिर नहीं होता है तो, कोर्ट गैर जमानती वारंट जारी कर सकता है। यह मामला ईपीडब्ल्यू से निकाले गए लेख और बाद में द वायर द्वारा प्रकाशित लेख से संबंधित है। मई 2019 में, लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने से पहले, अडानी समूह ने सभी के खिलाफ मामले वापस ले लिए - द वायर, मेरे तीन सह-लेखक लेकिन मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसके खिलाफ मामला जारी है। मुझे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया।"

हिंडनबर्ग रिसर्च के साथ सहयोग करने के सवाल पर उनका कहना है,

"रिपोर्ट आने से पहले, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। हालाँकि, रिपोर्ट, जिसमें 32,000 शब्द हैं, यदि पुस्तक के रूप में मुद्रित की जाती है, तो 150 पृष्ठों में आ सकती है। इस रिपोर्ट में, मेरे और अबीर दासगुप्ता जैसे स्वतंत्र

पत्रकारों द्वारा किए गए कार्यों के कई संदर्भ उल्लिखित हैं, जिनके साथ मैंने सहयोग किया। लेकिन यह सब वे मैटीरियल और दस्तावेज हैं, जो सार्वजनिक डोमेन में है और उन्हे कोई भी देख और पढ़ सकता है।"

परंजय गुहा ठाकुरता की मुलाकात भी गौतम अडानी से हुई। इसके बारे में वे कहते हैं, कि, "मैं गौतम अडानी से दो बार मिला - मई 2017 में मुंबई में, और फिर फरवरी 2021 में। हाल ही में मेरी उनसे टेलीफोन पर लंबी बातचीत हुई। लेकिन इनमें से हर मौके पर मैं उनसे इस शर्त पर मिला कि यह ऑफ द रिकॉर्ड होगा। मैंने उन वार्तालापों को रिकॉर्ड नहीं किया। प्रत्येक बातचीत के दौरान, टेलीफोन कॉल को छोड़कर मेरे साथ और लोग भी थे। एक पूर्व सहयोगी 2017 में मेरे साथ था और 2021 में, कमरे में हम पांच थे, जिनमें गौतम अडानी और मेरी पत्नी शामिल है। पहली बैठक लगभग एक घंटे तक चली, जबकि दूसरी, एक घंटे और 55 मिनट तक चली। फोन कॉल करीब 15 मिनट तक चली।"

"मुलाकात मेरे कहने पर हुई थी. दूसरा मेरे वकील आनंद याग्निक के द्वारा इस उम्मीद के साथ तय की गई थी कि, अदालत के बाहर समझौता हो सकता है। लेकिन वैसा नहीं हुआ। आखिरी फोन कॉल मेरी ओर से मामलों को वापस लेने का अनुरोध था। पर वह प्रतिबद्ध नहीं थे। मामले अभी भी लंबित हैं।"

शीर्ष कंपनियों और बड़े समूहों के खिलाफ लेख लिखने पर परंजय को अन्य अदालती मामलों का सामना भी सामना करना पड़ा है। इनके बारे में वे बताते हैं,

"कई कॉरपोरेट्स ने लीगल नोटिस भेजे हैं लेकिन असल में कोई मुझे कोर्ट तक नहीं ले गया। कानूनी नोटिस दोनों अंबानी भाइयों के नेतृत्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों द्वारा भेजे गए थे। सहारा के सुब्रत राय ने भी मुझे नोटिस भेजा पर वे कभी कोर्ट नहीं ले गए। पर इन मामलों का मुझ पर और मेरी जिंदगी पर असर पड़ता है। अनावश्यक समय बरबाद होता है और खर्चे भी होते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं, इनसे (इन लेखों के माध्यम से कॉर्पोरेट की अनियमितता उजागर करने से) कुछ अलग करता तो मेरा उत्तर 'नहीं' में होता।

आज जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, देश के स्टॉक मार्केट में भूचाल आया है, अडानी के शेयर आधे से भी कम कीमत पर रह गए हैं, एसबीआई, एलआईसी जैसी कई वित्तीय संस्थान जिन्होंने अडानी के शेयर खरीदे हैं, नुकसान उठाने की ओर है, दुनिया भर की क्रेडिट एजेंसियां और वित्तीय संस्थान अडानी के इस अचानक हुए पराभव से सशंकित है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर बांग्लादेश तक, यह समूह संदेह के घेरे में है तो आरएसएस और बीजेपी इसे देश पर हमला बता रहे हैं। कमाल की सरकार है और कमाल की गवर्नेंस। अडानी के शेयर उठे या गिरे, इससे अडानी पर लगे आरोप खत्म नही हो जाते हैं। शेयरों का उठना गिरना तो उस आरोपों का परिणाम है। आरोप है, शेल कंपनियों से पैसा लेना। इसे मनी लांड्रिंग भी कहा जाता है। ED प्रवर्तन निदेशालय, जिसने, बेहद कम धनराशि की मनीलांड्रिंग के आरोप में, केरल के पत्रकार, सिद्दीक कप्पन को जेल भेजा था, अब कॉमा में है। सरकार संसद में काका हाथरसी और दुष्यंत कुमार की कविताएं सुना रही है, पर अडानी का नाम तक नहीं ले रही है, जांच पड़ताल की कौन कहे।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार

रितांश आजाद

अपने आप को मज़बूत सरकार घोषित करने वाले एक डॉक्यूमेंटरी से इतना डर गए कि उसे ब्लॉक कर दिया गया । मोदी सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंटरी फिल्म "India: The modi question" को यूट्यूब से ब्लॉक करवा दिया साथ ही ट्विटर को भी इसके लिंक हटाने को कहा । बताया जा रहा है कि इस डॉक्यूमेंटरी फिल्म में तथ्यों के साथ दिखाया गया है कि कैसे 2002 में कराए गए गुजरात दंगों के तार सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए थे। ये दंगे भयावह थे और कई लोग इन्हें सीधे शब्दों में जनसंहार कहते हैं , इनमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए जिसमें ज़्यादातर मुसलमान थे । ये बात सालों से कई पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता कहते रहे हैं कि इसमें सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी/आरएसएस का हाथ था । खैर , हम कहते हैं कि अगर सरकार और मोदी इतने पाक साफ हैं तो अपनी बात रखिए न जनता के सामने ,एक फिल्म से इतना क्यूँ डर लगता है इस छप्पन इंच के सीने वाली सरकार को ? साफ है डर इसीलिए लगता है क्यूंकी सत्ता में बैठा व्यक्ति गुनहगार है ! फिल्म की स्क्रीनिंग हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय में की गई , ये फिल्म जेएनयू , जामिया और राजस्थान विश्विद्यालय में

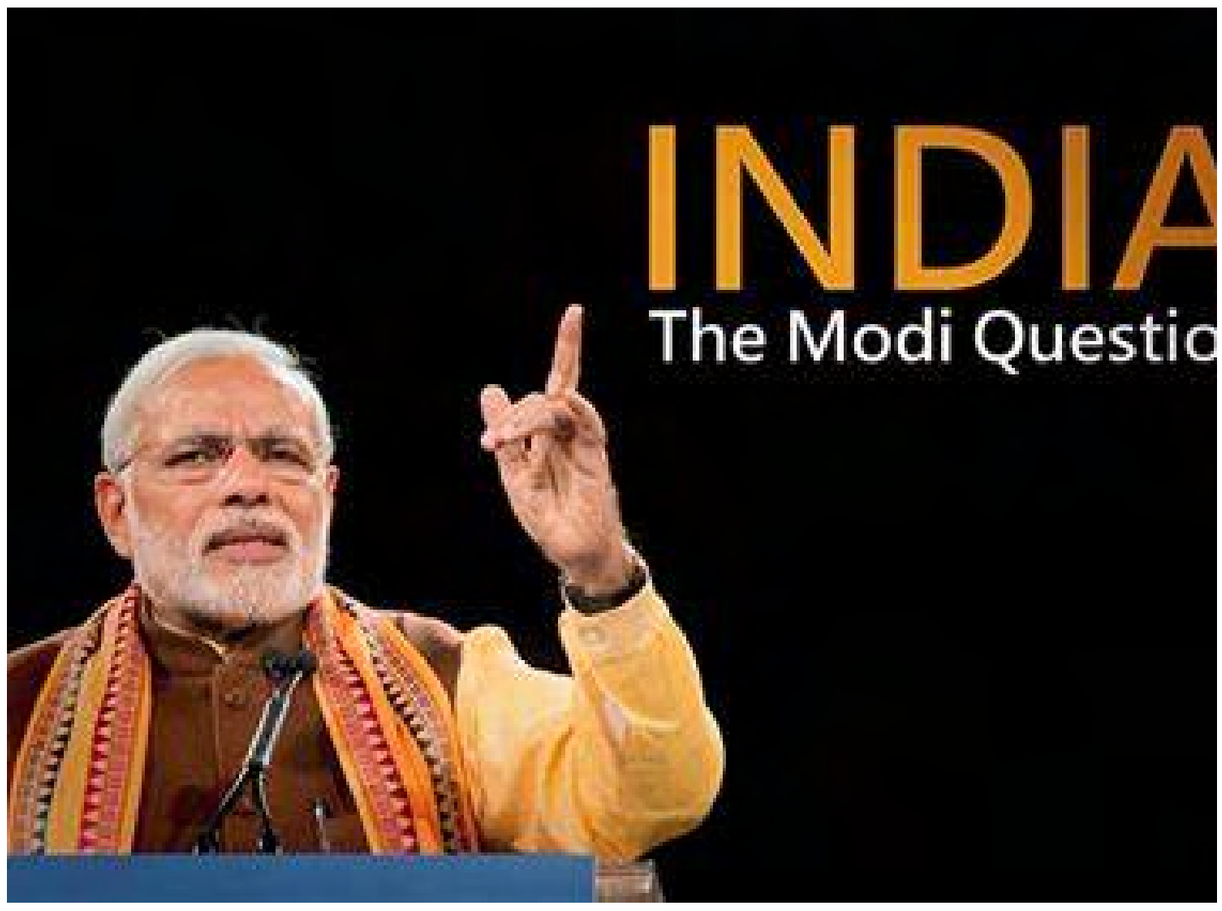

भी खुले आम दिखाई जाएगी । साथ ही वामपंथी संगठन इसे केरल में भी कई जगह दिखा रहे हैं । सभी युवाओं से अपील है कि इसका लिंक खोजकर इसे देखें और इसे गली मोहल्लों और कॉलिजों में खुलकर दिखाएं । साथ ही इसपर खुलकर बहस करें । हम इस सरकार की तानाशाही नहीं सहेंगे , इनके गुनाहों का पर्दाफाश करेंगे और इस देश की गंगा जमुनी तहज़ीब की रक्षा करेंगे !

को रखा है जिसमें उन्हें आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान करने की मांग शामिल है।मध्य प्रदेश के भाजपा सरकार के मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने उन्हें उचित आश्वासन दिया है।इस तरह जहां आरक्षण को निजी क्षेत्रों/ कॉरपोरेट घरानों के तहत लागू करने की पहल करनी है वहां,संघ परिवार के मार्गदर्शन में उसे पूरी तरह खत्म करने का आयोजन किया जा रहा है।

इसी संदर्भ में जाति उन्मूलन आंदोलन के साथ समान विचार वाले संगठनों ने मिलकर 6 दिसंबर से 25 दिसंबर तक तीखे होते आरएसएस नवफासीवाद के खिलाफ देशव्यापी राजनीतिक- सांस्कृतिक अभियान चलाया था। जाहिर है, दिसंबर 6, भगवा गुंडों द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ-साथ भारतीय संविधान के निर्माता अम्बेडकर की पुण्यतिथि का प्रतीक है, जबकि 25 दिसंबर वह दिन है जब अम्बेडकर ने आरएसएस फासीवाद के वैचारिक आधार मनुस्मृति को जलाया था। मुस्लिम-विरोधी, दलित-विरोधी, किसान, मजदूर, आम मेहनतकश जनता और पितृसत्तात्मक घोर महिला विरोधी संघी मनुवादी फासीवाद के खिलाफ हम मेहनतकश वर्ग, देशभक्त,जनवादी,धर्मनिरपेक्ष ,प्रगतिशील अवाम और तमाम उत्पीड़ितों से अपील करते हैं कि आरएसएस के वैचारिक आधार मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ उठ खड़े हों तथा इसकी कब्र खोदने और एक सच्चे जनवादी भारत के निर्माण के लिए,क्रांतिज्योती सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख,ज्योतिबा फुले,पेरियार,शहीद भगत सिंह और बाबासाहेब आंबेडकर के सपनों के भारत का निर्माण करने के लिए जाति उन्मूलन आंदोलन को आगे बढ़ाएं।

छत्तीसगढ़ में संघी फासिस्ट गिरोह की रोको, टोको और ठोको को उसकी औकात दिखानी है

सपन

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्र बस्तर में पिछले तीन माह से भी अधिक समय से फासिस्ट संघ परिवार का अल्पसंख्यक मसीही समाज के खिलाफ तांडव चल रहा है लेकिन भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार अपने नर्म हिंदुत्व के लाइन पर चलकर मूक दर्शक बने बैठी है। पिछले चुनाव के पहले, १५ साल से राज्य में काबिज भाजपा सरकार ,अपने मार्गदर्शक आरएसएस के निर्देशों पर आदिवासी से आदिवासी को लड़ाने का खूनी खेल खेलने के साथ साथ ,वनवासी कल्याण आश्रम सहित संघ परिवार के आनुषांगिक संगठनों की मदद से आदिवासियों के हिंदूकरण में जोर शोर से जुटी थी।२०१८ में जनता द्वारा फासिस्ट भाजपा का सूपड़ा साफ कर कांग्रेस को सत्ता सौंपा गया।लेकिन कांग्रेस भी कॉरपोरेट परस्त नीतियों और राम वनगमन पथ,कौशल्या मंदिर एवम गाय गोबर की राजनीति के जरिए संघ परिवार के वैचारिक आधार मनुवादी हिंदुत्व को खाद पानी दे रही है।

बस्तर में धुर दक्षिणपंथी फासिस्ट हिंदूवादियों की विशेष मुहिम की शुरुआत तब हुई जब गत वर्ष २६ अप्रैल को आरएसएस द्वारा निर्मित "जनजाति सुरक्षा मंच" की पहल से नारायणपुर जिले सहित कई स्थानों पर "रोको, टोको और ठोको" रैली व सभा का आयोजन कर ग्रामीणों को धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ नफरती भाषण के जरिए भड़काया गया। उस दिन भाजपा नेता भोजराम नाग, रुपसाय सलाम,नारायण मरकाम आदि ने धर्मांतरित ईसाई आदिवासियों के खिलाफ डी लिस्टिंग करने ,उन्हे सरकारी सुविधाओं से वंचित करने और सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करने की मांग की।तब से लगातार ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ लोगों को भड़काते हुए गत अक्टूबर से संघ परिवार हरकत में आया।बस्तर के कांकेर,कोंडागांव और नारायणपुर जिले के विभिन्न गांवों में तब से नफरत की आग सुलग रही है।मसीही समुदाय के पादरीगण तथा चर्च जाने वाले लोग जिनमें महिलाएं

और बच्चे ज्यादा हैं को लगातार मारा पिता जा रहा है कि वे ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लें नहीं तो गंभीर परिणाम होंगे।मसीही समुदाय का ग्रामों में सामाजिक आर्थिक बहिष्कार किया गया और उन्हें बलपूर्वक बिना घरेलू सामान के गांवों से बाहर खदेड़ दिया गया।

लोग गांव से भाग कर फरसगांव (कोंडागांव) में शरण ले रहे थे, उनको प्रशासन द्वारा जबरन गांव वापस भेजा गया। उनमें से ग्राम चिंगनार के लोगों के साथ फिर मार पीट होने की खबर आई। रात को ही पुरुष लोग अपनी सुरक्षा के लिए गांव से निकल कर जंगल में छुप गए थे, पर दूसरे दिन सुबह महिलाओं के साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट हुई है। उनका सामान भी बाहर निकाल कर फेंका गया है। पटवारी और सरपंच महिलाओं को प्राथमिक उपचार के लिए ले गए थे, और फिर वापस गांव में ही छोड़ दिया है। थाने में रिपोर्ट लिखवाने से भी मना कर रहे हैं। इनके साथ १८ दिसंबर से लगातार मारपीट हो रही है। सवाल ये है कि जब ये लोग खुद घर–बार छोड़ कर भाग के नारायणपुर/ फरसगांव आए हैं, इन्हे उसी भयावह माहौल में वापस क्यों धकेला जा रहा है? क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि पहले गांव में समझौता करवाए,

माहौल को शांत बनाए, फिर ही इन्हें वापस भेजे और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले? या फिर केवल अपनी जिम्मेदारी से हाथ धोना चाहती है?नारायणपुर में २० ग्रामों के ५०० ईसाई अल्पसंख्यकों ने शरण लिया है।पहले प्रशासन ने इन्हे खुली जगह रुकवा दिया था,विरोध करने पर नारायणपुर इंडोर स्टेडियम में इन्हें रुकवाया गया है। अपने गर्म कपड़ों,बिस्तर,कंबल,भोजन की व्यवस्था सब मसीही समाज स्वयं कर रहा है,प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है।२५ दिसंबर को क्रिसमस के दिन बेनूर थाने के अंतर्गत ग्रामों में ईसाई समुदाय पर हमला हुआ।पिछले तीन माह में ५०० से अधिक नामजद शिकायतें आरएसएस/ भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज की गई हैं लेकिन पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी रही।

२ जनवरी को अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा परवान चढ़ी जब हथियारबंद संघी गिरोह ने नारायणपुर जिले के बंगलापारा के सैक्रेड हार्ट चर्च पर हमला कर दिया।मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक सदानंद सहित सात पुलिस कर्मी इस घटना में घायल हो गए।इस घटना के बाद पुलिस ने बाध्य होकर एक भाजपा नेता समेत ११ लोगों को गिरफ्तार किया है।मजे की बात है कि २ जनवरी को नारायणपुर जिले के भाजपा अध्यक्ष रूपसाय सलाम के नेतृत्व में नारायणपुर में ईसाइयों के खिलाफ भड़काऊ सभा का आयोजन किया गया।जिला कलेक्टर अजीत वसंत ने पत्रकारों से कहा कि रुपसाय सलाम और अन्य भाजपा नेता,रैली / सभा को शांतिपूर्ण बनाए रखने का वादा किए हैं।लेकिन करीब २००० लोग नारायणपुर में इकठ्ठे होकर विश्वपीठ स्कूल और सैक्रड हार्ट चर्च पर हमला कर उसे तहस नहस कर दिया।

जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस फिर से एक बार धर्मनिरपेक्षता को समझे और हिंदुत्ववादियों के पिच पर खेलना छोड़ दे।कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व की नीति से उसे तनिक भी लाभ नहीं होगा क्योंकि लाभ तो फासिस्ट संघ परिवार को जाना है। जो जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकार को भटकाने और कॉरपोरेट घरानों की लूट को सुगम बनाने के लिए मनुवादी हिंदुत्व का जहर आदिवासी समाज के भीतर घोल रही है।कांग्रेस सरकार अगर जनता का दिल जीतना चाहती है तो उसे कांग्रेस के भीतर और पुलिस प्रशासन में छुपे और खुले मनुवादी हिंदुत्व के पैरोकारों को निबटाना पड़ेगा।लेकिन अपने वर्गचरित्र के चलते कांग्रेस,ये फासीवाद विरोधी पोजीशन नहीं लेगी।सर्व आदिवासी समाज और अन्य आदिवासी संगठनों को चाहिए कि वे आरएसएस के इस तथाकथित हिंदुराष्ट्र के अभियान को समझें,उससे दूरी बनाए और आदिवासी समाज में चेतना पैदा करें कि आदिवासी कभी हिंदू नहीं थे।आरएसएस के घोषित संविधान मनुस्मृति के अनुसार आदिवासी,दलित ,महिला आदि सब शुद्र हैं जिन्हे मानव का दर्जा नहीं प्राप्त है।जल, जंगल जमीन पर अधिकार,मूलभूत मानव अधिकार,जीने की आजादी के लिए आदिवासियों की लड़ाई को भटकाना आदिवासियों के दुश्मन,कॉरपोरेट घरानों के दलाल संघी मनुवादी फासिस्ट ताकतों की चाल है,धर्मांतरित ईसाई उनके अपने हैं।मूल लड़ाई कॉरपोरेट घरानों और उनके दलाल आरएसएस नवफसिवादियों से जनता की है।वामपंथी जनवादी संघर्षशील संगठनों को चाहिए कि वे पूरे देश और छत्तीसगढ़ में एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर व्यापक संघी फासीवाद विरोधी लड़ाकू मोर्चा का निर्माण करें अन्यथा कल बहुत देर हो जाएगी।

कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के मंच रेड स्टार को पढ़ें और वर्ग संघर्ष के हित में प्रचार-प्रसार करें।

जुड़ने और मदद करने के लिए संपर्क करें:

मोबाइल नंबर: 9425560952

ऑफिस फोन: 011-41056622

ईमेल: redstarhindi@gmail.com

आर्थिक मदद के लिए:

गूगल पे नंबर: 8714336875

यूपीआई: kabeerkatlat@okicici

जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ।
प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशनार्थ

उत्तराखण्ड के सीमांत पर बसे ऐतिहासिक-सांस्कृतिक-पर्यटक नगर जोशीमठ के अस्तित्व के लिये और अपने जीवन व भविष्य के प्रति आशंकित लोगों का संघर्ष जारी है ।

हमारे पुरखे सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से ही इस क्षेत्र नहीं बसे हहोंगे। प्रकृति ने इसे और भी इतनी नेमतें दी थी, इसी वजह से लोग सैकड़ों वर्षों में देश के बहुत से हिस्सों से एक बार यहां आए और यहीं के होकर रह गए ।

अभी की ही हमारी स्मृति में, पिछले पचास से सौ वर्षों में हमने बहुत से प्रकृति प्रेमियों, आध्यात्मिक रुचि के लोगों को यहां आने के बाद यहीं का होते हुए देखा है ।

देश दुनिया से आज जो समर्थन, प्रेम, सहानुभूति जोशीमठ को मिल रही है,उसके मूल में इस नगर की सबको अपना बना लेने की विशेषता भी है ।

अपने इसी प्यारे नगर को बचाने की हमारी लड़ाई थी और है ।

लेकिन लोभ और स्वार्थ की वशीभूत सरकार- सत्ताओं ने इस नगर के अस्तित्व पर मंडराते खतरे को न देखा और ना ही सुना ।

23 दिसंबर 2003 को हमने इसी आशंका के चलते एक पत्र तत्कालीन राष्ट्रपति को दिया था । उसमें हमने जय प्रकाश कम्पनी की विष्णुप्रयाग परियोजना का उदाहरण देते हुए कहा था कि यदि जोशीमठ के नीचे इसी तरह सुरंग आधारित परियोजना (जो तब प्रस्तवित भर थी) बनाई जाएगी तो इस नगर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा । राष्ट्रपति के यहां से सम्बंधित परियोजना निर्मात्री कम्पनी को सम्बोथित पत्र भी आया, जिसमें हमारी आशंकाओं का समाधान करने को कहा गया । लेकिन परियोजना निर्माता कंपनी ने हमारी आशंकाओं और राष्ट्रपति के पत्र- दोनों को ही तवज्जो नहीं दी।

तब आंदोलन ही विकल्प था, जो हमने किया ।

2005 में परियोजना की जन सुनवाई के समय भी हमने वही सारी आशंकाएं जोर-शोर से रखीं । कोई उत्तर नहीं मिला । हमने उस जनसुनवाई का विरोध किया क्योंकि कंपनी के पास जनता के सवालों और आशंकाओं का कोई जवाब नहीं था।

फिर परियोजना के शिलान्यास का जबर्दस्त विरोध हुआ । जिसकी परिणति हुई कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को तमाम तैयारियों के बावजूद अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा । जोशीमठ में परियोजना का शिलान्यास करने में विफल रहने पर देहरादून में शिलान्यास कर दिया गया । और शिलान्यास का पत्थर जोशीमठ की छाती में गाड़ दिया गया । दो साल लगातार परियोजना बंद करने के लिए आंदोलन चलता रहा ।, 24 दिसंबर 2009 को जब इस परियोजना की सुरंग में टी बी एम के ऊपर बोल्डर गिरने से, मशीन फंस गयी और उस जगह से 600 लीटर पानी प्रति सेकंड निकलने लगा. यह जोशीमठ के स्रोतों का पानी था. सुरंग से बहते पानी से आसन्न खतरे को भांपते हुए जोशीमठ में लम्बा आंदोलन चल । आंदोलन के परिणामस्वरूप तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, जिला प्रशासन की मध्यस्थता में हमारा परियोजना निर्माता कंपनी एनटीपीसी समझौता हुआ. समझौते के तहत एनटीपीसी को न सिर्फ जोशीमठ के पेयजल की दीर्घकालिक व्यवस्था करनी थी अपितु हमारे घर-मकानों के बीमा भी करना था, ताकि यदि मकानों को नुकसान हो तो भरपाई भी हो सके ।

समझौते की यह मांग इसलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि उसी समझौते के तहत एक हाई पावर कमेटी को परियोजना की समीक्षा भी करनी थी । किन्तु वह कमेटी कभी बैठी ही नहीं ।

इस तरह जोशीमठ के भविष्य व अस्तित्व पर तभी प्रश्नचिन्ह लग गया था ।

एनटीपीसी और सरकार का बार-बार कहना है कि परियोजना की सुरंग जोशीमठ से दूर है । हमारा सवाल है कि बाईपास सुरंग कहां है ? उसकी स्थिति जोशीमठ के नीचे ही है और वह विस्फोटों के जरिये ही बनी है । लोगों को आशंका है कि उसमें कुछ दिन पहले तक लगातार विस्फोट किये जा रहे थे जो जोशीमठ में आज हो रहे भू धंसाव का मुख्य कारण हैं । शेष कारणों ने इस प्रक्रिया को तीव्र करने में योगदान किया है ।

अब जब जोशीमठ के अधिकांश घरों में दरारें आ चुकी हैं और कुछ भूगर्भ वैज्ञानिकों ने भी जनता की ही तरह, बड़ी आपदा की आशंका व्यक्त की है, तब अपना जीवन, सम्पत्ति व भविष्य की सुरक्षा की चिंता ने जनता को पुनः सड़कों पर ला दिया है ।

यदि सरकार व प्रशासन समय रहते जनता की सुन लेते और कार्यवाही करते तो यह नौबत नहीं आती ।

पिछले 14 महीने से लगातार इसपर बोलते-लिखते-लड़ते रहने के बावजूद सरकार नहीं जागी और आज हालात काबू से बाहर हैं ।

हमें उम्मीद थी कि आज जब दुनिया भर में जोशीमठ को लेकर लोग चिंतित हैं, तब सरकार कुछ संवेदनशील होकर तथा राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठकर कार्य करेगी ।

इसी उम्मीद के साथ कल तमाम पुराने मतभेद भुलाकर , जनता के तमाम आक्रोश के बावजूद संघर्ष समिति ने शांतिपूर्ण बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार किया ।

संघर्ष समिति ने जनता के व्यापक हितों व आपदा की व्यापकता के मद्देनजर पांच बिंदु रखे थे. इन बिंदुओं पर उत्तराखंड सरकार के आपदा प्रबंधन सचिव से पहले ही चर्चा की जा चुकी थी ।

हमारे द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष रखे गए पांच बिंदु :

1.एनटीपीसी की परियोजना पर पूर्ण रोक की प्रक्रिया प्रारंभ हो

2.हेलंग-मारवाड़ी बाईपास पूर्णतया बन्द हो ।

3.एनटीपीसी को पूर्व में हुए 2010 के समझौते को लागू करने को कहा जाय, जिससे घर-मकानों का बीमा करने की बात प्रमुख है ।

4.जोशीमठ के समयबद्ध विस्थापन, पुनर्वास एवं स्थायीकरण के लिये,जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति को शामिल करते हुए एक अधिकार प्राप्त उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हो ।

5.जोशीमठ में पीड़ितों की तत्काल आवास भोजन व अन्य सहायता हेतु एक समन्वय समिति बने जिसमें स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाय ।लोगों के घर मकानों का आंकलन करते हुए मुआवजा व उनके स्थाई पुनर्वास की प्रक्रिया तुरन्त प्रारंभ की जाए ।

इन बिंदुओं पर ही मुख्यमंत्री के साथ बातचीत व निर्णय होना था । विस्तृत चर्चा क्योकि आपदा सचिव से हो चुकी थी, इसलिए हमारी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में

इनपर निर्णय हो । इसीलिए मुख्यमंत्री के ओ एस डी से भी सुबह ही बात हो चुकी थी । उन्हें हमारी मांगें के संदर्भ में ब्रीफ किया जा चुकी था ।

देहरादून से जोशीमठ मुख्यमंत्री के आने का यही कारण भी लगता था कि वे ठोस निर्णय की घोषणा करने ही आ रहे हैं । किंतु हमारी प्रार्थना का यही उत्तर मिला कि देहरादून जाकर बैठक कर ही तय करेंगे ।

संघर्ष समिति ने इसपर यही निर्णय लिया है कि जब तक सभी विस्थापित होने वालों के साथ एक समान न्याय नहीं हो जाता व जब तक उपरोक्त मांगों पर ठोस जमीनी कार्यवाही नहीं दिखती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा ।

संघर्ष समिति सरकार से पुनः यह मांग / अपेक्षा / प्रार्थना करती है कि इस आपदा की घड़ी में विशाल ह्रदय से ,मानवीय दृष्टिकोण से, दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर पीड़ित जनता के हित मे सबको साथ लेकर चलते हुए कार्य करे । हमारा मानना है कि सिर्फ प्रशासनिक मशीनरी के भरोसे, इस बड़ी आपदा से नहीं निपटा जा सकता । पूर्व की आपदाओं का भी यही सबक है । हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने और सहयोग करने का प्रस्ताव पुनः पुनः दोहराते हैं ।

इस नगर के व इसके निवासियों के भविष्य के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार शीघ्र कार्यवाही करे ।

2023-24 का बजट दरबारी/ जुआड़ी बड़े पूंजीपतियों के हित में "अमृत काल" सुनिश्चित करने के लिए जनता को छल रहा है

"समावेशी विकास" और "भारत के विकास प्रक्षेपक में नई ऊर्जा के संचार" पर बयानबाजी के बीच, ऊंची आवाज में मुफ्त की रेवड़ी के पूरे पैकेज की घोषणा के साथ, मोदी सरकार का 2023-24 का बजट, 2022-23 के बजट की ही तरह, एक धुर दक्षिणपंथी कॉर्पोरेट समर्थक एजेंडे का दुहराव है और उन्ही नीतियों की मजबूती प्रदान करता है।

यह अडानी जैसे सबसे भ्रष्ट जुआड़ी कॉरपोरेट पूंजीपति के लिए एक "अमृत काल" की परिकल्पना करता है, जो अपने सट्टा साम्राज्य के अचानक फटने के बाद कुछ दिनों के भीतर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर की पायदान से गिरकर सिर्फ 15 की स्थिति में आ गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूजी निवेश परिव्यय में 33 प्रतिशत की वृद्धि की बजट अनुमानों में लगभग 10 लाख करोड़ रु, मुख्य रूप से पीपीपी परियोजनाओं के माध्यम से कॉर्पोरेट अरबपतियों के खजाने में बढ़ोतरी की योजना है। क्योंकि मोदी सरकार एक 'कॉर्पोरेट-सहायक' होने के नाते, पहले से ही कॉर्पोरेट सटोरियों को 'विकास' का कार्य सौंप चुकी है। चूंकि कॉरपोरेट घरानों की रोजगारोन्मुख उत्पादक गतिविधियों में कम दिलचस्पी है, जैसा कि अडानी जैसे कॉरपोरेट्स के संचालन से स्पष्ट है, मोदी सरकार ने उदार कर, श्रम और पर्यावरण नियमों का कॉरपोरेट हित में प्रभावी ढंग से उपयोग किया।और यह करते हुए उसने इस विशाल परिव्यय को सट्टेबाजी, रियल एस्टेट, श्रम का अत्यधिक शोषण और प्रकृति की एकमुश्त लूट की ओर धकेल दिया। यह बजट, कॉर्पोरेट अरबपतियों में धन के एकत्रीकरण को भयानक स्तर तक बढ़ा देगा। बजट में उन 23 करोड़ लोगों के लिए कुछ भी नहीं है जो "बेहद गरीब" वर्ग से संबंधित है।

उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा आवंटन का मामला लें, जो कि पिछले 4 वर्षों में सबसे कम है, यानी 2022-23 की तुलना में 32 प्रतिशत कम है । यह 89400 रुपए से रु. 60000 करोड़ हो गया है।और 21-22 में वास्तविक व्यय 98468 रुपये की तुलना में 2023-24 के परिव्यय में कमी 60 प्रतिशत से अधिक आती है। ऐसे समय में जब भारत का 95 प्रतिशत से अधिक कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्रों पर निर्वाह करता है और सब जानते हैं कि कॉर्पोरेट के नेतृत्व वाले विकास को "रोजगार रहित विकास" कहा जाता है, भारत अब 50 वर्षों में सबसे भीषण बेरोजगारी का सामना कर रहा है। इसलिए, आवश्यकता के बरक्स, मनरेगा के लिए अब नगण्य राशि का आबंटन हुआ है। वास्तव में मौजूदा सक्रिय जॉब कार्डों के लिए 100 दिनों का काम प्रदान करने के लिए भी लगभग न्यूनतम आवंटन 3 लाख करोड़ की जरूरत है। अब तक देश के केवल 10 प्रतिशत सक्रिय श्रमिकों को ही 100 दिन का रोजगार मिल पाता रहा है और अब आवंटन में भारी गिरावट को देखते हुए स्थिति दयनीय होने वाली है। इसी तरह, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में की गई घोषणाएं केवल जुमले हैं , उनमें कोई सार नहीं है।

दूसरी ओर, रक्षा के लिए धन आवंटन में कोई कमी नहीं है, जो पिछले साल के 5.25 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से बढ़कर 2023-24 के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपये हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस आवंटन में से कुल 1.62 करोड़ रुपये सीधे हथियार निर्माता बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) को नए हथियार, विमान और अन्य सैन्य हार्डवेयर आयात करने के लिए दिए जा रहे हैं। जबकि प्रत्यक्ष करों पर कई छूट मध्यम और अभिजात/ कुलीन वर्गों को खुश करने के लिए प्रदान की जा रही है।लेकिन जीएसटी और अन्य अप्रत्यक्ष करों को सुव्यवस्थित करने के कारण , करों का भारी बोझ अधिकांश आम जनता को ही बिना किसी कमी के ढोना है। इस बीच, दुनिया में सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स दर वाले देश के रूप में भारत के कद में कोई बदलाव नहीं आया है।

बहरहाल 2023-24 के बजट ने मध्यम वर्ग के तुष्टीकरण के साथ-साथ कॉर्पोरेट अति-अमीरों के लिए "अमृत

काल" की परिकल्पना की है। जिसमें कामकाजी और उत्पीड़ितों सहित अधिकांश जनता को पूरी तरह से हाशिए पर रख दिया गया है। अर्थव्यवस्था की पूरी बागडोर कारपोरेट-सटोरिए पूंजीपतियों के हाथ में है, जो नवफासीवादी भगवा शासन के साथ नापाक गठजोड़ में हैं। ये नव फासीवादी भगवा शासक, संकट की स्थिति में कॉरपोरेट घरानों को उबारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जैसा कि हाल के अडानी प्रकरण से स्पष्ट है। दूसरी ओर देश की आम जनता को भयावह गरीबी और बर्बादी के मुहाने पर खड़ा कर दिया गया है।

इस संदर्भ में, भाकपा (माले) रेट स्टार मजदूरों, किसानों , शोषितों तथा सभी प्रगतिशील जनवादी ताकतों से अपील करती है कि वे 2023-24 के बजट के वास्तविक सार का शिद्दत से पर्दाफाश करें जो भारतीय और विदेशी कॉर्पोरेट पूंजी के हितों की सेवा करता है और आम जनता की पीठ पर भारी बोझ डालकर उन्हे तबाह करता है।

महासचिव
भाकपा (माले) रेड स्टार
1 फरवरी 2023

ब्राजील में "नवफासीवादी तख्तापलट" नव-फासीवाद के तहत पिस रहे देशों के लिए आंखे खोलने वाला होना चाहिए

अक्टूबर 2022 के राष्ट्रीय चुनाव में "धांधली" होने का दावा करते हुए, हज़ारों गली के गुंडे, जो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति, नवफासीवादी बोलसोनारो के समर्थक हैं, उन्होंने वैश्विक मीडिया द्वारा प्रसारित वीडियो के अनुसार, 8 जनवरी को देश की संसद, राष्ट्रपति महल और सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोलकर कलाकृतियों को नष्ट कर दिया और संसद को अंदर से आग लगाने का प्रयास किया। स्पष्ट रूप से, और जैसा कि स्वयं राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने आरोप लगाया था, यह पुलिस की मिलीभगत के साथ हुआ जो केवल दर्शक के रूप में थे जबकि बोल्सोनारो समर्थक फासीवादी गुंडों ने राज्य के सर्वोच्च कार्यकारी कार्यालयों पर आक्रमण किया था। यह 6 जनवरी, 2021 की याद दिलाता है जब फासीवादी दंगाइयों ने 2020 के अमेरिकी चुनाव के प्रमाणन को रोकने के अपने प्रयास में अमरीकी राजधानी मुख्यालय पर धावा बोल दिया था, जिसने नवफासीवादी ट्रम्प की हार की घोषणा की थी।

इससे पहले, कई हज़ारों 'बोलसोनारिस्तस' या बोल्सनारो के हिंसक समर्थकों को घूमते देखा जा सकता था और यहां तक कि सैन्य बैरकों में इकट्ठा होकर सत्ता पर कब्जा करने के लिए ब्राजील की सेना को आहवान रहे थे। संक्षेप में, वे मुसोलिनी और हिटलर के "ब्लैक शर्ट" और "ब्राउन शर्ट" जैसे अर्धसैनिक "फासीवादी तूफानी दस्तों" के समान आचरण कर रहे थे। हालांकि बोल्सोनारो, जो अब फ्लोरिडा ,अमरीका में सुरक्षित रूप से बस गए हैं, ने दंगों में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है।लेकिन स्वतंत्र पर्यवेक्षकों के अनुसार, ब्राजील में 'तख्तापलट' के प्रयास की राजनीतिक जिम्मेदारी खुद बोलसोनारो की है।

बेशक, बोल्सनारो के समर्थकों की बर्बरता पर गहरी "चिंता" व्यक्त करने वाले विश्व नेताओं के साथ मोदी का बयान काफी आकर्षक है। हालाँकि,सबसे मजेदार बात है कि ट्रम्प, बोल्सनारो और मोदी के बीच बहुत समानता दिखती है, क्योंकि तीनों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा 'एक ही साँचे में ढले' के रूप में पेश किया जा रहा है। तीनों के नेतृत्व वाले शासनों को विशिष्ट नवफासीवादी और बहुसंख्यकवाद को थोपने वाला धुर दक्षिणपंथी नवउदारवाद के मानक वाहक के रूप में जाना जाता है। क्योंकि, अपने अपने देश में ठोस स्थिति के आधार पर, ट्रम्प और बोल्सोनारो के नव फासीवाद का वैचारिक आधार ईसाई इंजीलवाद था तो भारतीय शासको के लिए, यह मनुवादी-हिंदुत्व है।

बोल्सोनारो और ट्रम्प दोनों के प्रति मोदी का जो लगाव है, वह अपने व्यक्तित्व को जनता के समक्ष महान प्रमाणित करने में या व्यक्ति पूजा करवाने के प्रदर्शन में दिखता है। बाकी दोनों की तरह उन्हें भी इस विषय में विशेषज्ञता प्राप्त है।मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान ये साफ तौर पर दिखता है। मई 2019 में मोदी के फिर से चुने जाने के बाद भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड में बोल्सनारो मुख्य अतिथि थे। इसी तरह, ट्रम्प ने फरवरी

2020 के दौरान जब भारत का दौरा किया था तब देश में COVID के बारे में संक्रमण बढ़ रहा था और व्यापक चिंता व्याप्त थी। इन दो मौकों पर आधिकारिक भारतीय प्रतिक्रिया से तीनों नवफासीवादी शासकों के बीच घनिष्ठता और अंतरंगता का खुलासा हुआ है।

जबकि दुनिया के सभी क्षेत्रों के नेता बोल्सनारो के फासीवादी गुंडों द्वारा किए गए 'तख्तापलट' की निंदा करने के लिए आगे आए हैं, भारतीयों के रूप में, हम अपने देश में वर्तमान नवफासीवादी अंधकारमय परिस्थिति को नज़रअंदाज नहीं कर सकते , जहां शासन की बागडोर आरएसएस द्वारा नियंत्रित की जाती है,जो कि दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फासीवादी संगठन है। वास्तव में, बोल्सनारो और ट्रम्प के इवेंजेलिकल " तूफानी दस्ते(स्टॉर्म ट्रूपर्स) ," आरएसएस की तुलना में कम प्रभावशाली हैं , जो सैकड़ों गुप्त और खुले संगठनों के माध्यम से भारत में सड़क और राज्य सत्ता दोनों को नियंत्रित करने वाले संघ परिवार का नेतृत्व करता है, जो समाज के पूरे सूक्ष्म और स्थूल क्षेत्रों में व्याप्त है। . न केवल न्यायपालिका सहित नागरिक प्रशासन बल्कि सेना में भी इसका जाल फैला हुआ है। विशाल कॉर्पोरेट शक्ति के समर्थन के साथ, धुर दक्षिणपंथी आर्थिक अभिविन्यास के साथ, इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कॉर्पोरेट मीडिया पर नियंत्रण है। भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और बौद्धिक क्षेत्रों पर इसके नियंत्रण की भी काफी चर्चा है।

अमेरिका की ठोस ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार,सबसे भ्रष्ट कॉरपोरेट पूंजी के चहेते नव फासीवादी ट्रम्प और बोल्सोनारो का वैचारिक आधार ईसाई इंजीलवाद है।वहीं इनके भारतीय समकक्षों का वैचारिक आधार है सबसे अमानवीय ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था।जिसकी पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति है जिसे आरएसएस ने 1949-50 की अवधि के दौरान भारत के संविधान के रूप में सामने रखा था । मनुस्मृति के अनुसार, दलित जो भारतीय मजदूर वर्ग का प्रमुख हिस्सा है, महिलाओं के साथ-साथ अमानवीय दर्जा प्राप्त है। आरएसएस हिंदुराष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर पागलों की तरह दौड़ लगा रहा है। मुसलमानों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करना और उनसे 'द्वितीय श्रेणी के नागरिक' के रूप में व्यवहार करना भी बदस्तूर जारी है। इस संदर्भ में, भारत में 2024 का आम चुनाव निर्णायक होगा क्योंकि उसके बाद का वर्ष आरएसएस का शताब्दी वर्ष है। इसलिए, इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, भारत के सभी मेहनतकश और उत्पीड़ित लोगों के साथ-साथ सभी प्रगतिशील-जनवादी ताकतों के लिए दक्षिण अमेरिका का कद्दावर देश और दुनिया के पांचवें सबसे बड़े देश ब्राजील की घटनाओं से सबक लेने का यही सही समय है। .

पी जे जेम्स
महासचिव
भाकपा (माले) रेड स्टार
नई दिल्ली
10/01/2023

पार्टी की अपील : भाकपा (माले) रेड स्टार के सेंट्रल पार्टी फंड कलेक्शन को सफल बनाएं

कामरेड और दोस्तों,

दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फासीवादी संगठन आरएसएस अब भारत में राज्य सत्ता की बागडोर संभाल रहा है। यह भारत को हिंदुराष्ट्र में बदलने की दिशा में एक व्यवस्थित और लगातार आक्रमण में लगा हुआ है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, अल्पसंख्यकों, दलितों और महिलाओं में असुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए अत्यधिक विभाजनकारी नीतियों और लोगों के बीच आपसी नफरत की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुसलमानों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करने के प्रयास जोरों पर हैं, जबकि आर्थिक आरक्षण की आड़ में जातिगत आरक्षण को कमजोर करते हुए दलितों को उनके लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य न्यूनतम लोकतांत्रिक अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। इस भगवा एजेंडे से पूरी तरह से जुड़ी हुई अति दक्षिणपंथी नवउदारवादी कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों को लोगों पर थोपा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ अरबपतियों के हाथों में संपदा का अभूतपूर्व संकेन्द्रण होता है, जो एक ही समय में अधिक से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी की ओर धकेलता हुए भारत को 'वैश्विक गरीबी के गढ़' के रूप में परिवर्तित करता है।

इस कारपोरेट भगवा फासीवाद की अभिव्यक्तियाँ, जो अंततः एक छोटे से उच्च-अभिजात वर्ग, कारपोरेट अरबपतियों के हितों की पूर्ति करती हैं, अनेक हैं।जैसे कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, कश्मीर को तोड़ना और भारतीय संघ में इसका जबरन एकीकरण, मोदी द्वारा स्वयं राम मंदिर की नींव रखना, बेशर्मी से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करना, सीएए. समान नागरिक संहिता, भगवाकरण और एनईपी 2020(नई शिक्षा नीति) के जरिए शिक्षा के कॉरपोरेटीकरण के माध्यम से मुसलमानों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनाना, कॉर्पोरेट समर्थक श्रम संहिता, कठोर कृषि कानून और पर्यावरण नियम को थोपना जो कॉर्पोरेट की सेवा करते हैं, आलोचकों और राजनीतिक विरोधियों पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए उनका दमन करना ,देश के बहुराष्ट्रीय स्वरूप को बदलने के लिए संधीय ढांचे विरोधी आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक पुलिस और भाषा नीतियों के एक पूरे सेट को जनता पर जबरन थोपना आदि । जनता के दुश्मन ये फासीवादी, एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय और बहु- धार्मिक भारत को एकात्मक, बहुसंख्यक हिंदुराष्ट्र में बदलने में लगे हुए हैं। लोग अब तक की सबसे भयानक स्तर की बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि का सामना कर रहे हैं, जबकि देश की कीमती सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण किया जा रहा है और औने -पौने दामों पर कॉर्पोरेट फाइनेंसरों को बेच दिया गया है। साथ ही मेहनत से अर्जित सभी लोकतांत्रिक अधिकारों और कल्याणकारी उपायों को छीन लिया गया है।

इसी सन्दर्भ में भाकपा (माले) रेड स्टार की केंद्रीय समिति ने पार्टी की 12वीं कांग्रेस में अपनाए गए राजनीतिक प्रस्ताव के आधार पर आरएसएस नव फासीवाद के सभी रूपों के खिलाफ चौतरफा हमला करने का संकल्प लिया है. और जैसा कि 2024 का आम चुनाव करीब आ रहा है, आरएसएस /बीजेपी राज्य और सड़क दोनों की सत्ता पर अपने नियंत्रण के साथ हिंदुत्ववादी बुलडोजर चलाते हुए इसे जीतने की दिशा में एक पागल गति से आगे बढ़ रहे हैं। ताकि आरएसएस द्वारा अपने शताब्दी समारोह की ओर बढ़ते हुए हिंदूराष्ट्र के अपने अंतिम लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में इसे एक कदम के रूप में उपयोग किया जा सके।

इस नाजुक मोड़ पर, सभी समान विचारधारा वाली ताकतों के साथ एकजुट होकर आरएसएस के नव फासीवाद को हराने का बीड़ा उठाते हुए भाकपा (माले) रेड स्टार ,मजदूर वर्ग और सभी उत्पीड़ितों को सत्तारूढ़ व्यवस्था के खिलाफ उनकी आजीविका और जीवन के अधिकार को बरकरार रखते हुए संगठित करने में लगी हुई है। कारपोरेट-भगवा ताकतों को सीधी चुनौती देने वाले इस बहुमुखी कार्य में पार्टी को पूरी तरह मेहनतकशों और शोषित पीड़ित व्यापक जनता पर और उन सभी पर निर्भर रहना होगा जो फासीवाद और कॉरपोरेटकरण के खिलाफ हैं। इसलिए केंद्रीय समिति सभी से अपील करती है कि वे फरवरी 2023 के दौरान पार्टी द्वारा घोषित धन संग्रह अभियान का तहेदिल से समर्थन और सहयोग करें।

आप अपना योगदान पार्टी के बैंक खाते में भेज सकते हैं: CPI(ML) रेड स्टार दिल्ली-110059 यूनियन बैंक नवादा शाखा, A/C No. 510101002779667 (IFSC UBIN0913120) या इस अपील के साथ आपसे संपर्क करने वाले हमारे साथियों को भेज सकते हैं।

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ,
पी जे जेम्स
महासचिव
भाकपा(माले) रेड स्टार
1फरवरी 2023

छत्तीसगढ

20 जनवरी को रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित पीयूसीएल के राज्य स्तरीय सम्मेलन में शिरकत करते हुए पार्टी के साथी

मनुवादी हिंदुत्व का प्रतिरोध और जाति का विनाश पर जनसभा संपन्न लखन सुबोध के नेतृत्व में जाति उन्मूलन आंदोलन राज्य समन्वय समिति गठित

रायपुर,२२ जनवरी २९२३. रायपुर छत्तीसगढ़ के वृंदावन हॉल में जाति उन्मूलन आंदोलन की ओर से एक जन कन्वेंशन का आयोजन किया गया।कन्वेंशन की अध्यक्षता गुरुघासीदास सेवादार संघ के अध्यक्ष और प्रख्यात वामपंथी चिंतक लखन सुबोध ने की।जाति उन्मूलन आंदोलन के केंद्रीय कमिटी सदस्य और क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच (कसम) के महासचिव तुहिन ने " जाति उन्मूलन आंदोलन को आगे बढ़ाएं,आरएसएस के वैचारिक आधार मनुवादी हिंदुत्व का प्रतिरोध करें" नामक आधार पत्र को प्रस्तुत किया।प्रमुख वक्ताओं में पूर्व विधायक और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा (CMM) के अध्यक्ष जनक लाल ठाकुर,जन संघर्ष मोर्चा के संयोजक प्रसाद राव और अखिल भारतीय क्रांतिकारी महिला संगठन(AIRWO) की राज्य संयोजक हेमा भारती शामिल थे।संचालन अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा(AIKKS) के सचिव तेजराम विद्रोही ने किया।

आभार जाति उन्मूलन आंदोलन (CAM) के रायपुर संयोजक हेमंत टंडन ने किया।डॉक्टर बिप्लब बंदोपाध्याय ने " नफस नफ्स कदम कदम" नामक जन गीत प्रस्तुत किया। परिचर्चा में आलोक प्रेमानंद,डॉक्टर ईश्वरदीन,प्रताप सिंह,शोभाराम गिलहरे, उषा (AIRWO),टंडन कुमार साहू,सविता जांगड़े,वसीम(AIRSO),टिकेश,बसंत साहू(CMM), सौरा(केंद्रीय कमिटी सदस्य आदिवासी भारत महासभा), पुनूराम घृतलहरे व टी आर खूंटे ने हस्तक्षेप किया।कन्वेंशन में छत्तीसगढ़ में जाति उन्मूलन आंदोलन छेड़ने के लिए १६ सदस्यीय राज्य समन्वय समिति का गठन किया गया।समिति के राज्य संयोजक के रूप में लखन सुबोध निर्वाचित हुए।कन्वेंशन ने "फासिस्ट संघ परिवार के मार्गदर्शन में बस्तर में आदिवासियों का जबरिया हिंदूकरण और ईसाई अल्पसंख्यकों पर दमन के खिलाफ ,छत्तीसगढ़ को धुर दक्षिणपंथी आरएसएस द्वारा कंधमाल बनाने के षड्यंत्र में मूक दर्शक बनी कांग्रेस सरकार के खिलाफ तथा हमलों के शिकार अल्पसंख्यकों के पुनर्वास व सुरक्षा के लिए प्रस्ताव के साथ आदिवासी से आदिवासी को लड़ाने वाली संघी फासिस्ट गुंडों पर अंकुश लगाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया।इसके साथ ही"राज्य में अंतर्जातीय एवम अंतरधार्मिक विवाह हेतु अभियान चलाने,जातिगत खाप पंचायत/ सामाजिक बहिष्कार जैसे जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं का विरोध तथा धीरेंद्र शास्त्री जैसे ढोंगी बाबाओं जो चमत्कार , मनुस्मृति के आधार पर दलितों,आदिवासियों,महिलाओं,अल्पसंख्यकों के प्रति नफ़रत फैलाते हैं का पर्दाफाश के साथ अंधश्रद्धा निर्मूलन के पक्ष में प्रस्ताव" पारित किया गया।सभा में दुनिया की मेहनतकशों के महान नेता लेनिन और छत्तीसगढ़ में १८५७ के महाविद्रोह के अमर शहीद गेंद सिंह को उनके स्मरण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया।

वक्ताओं ने कहा कि 1935 में बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा था कि भारत में अमानवीय जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंके बिना कोई लोकतांत्रिक समाज नहीं बन सकता।इसके लिए उन्होंने भारतीय जनता को दो दुश्मनों से लड़ने को कहा था - एक ब्राम्हणवाद तो दूसरा पूंजीवाद ।शहीद भगत सिंह ने भी ब्रिटिश साम्राज्य(गोरे अंग्रेज) को उखाड़ फेंकने के साथ साथ उसकी दलाल भारतीय पूंजीवाद(काले अंग्रेज) से भी लोहा लेने को कहा था। आज की तारीख में हम देखते हैं कि ब्राम्हणवाद,आरएसएस के वैचारिक आधार मनुवादी हिंदुत्व का रूप लेकर आज के पूंजीवाद,जिसे अंबानी - अडानी जैसे धनकुबेरों का कॉरपोरेट राज कह सकते हैं का अनुगत / पैरोकार बना हुआ है।इसीलिए आज इस पर चिंतन करने की जरूरत है कि एक सच्चा लोकतांत्रिक समतावादी समाज बनाने के लिए मनुवादी हिंदुत्व का प्रतिरोध और जाति उन्मूलन आंदोलन क्यों इतना जरूरी है।वक्ताओं ने तमाम तरक्की पसंद,अमन पसंद अवाम से अपील की कि आइए इस पर विचार करने के लिए हम साथ साथ बैठते हैं ताकि एक साथ कारवां को जाति विनाश के लिए आगे बढ़ा सकें। जनसभा में सर्वसम्मति से घोषणा किया गया कि हम चार्वाक/ लोकायत ,गौतम बुद्ध,कबीर,रैदास,गुरुनानक,गुरु घासीदास,नारायण गुरु,आयंकाली,पेरियार,बाबासाहब आंबेडकर और शहीदे आज़म भगत सिंह के आधुनिक वारिस हैं और एक जातिविहीन, धर्मनिरपेक्ष,वर्गविहीन,पितृसत्त से मुक्त,वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित एक शोषण हीन समतावादी समाज बनाने के लिए संघर्ष करेंगे।कन्वेंशन में राज्य के संघर्षशील संगठनों के साथियों ने भागीदारी की।

हेमंत टंडन,पुनुराम धृतलहरे
जाति उन्मूलन आंदोलन,छत्तीसगढ़

संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने, हर प्रकार के भेदभाव और असमानता समाप्त करने, लूट और शोषण के खिलाफ संघर्ष करने और संघी मनुवादी फासिस्ट ताकतों के खिलाफ मोर्चा बनाने के उद्देश्यों को लेकर गठित छत्तीसगढ़ जनसंघर्ष मोर्चा की बैठक इंडियन काफी हाऊस,भिलाई में 25 जनवरी को संपन्न हुई ।

26 जनवरी को किसानों ने निकाली किसान तिरंगा ट्रैक्टर रैली
सभी फसलों के लिए एमएसपी की क़ानूनी गारंटी मांगा
राजिम और नवापारा नगर का किया भ्रमण

संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के देशव्यापी आह्वान सभी किसानों को उनके सभी फसलों या उत्पादों जैसे धान, गेंहू, सब्जी, फल, दूध आदि का बारहवों महीने चाहे सरकार खरीदे या व्यापारी खरीदे सभी जगह न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके । हर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य, हर फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य संदेश के साथ गरियाबंद जिले के किसान अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के बैनर तले 26 जनवरी को सुबह 11.30 से कृषि उपज मंडी राजिम में एकत्रित हुए जहाँ से दोपहर 1.00 बजे किसान तिरंगा ट्रेक्टर रैली निकाली गई जो फिंगेश्वर-राजिम, राजिम-रायपुर, राजिम- छुरा मुख्य मार्ग होते हुए राजिम और नवापारा नगर का भ्रमण किया जहाँ से वापस कृषि उपज मंडी पहुंच कर सभा की गई।

सभा में किसान तिरंगा ट्रैक्टर रैली आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के सचिव एवं छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संयोजक मंडल सदस्य तेजराम विद्रोही ने कहा कि सभी फसलों और सभी किसानों को पूरे साल न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारण्टी मिल सके यह सभी किसानों का मूलभूत अधिकार है। इसके लिए गांव गांव से किसानों को संगठित कर संवैधानिक रूप संघर्ष करके ही अपने अधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार न्यूनतम वेतनमान और अधिकतम खुदरा मूल्य का क़ानून है उसी प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी गारंटी होना आवश्यक है।

सभा को किसान मजदूर संघर्ष समिति राजपडाव मैनपुर के अध्यक्ष अर्जुन नायक, छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संयोजक मंडल सदस्यगण जागेश्वर जुगनू चन्द्राकर, पारसनाथ साहू, डॉ ईश्वर दान आसिया, गजेंद्र कोसले, अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के सदस्यगण हेमंत कुमार टंडन, लखबीर सिंह, उत्तम कुमार, ललित कुमार, समर्थन में आए अनुसूचित जाति महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती धनेश्वरी डांडे, जे पी बघेल आदि ने संबोधित किया। सभा का संचालन एम आर डांडे ने किया तथा अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन लाल साहू ने आभार व्यक्त किया।

ट्रैक्टर तिरंगा रैली में दीनू राम, छन्नू राम, हिरामन साहू, विनोद यदु, ओम साय साहू, लक्ष्मण चन्द्राकर, जागेश साहू, चेमन धीवर, डेनिश कुमार, चोवराम, कांशी राम, भुनूराम, मनोज कुमार, जहुर राम, पवन कुमार, नंद कुमार, रमेश कुमार, कृष्णा साहू, जितेन्द्र साहू, सोमनाथ साहू, अजय कुमार, नोहर, शेषनारायण साहू, रेखुराम, पदुमलाल, सोमन यादव, नंदू ध्रुव, शेषनारायण चन्द्राकर, बालचंद, नरेश ध्रुव, जीवन साहू, रिंकू पटेल,लाला साहू,गिरधर साहू, आदेश कुमार, महेंद्र कुमार सहित बेलटुकरी, लफंदी, राजिम, पितईबंद, श्यामनगर, परतेवा, सिर्रिकला, पुरैना, कुम्हि, दुतकैय्या, धमनी, अरण्ड, किरवई, मैनपुर, राजपडाव आदि गांव से बड़े पैमाने पर किसान सम्मिलित हुए।

सरकार मेहनतकशों के साथ खिलवाड़ करना बंद कर मांग पूरी करे
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की अनिश्चित कालीन धरना चौथे दिन जारी

संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के देशव्यापी आह्वान सभी किसानों को उनके सभी फसलों या उत्पादों जैसे धान, गेंहू, सब्जी, फल, दूध आदि का बारहवों महीने चाहे सरकार खरीदे या व्यापारी खरीदे सभी जगह न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके । हर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य, हर फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य संदेश के साथ गरियाबंद जिले के किसान अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के बैनर तले 26 जनवरी को सुबह 11.30 से कृषि उपज मंडी राजिम में एकत्रित हुए जहाँ से दोपहर 1.00 बजे किसान तिरंगा ट्रेक्टर रैली निकाली गई जो फिंगेश्वर-राजिम, राजिम-रायपुर, राजिम- छुरा मुख्य मार्ग होते हुए राजिम और नवापारा नगर का भ्रमण किया जहाँ से वापस कृषि उपज मंडी पहुंच कर सभा की गई।

सभा में किसान तिरंगा ट्रैक्टर रैली आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के सचिव एवं छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संयोजक मंडल सदस्य तेजराम विद्रोही ने कहा कि सभी फसलों और सभी किसानों को पूरे साल न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारण्टी मिल सके यह सभी किसानों का मूलभूत अधिकार है। इसके लिए गांव गांव से किसानों को संगठित कर संवैधानिक रूप संघर्ष करके ही अपने अधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार न्यूनतम वेतनमान और अधिकतम खुदरा मूल्य का क़ानून है उसी प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी गारंटी होना आवश्यक है।

सभा को किसान मजदूर संघर्ष समिति राजपडाव मैनपुर के अध्यक्ष अर्जुन नायक, छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संयोजक मंडल सदस्यगण जागेश्वर जुगनू चन्द्राकर, पारसनाथ साहू, डॉ ईश्वर दान आसिया, गजेंद्र कोसले, अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के सदस्यगण हेमंत कुमार टंडन, लखबीर सिंह, उत्तम कुमार, ललित कुमार, समर्थन में आए अनुसूचित जाति महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती धनेश्वरी डांडे, जे पी बघेल आदि ने संबोधित किया। सभा का संचालन एम आर डांडे ने किया तथा अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन लाल साहू ने आभार व्यक्त किया।

ट्रैक्टर तिरंगा रैली में दीनू राम, छन्नू राम, हिरामन साहू, विनोद यदु, ओम साय साहू, लक्ष्मण चन्द्राकर, जागेश साहू, चेमन धीवर, डेनिश कुमार, चोवराम, कांशी राम, भुनूराम, मनोज कुमार, जहुर राम, पवन कुमार, नंद कुमार, रमेश कुमार, कृष्णा साहू, जितेन्द्र साहू, सोमनाथ साहू, अजय कुमार, नोहर, शेषनारायण साहू, रेखुराम, पदुमलाल, सोमन यादव, नंदू ध्रुव, शेषनारायण चन्द्राकर, बालचंद, नरेश ध्रुव, जीवन साहू, रिंकू पटेल,लाला साहू,गिरधर साहू, आदेश कुमार, महेंद्र कुमार सहित बेलटुकरी, लफंदी, राजिम, पितईबंद, श्यामनगर, परतेवा, सिर्रिकला, पुरैना, कुम्हि, दुतकैय्या, धमनी, अरण्ड, किरवई, मैनपुर, राजपडाव आदि गांव से बड़े पैमाने पर किसान सम्मिलित हुए।

राजस्थान

क्रांतिकारी नौजवान भारत सभा (RYFI) और PUCL जयपुर के साथियों ने PUCL के जयपुर ऑफिस में बीबीसी की फिल्म India: the modi question की स्क्रीनिंग की। साथियों को बता दें कि इस फिल्म को देखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है ,लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि जैसे ये प्रतिबंधित है। इसीलिए हमारा कहना है कि इसे खुले आम दिखाया जाना चाहिए। फिल्म के बाद मोदी सरकार की 2002 के गुजरात दंगों में सीधी भागीदारी और आज देश भर में RSS/BJP के द्वारा बनाए जा रहे सांप्रदायिक माहौल पर चर्चा हुई । स्क्रीनिंग में मुख्य तौर पर युवा साथी मौजूद थे और सभी ने इस मुद्दे पर मुखरता से राय रखी। इसके बाद हमने राजस्थान केन्द्रीय यूनिवर्सिटी के उन छात्रों से मुलाकत की जिन्हें 14 दिन के लिए सिर्फ ये फिल्म मोबाइल पर देखने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। छात्रों का कहना है कि ऐसा ABVP के छात्रों द्वारा हंगामा किये जाने के बाद किया गया । हम इस तानाशाही भरे फैसले के खिलाफ हैं और हमारी प्रशासन से ये अपील है कि तुरंत इस आदेश को खारिज किया जाए और उन्हें कॉलिज में फिर से आने की अनुमति मिले । अगर छात्र कॉलिज प्रशासन के इस तानाशाही भरे फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं ।

झारखंड

भाकपा माले रेड स्टार के नेता व कार्यकर्ता गुमला उपायुक्त के समक्ष मजदूर किसानों के शोषण के विरुद्ध धरना कार्यक्रम करते हुए

बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती पर जल जंगल जमीन बचाओ और जाति आधारित जनगणना कराओ के नारों से गूंज उठा डाल्टनगंज।

बिहार के लेनिन के नाम से मशहूर क्रांतिकारी नेता जगदेव प्रसाद की जयंती पर जन संग्राम मोर्चा के जुगल पाल, भाकपा माले के बीएन सिंह, भाकपा माले(रेड स्टार) के वशिष्ठ , हूल झारखंड क्रांति दल के चंद्रधन महतो और ओबीसी मोर्चा के रवि पाल ने जगदेव प्रसाद चौक स्थित जगदेव प्रसाद की मूर्ति पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया फिर पदयात्रा करते हुए भगत सिंह चौक पहुंच कर शहीद ए आजम भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए कचहरी पहुंचकर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। संयुक्त रूप से सभी संगठन के लोगों ने जल जंगल जमीन बचाओ के नारे का समर्थन किया और लोगों से जन जंगल जमीन बचाने की लड़ाई में कूदने का आह्वान भी किया इसके साथ ही गैर बराबरी समाप्त करने के लिए जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया और जाति आधारित आरक्षण लागू करने का मांग रखा। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी की मांग सभी संगठन के लोगों ने किया।

जगदेव प्रसाद के प्रसिद्ध वाक्य 100 में 90 शोषित हैं 90 भाग हमारा है के नारे भी नुक्कड़ सभा में लगाए गए। सभी संगठन के नेताओं ने किसानों की बदतर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए किसानों की आय दोगुनी करने की मांग को प्रमुखता से उठाया और कहा कि सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी लेकिन यह बात पूरी तरह से जुमला साबित हुई है। बिजली विभाग द्वारा किसानों के ऊपर किए जा रहे अत्याचार के मुद्दे को भी सभी संगठनों ने प्रमुखता से उठाया और 2020 में लाएं गए बिजली बिल संबंधित नए कानूनों को रद्द करने का मांग भी उठाया इसी प्रकार सभी संगठन ने 4 लेबर कोड का भी विरोध किया और इन कानूनों को मजदूर विरोधी कानून बताया। झारखंड क्रांति मोर्चा के अध्यक्ष शत्रुघ्न शत्रु ने नुक्कड़ सभा स्थान पर पहुंचकर सभी संगठन के सभी मांगों को अपना समर्थन दिया उसके बाद पैदल मार्च करते हुए सभी संगठन के लोग छह : महान चौक पहुंचकर पदयात्रा को समाप्त किया। इसी के साथ कल दिनांक 3 फरवरी से इन सभी मुद्दों को जनता तक पहुंचाने और सभी मुद्दों से जनता को अवगत कराने के लिए पूरे पलामू में पदयात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा का नेतृत्व जन संग्राम मोर्चा , भाकपा माले, भाकपा माले (रेड स्टार), हूल झारखंड क्रांति दल और ओबीसी मोर्चा करेगी।

6 फरवरी को धज्वा पहाड़ संघर्ष मोर्चा के घटक संगठन भाकपा माले रेड स्टार एंव जनसंग्राम मोर्चा के साथियों द्वारा पहाड़ खनन माफिया सुरज सिंह शिवालिका कम्पनी का पार्टनर एंव उसके सहयोगी पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा जो पूर्व मे हार्ड कोर माओवादी था को आक्रोशित ग्रामीणों के साथ पहाड़ पर घेर कर जबाव तलब कर भगाया गया। यह घटना पलामू जिला के पांडू प्रखंड के बरवाही ग्राम की है|

पंजाब

गत 19 जनवरी को मानसा पंजाब में रल्ला विखे गांव के एक दबंग जातिवादी परिवार द्वारा मामूली विवाद को लेकर एक दलित परिवार पर जानलेवा हमला किया गया।ऊंची जाति के गुंडों ने दलितों पर लाठी से हमला करते हुए उस परिवार की एक दलित महिला पर चार पहिया वाहन चढ़ा दिया।जिससे उस महिला की मृत्यु हो गई।मृतका के शरीर को न जलाते हुए इलाके के दलितों ने जनवादी संगठनों के साथ मिलकर मानसा में जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष जंगी प्रदर्शन किया।लगातार आठ दिन तक आंदोलन चलता रहा।जन संगठनों के दबाव में पुलिस प्रशासन ने जान से मारने से लेकर SC/ST अत्याचार अधिनियम की धारा भी अपराधियों पर लगाया।साथ ही प्रशासन ने पीड़ित परिवार को चार लाख रुपए मुआवजा राशि देते हुए तीन कातिलों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया ।इस आंदोलन में कॉमरेड लाभ सिंह और कॉमरेड केवल सिंह के नेतृत्व में मजदूर अधिकार आंदोलन ,पंजाब ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

उत्तर प्रदेश

17 जनवरी को बलिया उत्तरप्रदेश में जाति उन्मूलन आंदोलन और वर्ग संघर्ष के बीच संबंध पर अध्ययन शिविर

26 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा(एसकेएम) बलिया के नेतृत्व में विभिन्न किसान संगठनो के नेतृत्वकारी साथियों द्वारा बलिया डीएम कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया गया जिसमें अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा की तरफ से का0 कन्हैया, राजाराम, परशुराम वर्मा, श्रीनिवास राम और श्रीराम भारती शामिल रहे।

आजमगढ़ मंदुरी हवाई अड्डा के विस्तारीकरण पर फौरन रोक लगाए सरकार और आंदोलन के नेता राजीव यादव समेत अन्य साथियों के खिलाफ पुलिसिया दमन बंद हो

-भाकपा माले रेडस्टार

बलिया 3 फरवरी। भाकपा माले रेडस्टार के उत्तर प्रदेश राज्य समन्वयक का0 कन्हैया ने सरकार से जनभावनाओं का सम्मान करते हुए आजमगढ़ मंदुरी हवाई अड्डा के विस्तारीकरण पर फौरन रोक लगाने की तथा आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस करवाई को बंद करने की मांग की है।

का0 कन्हैया ने कहा कि आजमगढ़ मंदुरी हवाई अड्डा बिस्तारीकरण से प्रभावित गांवों की सम्पूर्ण जनता हवाई अड्डा बिस्तारीकरण के खिलाफ है। वैसे भी आज तक मंदुरी हवाई अड्डा पर एक जहाज तक नहीं उतरा है। जिस हवाई अड्डा पर आजतक एक जहाज तक नहीं उतरा हो, उसके बिस्तारीकरण का जनहित में कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हवाई अड्डा बिस्तारीकरण के लिए जमीन -मकान से आमजन को बेदखल कर भूमि अधिग्रहण करने की कार्यवाही पर फौरन रोक लगना चाहिए। उन्होंने ने आगे कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत लोगों की बिना इजाजत एवं सहमति लिए हवाई अड्डा बिस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण करना कानून का उल्लंघन है।

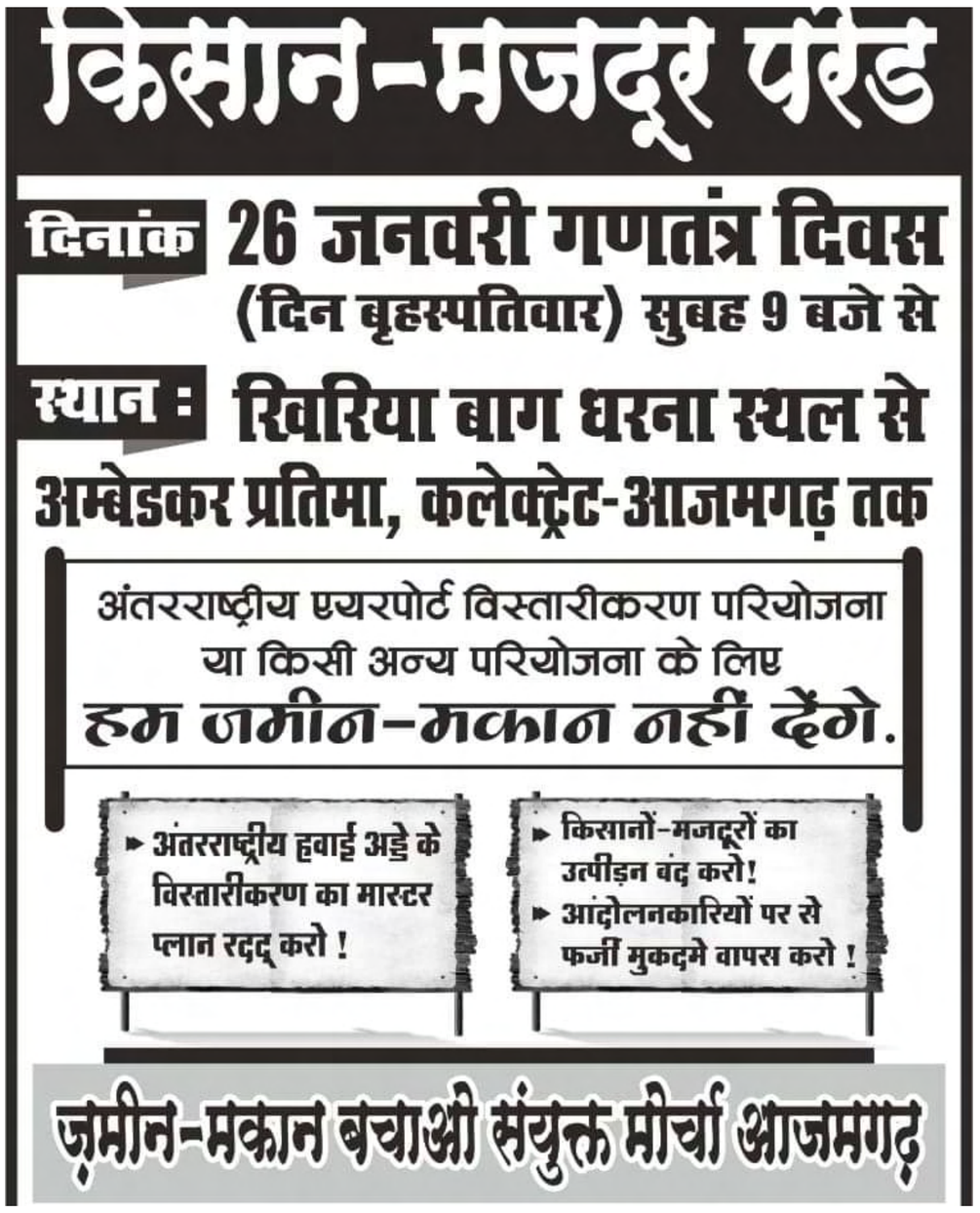

भाकपा माले रेडस्टार राज्य समन्वयक ने कहा कि एक तरफ मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कारपोरेट घरानों और पूंजीपतियों को देश के हवाई अड्डे को बेच रही है तो योगी आदित्यनाथ सरकार आजमगढ़ मंदुरी हवाई अड्डा बिस्तारीकरण के लिए पुलिस और प्रशासन के बल पर बलपूर्वक जनता का दमन करके, जमीन -मकान से आमजन को बेदखल करके भूमि अधिग्रहण क्यों कर रही है? आखिर हवाई अड्डा बिस्तारीकरण के नाम पर भूमि अधिग्रहण करने के पीछे सरकार का असली मकसद और मंशा क्या है? जनता की जमीन -मकान को लूट कर अडानी अम्बानी जैसे कारपोरेट घरानों को जमीन और हवाई अड्डा सरकार क्यों देना चाहतीं हैं? फासिस्ट मोदी और फासिस्ट योगी आदित्यनाथ सरकार कारपोरेट घरानों की दलाली और गुलामी क्यों कर रही है जिससे आमजन को कोई फायदा नहीं है।

उन्होंने आन्दोलनरत जनता, मजदूरों, किसानो की मांगों को पूरा करने और कॉरपोरेट घरानों के विकास के नाम पर विनाशकारी आजमगढ़ मंदुरी हवाई अड्डा बिस्तारीकरण की कार्यवाही पर फौरन रोक लगाने की मांग की है।साथ ही आंदोलन के नेता राजीव यादव और अन्य साथियों को पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किए जाने की तीव्र निंदा की है।

कॉमरेड कन्हैया
भाकपा (माले) रेड स्टार
उत्तर प्रदेश राज्य संगठन कमिटी

रिपोर्ट

ओडिसा

26 जनवरी को गंजाम,ओडिसा में कॉमरेड शंकर और कॉमरेड पार्वती के नेतृत्व में ओडिशा निर्माण श्रमिक यूनियन ने एसकेएम के आहवान पर प्रदर्शन किया

AIRWO

7,8 मार्च को बैंगलोर में आयोजित अखिल भारतीय क्रांतिकारी महिला संगठन (AIRWO) के पांचवे अखिल भारतीय सम्मेलन को सफल बनाएं
पितृसत्ता की पोषक कॉरपोरेट फासिस्ट शिकंजे को तोड़ दें

साथियों,
भारत एक ऐसा देश है जहाँ पितृसता/ मर्दवाद अपने सबसे बुरे रूपों में मौजूद है। मनुस्मृति जो कि मनुवादी - हिंदुत्व की पवित्र पुस्तक है, के अनुसार महिलाएं मानव का दर्जा पाने लायक नहीं हैं और इसलिए दलितों की तरह बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित हैं। केवल हिंदू धर्म ही नहीं, सभी पितृसत्तात्मक धर्म किसी न किसी रूप में महिला विरोधी हैं। इसलिए लैंगिक समानता और महिलाओं की मुक्ति के लिए सभी प्रकार के लैंगिक भेदभाव सहित पितृसत्ता / पुरुष प्रभुत्व का उन्मूलन करना जरूरी है।

आज जहां कॉरपोरेट
भगवा फासीवाद जिसका वैचारिक आधार मनुवादी हिंदुत्व है, समाज के समूचे बड़े और छोटे क्षेत्रों को नियंत्रित कर रहा है, वहीं महिलाएं सबसे ज्यादा भेदभाव और कई तरह से उत्पीडन का शिकार हैं। फासिस्ट और घोर महिला विरोधी आरएसएस के तथाकथित हिंदुराष्ट्र (जो कि अंबानी अदानी जैसे कॉरपोरेट थैलीशाहों का होगा) में महिलाओं की हालत कैसी होगी यह हम हिंदुराष्ट्र की हालिया प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं जहां आम गरीब मेहनतकश उत्पीड़ित वर्ग की महिलाएं हाथरस,उन्नाव,बहराइच,गोहरी इलाहाबाद और देहरादून में सिसक सिसक कर न्याय की आस में दम तोड देती हैं तो दूसरी ओर राम रहीम,आशाराम से लेकर सारे के सारे बलात्कारी,हत्यारे ढोंगी बाबाओं की जमात के साथ भाजपा समेत पूरा संघ परिवार मजबूती से खड़ा है।हालत यह है कि महिला खिलाड़ियों के साथ यौन दुर्व्यवहार का आरोपी भाजपा का बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण जो की भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष है के खिलाफ कारवाई की मांग को लेकर ओलंपिक और एशियाई खेलों में पदक विजेता महिला और पुरुष पहलवानों को लड़ना पड़ रहा है लेकिन भाजपा टस से मस नहीं हो रही है और बलात्कार व महिला उत्पीड़न के अपराधियों पर कोई कारवाई न करने के अपने रिकॉर्ड पर कायम है।।इसलिए महिलाओं की समानता के लिए संघर्ष आरएसएस फासीवाद का प्रतिरोध करने और उसे शिकस्त देने के तात्कालिक कार्य से जुड़ा हुआ है। साथ ही, सामंती और पूंजीवादी सामाजिक संबंधों और शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था के हिस्से में निहित लैंगिक प्रश्न को हल करना और महिला मुक्ति के संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन के लिए दीर्घकालिक संघर्ष से जोड़ना भी जरूरी है।

देश में महिलाओं का बड़ा हिस्सा अवैतनिक पारिवारिक श्रम तक ही सीमित है, यहां तक कि वे जो सामाजिक उत्पादन में भाग लेते हैं उन्हें भी कम भुगतान किया जाता है ।और कार्यस्थल पर यौन शोषण सहित सभी प्रकार के भेदभाव और हमलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कार्यस्थल सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं की समानता के लिए संघर्ष करना जनवादी और प्रगतिशील महिलाओं का परम कर्तव्य है। भारत जैसे देश में समान काम के लिए समान वेतन के संघर्ष के साथ-साथ महिलाओं के लिए संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित करने का संघर्ष भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, महिला विशिष्ट और लैंगिक अनुकूल कामकाजी परिस्थितियों के लिए लड़ाई भी जनवादी

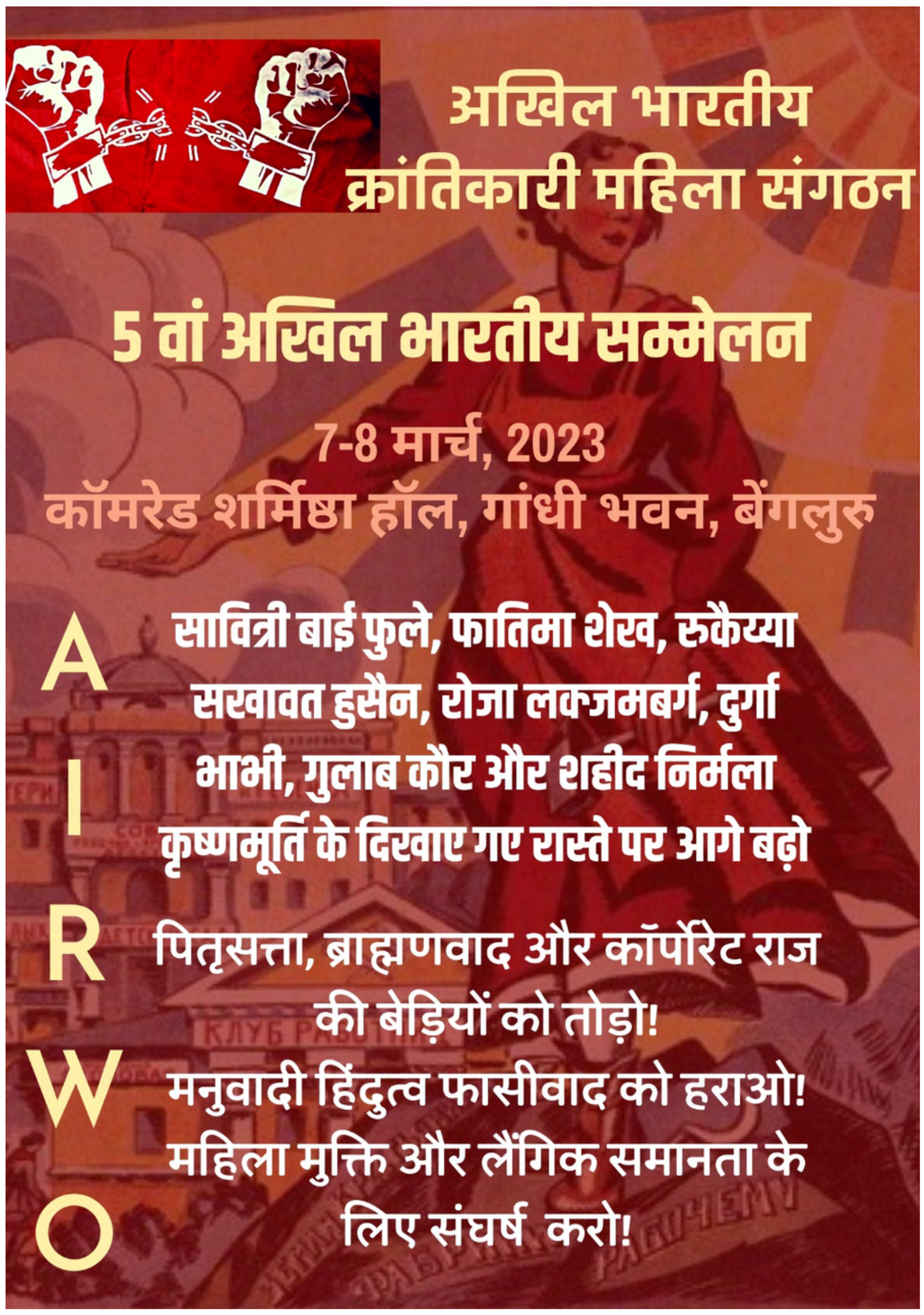

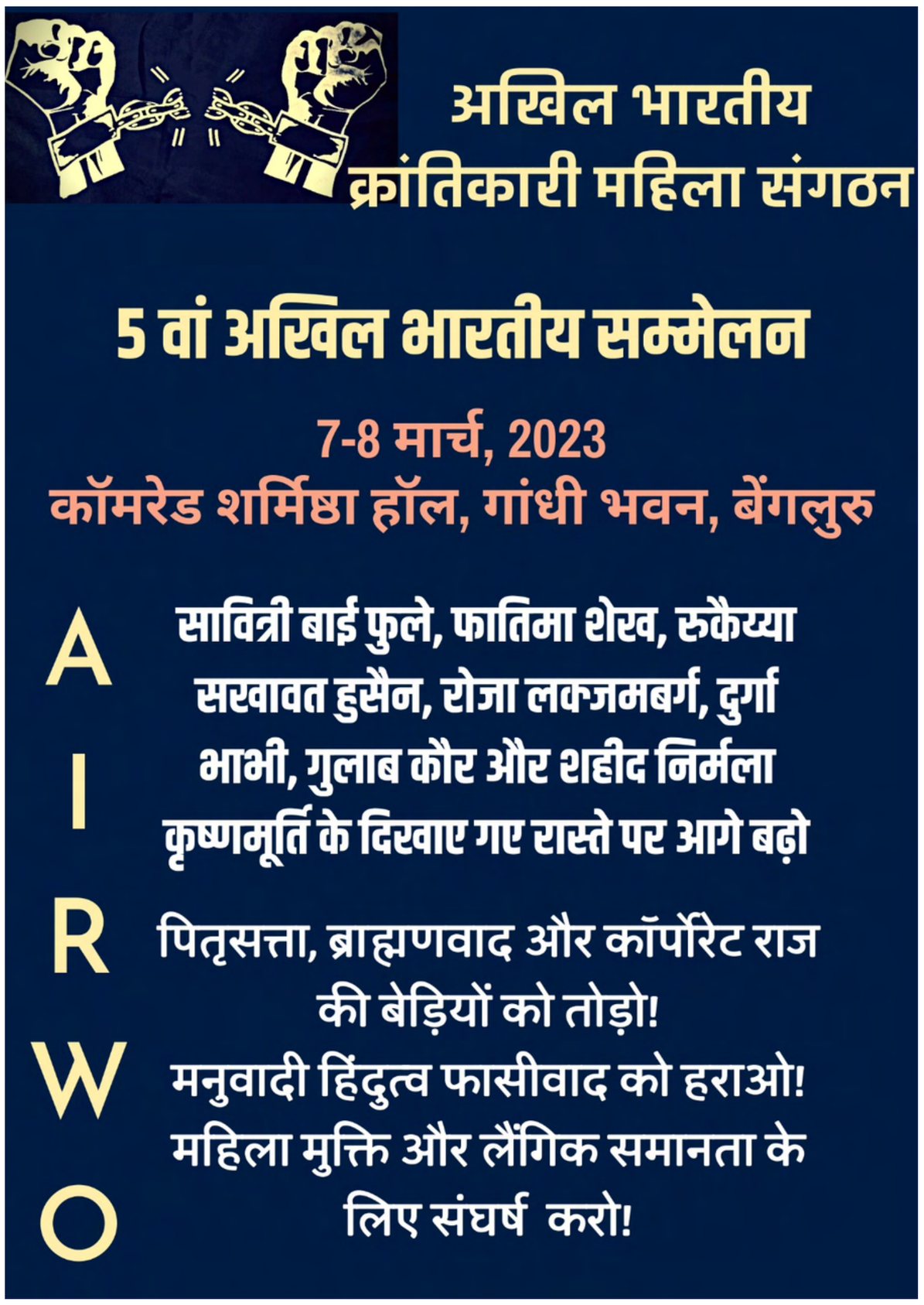

और प्रगतिशील महिलाओं द्वारा उठाया जाने वाला अत्यावश्यक कार्य है। यह इस संदर्भ में है कि AIRWO (अखिल भारतीय क्रांतिकारी महिला संगठन) जो एक लैंगिक समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए लड़ाई में जुटा हुआ है और जिसमे महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान संपत्ति और कमाई सहित तमाम जनवादी अधिकार प्राप्त होते हैं का पांचवा अखिल भारतीय सम्मेलन " गांधी भवन, बेंगलुरु ,कर्नाटक" में आगामी 7 और 8 मार्च को आयोजित है। यह सम्मेलन उपरोक्त मुद्दों के साथ-साथ भारत में पितृसत्ता की पोषक, कॉरपोरेट घरानों की दलाल और भारतीय जनता के दुश्मन संघी मनुवादी फासिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ाई में क्रांतिकारी महिला आंदोलन को तेज और मुकम्मल बनाने का संकल्प लेगा ।साथ ही इस कार्य को ध्यान में रखते हुए AIRWO को पूरी तरह से राजनैतिक वैचारिक रूप से लैस करेगा।

AIRWO, तमाम संघर्षशील,प्रगतिशील,मेहनतकश महिलाओं और आम जनता से पांचवे अखिल भारतीय सम्मेलन को तहे दिल से सफल बनाने की अपील करती है।
मनुस्मृति ,महिलाओं समेत तमाम उत्पीड़ित मेहनतकश जनता के लिए गुलामी का दस्तावेज है,मनुस्मृति के आधार पर हिंदुराष्ट्र बनाने नहीं देंगे, आरएसएस के वैचारिक आधार मनुवादी हिंदुत्व को उखाड़ फेंके
सावित्री बाई फुले,रुकैया शखावत हुसैन,दुर्गा भाभी,गुलाब कौर और शहीद निर्मला कृष्णमूर्ति के पथ पर अग्रसर हों
महिला मुक्ति,जनवाद और समाजवाद के लिए संघर्ष करें

क्रांतिकारी अभिनंदन सहित

प्रमिला, अध्यक्ष
अखिल भारतीय क्रांतिकारी महिला संगठन (AIRWO)
संपर्क-9437206230
पूर्णिमा, समन्वयक
संपर्क-9481920376

आईकोर

क्रांतिकारी संगठनों के अंतरराष्ट्रीय समन्वय(ICOR) में हमारे साथी संगठन MLKP (कुर्दिस्तान की मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी) के दो केंद्रीय कमिटी सदस्यों- कॉमरेड जैकी गुरबुज और युवा कॉमरेड उजगुर नामगोलू को सीरिया के रोजावा में टर्की की फासिस्ट एर्डोगन सरकार ने ड्रोन हमले में मार डाला। दोनों शहीद कॉमरेड को लाल सलाम।कॉमरेड जैकी,केंद्रीय कमिटी के दूसरे सदस्य हैं जो एर्डोगन सरकार के खुफिया एजेंसियों के हमले में शहीद हुए।इसके पहले भी फ्रांस की राजधानी पेरिस में पार्टी पर , टर्की सरकार ने हमला करवाया।यूरोप और सीरिया में कुर्द क्रांतिकारी कम्युनिस्टों के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं।लेकिन टर्की की फासिस्ट सरकार यह जान ले कि इस तरह वे MLKP को खत्म नहीं कर पाएंगे। रोजावा में कुर्द क्रांतिकारी कम्युनिस्टों जिनमें महिलाएं नेतृत्वकारी भूमिका में हैं ने अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा पैदा किए गए फासिस्ट आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट्स(ISIS) की कब्र खोदी है।तो ऐसे जांबाज कम्युनिस्टों द्वारा चलाई जा रही आजादी की लड़ाई को अमरीकी साम्राज्यवाद और उसके दलाल फासिस्ट एर्डोगन सरकार कैसे रोक पाएंगे।दुनिया भर से साम्राज्यवाद और उसके लठैत नव फासिस्टो का सफाया होगा,चाहे वो एर्डोगन हो या मोदी।जनता के जनवाद और विश्व समाजवादी क्रांति की विजय पताका को फहराने से कोई नहीं रोक सकता।इंकलाब ज़िंदाबाद

स्मरण

आदिवासी भारत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड भोजलाल नेताम का निधन

आदिवासी भारत महासभा (ए.बी.एम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) रेड स्टार के राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड भोजलाल नेताम का आज दिनांक 04 फरवरी 2023 को आकस्मिक निधन हो गया. 75 वर्षीय कॉमरेड नेताम ग्राम जिडार, मैनपुर, जिला गरियाबंद के निवासी थे. वे अपनी युवा अवस्था से ही कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे. वे भारत में साम्यवादी क्रांति के समर्थक थे और एक पूर्णकालिक पेशेवर क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना जीवन क्रांति के आदर्शों व सिद्धांतों पर चलते हुये बिताया.

पार्टी के राज्य कमेटी सचिव कॉमरेड सौरा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुये कहा कि कॉमरेड नेताम का आकस्मिक निधन पार्टी एवं उनके परिवार के लिये भारी क्षति है. उनके निधन से पूरे आदिवासी क्षेत्र में शोक व्याप्त है. वे बिन्द्रानवागढ़, गरियाबंद क्षेत्र में एक वरिष्ठ वामपंथी विचारक और नेता के तौर पर लोकप्रिय थे. वे वर्ष 2016 से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) रेड स्टार के सक्रिय राज्य कमेटी सदस्य थे. वे 2018 में बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा सीट से विधायक एवं 2019 में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार रहे.

कॉमरेड नेताम शुरुआती दौर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे. उन्होंने 1985 में तत्कालीन सोवियत रूस और

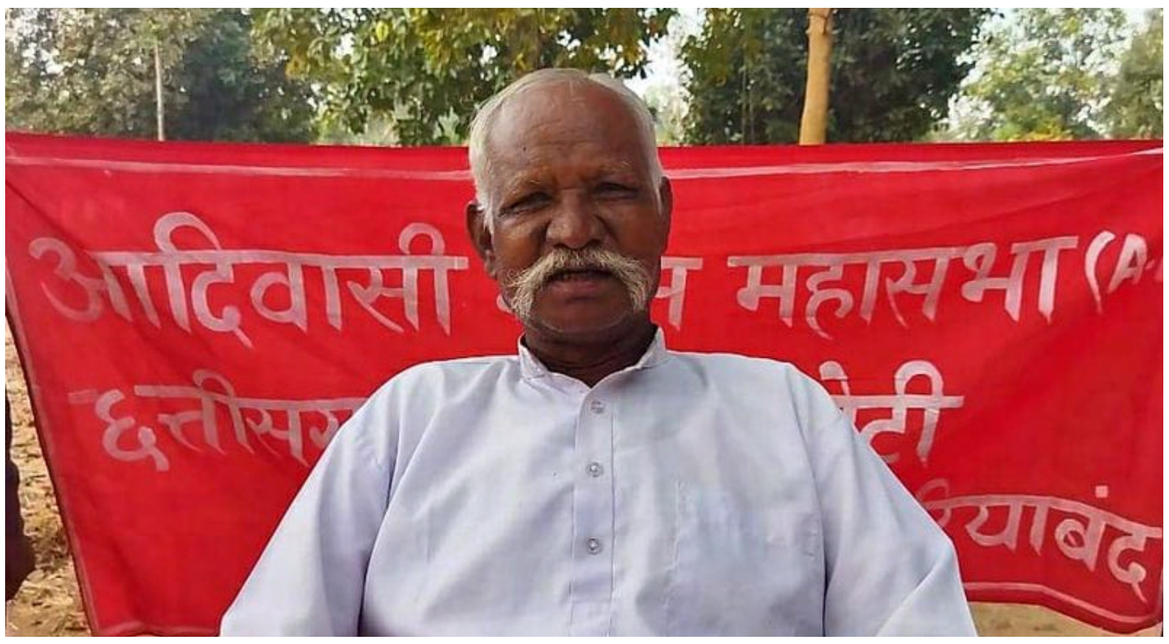

यूक्रेन का दौरा किया, रूसी नेताओं से मुलाकात की तथा उस दौर के राजनीतिक-सामाजिक हालातों को समझा. भारत आकर उन्होंने मजदूर, किसान, आदिवासियों के हित में कई महत्वपूर्ण संघर्षों व आंदोलनों का नेतृत्व किया. इस संबंध में उन्हें दर्जनों बार जेल भी जाना पड़ा लेकिन वे निरंतर संघर्ष को आगे बढ़ाते रहे. वर्तमान में आदिवासी भारत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जल-जंगल-जमीन, पेसा कानून, एवं आदिवासियों के अधिकारों और उनपर बढ़ते दमन के खिलाफ निरंतर अपनी आवाज बुलंद किया.

आदिवासी भारत महासभा (ए.बी.एम) एवं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) रेड स्टार कॉमरेड भोजलाल नेताम को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है.

कॉमरेड सौरा
राज्य सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य कमेटी
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) रेड स्टार

पेरू में, ग्रामीण इलाकों से हजारों प्रदर्शनकारी, लीमा की सड़कों पर सशस्त्र पुलिस से लड़ रहे हैं, दीना बोलुआर्टे द्वारा सत्ता पर कब्जा करने का विरोध कर रहे हैं, नए चुनाव की मांग कर रहे हैं। --------- फ्रांस में करोड़ों मेहनतकश लोग खत्म होते जन कल्याणकारी योजनाओं के दरमयान सड़कों पर उतर कर सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ------- ब्रिटेन में हजारों लोग सड़कों पर उतर कर रूढ़िवादी, श्रमिक-कर्मचारी विरोधी सरकार द्वारा हड़तालों को तोड़ने/ मेहनतकश लोगों के गठजोड़ को कमजोर करने के प्रयासों का विरोध कर रहे हैं।

रेड स्टार
फरवरी 2023